राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 338

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, रविवार, 17 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

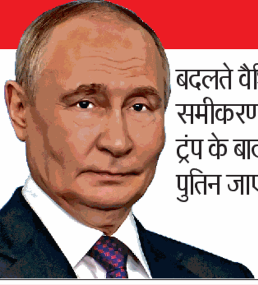

बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन

>> 11

रविवार विशेष

स्क्रीन में डूबा बचपन हो रहा बीमार

● पेज-7

संपादकीय

विदेशी मुद्रा बचाने की चुनौती: सरकारी तंत्र को यह समझना होगा कि जाम से

मुक्ति पाकर अरबों रुपये का ईंधन बचाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। **संजय गुप्त** का आलेख।

त्याग पथ पर चलते मंत्री महोदय: चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन क्षेत्र का त्याग ही पर्याप्त नहीं था, सो मंत्री जी ने काफिला भी त्याग दिया। **संतोष त्रिवेदी** का व्यंग्य।

● पेज-8

विमर्श

इतिहास लेखन बाधित करता स्लीपर सेल: भारतीय राजनीति में इतिहास पर निरंतर चर्चा होती रहती है। किसी अन्य दल पर दोषारोपण के लिए नेता अक्सर इतिहास से ही तथ्यों का सहारा लेते हैं। **अनंत विजय** का आलेख।

● पेज-9

सप्ताह का साक्षात्कार

दल क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, उन्हें हर 15 साल में नए नेतृत्व और सोच की जरूरत : डा. पलशीकर

हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी और भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है। इसको लेकर क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। शिक्षाविद् व जाने-माने राजनीति शास्त्री डा. सुहास पलशीकर का कहना है कि राजनीतिक दल क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, दोनों को ही हर 15 साल में नए नेतृत्व और सोच की जरूरत है। यदि उन्होंने खुद को नए सिरे से नहीं गढ़ा तो वह सिमटती चली जाएंगी। दैनिक जागरण की समाचार संपादक रुमनी घोष ने उनसे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के इतिहास, आचार-व्यवहार, जवाबदेही और बढ़ते-घटते दायरे पर विस्तार से बातचीत की।

● पेज-13

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज के मैच

पंजाब किंग्स vs रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु

दोपहर 3:30 बजे स्थान : धर्मशाला

दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रायल्स

शाम 7:30 बजे स्थान : दिल्ली

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

अब बिना मंजूरी नहीं हो सकेगा चांदी का आयात

नई दिल्ली : कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को बढ़ाकर छह से 15 प्रतिशत किए जाने के बाद अब सरकार ने चांदी आयात के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत चांदी आयात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यानी अब चांदी का आयात पूर्व मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगा। क अधिसूचना में बताया कि यह बदलाव 99.9 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता वाली चांदी के साथ सोने और प्लेटिनम के साथ इस्तेमाल होने वाली चांदी पर भी लागू होंगे। (पेज-10)

मोदी ने चेताया-स्थितियां नहीं बदलीं तो एक दशक की उपलब्धियों पर फिर जाएगा पानी

नीदरलैंड्स में भारतवंशियों के बीच प्रधानमंत्री ने मानवता के समक्ष कई बड़ी चुनौतियों को गिनाया

कहा- हालात नहीं बदले तो दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले ढाई महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष के समाप्त होने की संभावना कम होते देख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके भयावह परिणाम को लेकर दुनिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कोरोना और मौजूदा संघर्ष के संदर्भ में कहा कि अगर स्थिति नहीं बदली तो पिछले एक दशक में जो प्रगति हुई है, उस पर पानी फिर जाएगा और करोड़ों लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। मोदी ने यह बात नीदरलैंड्स के हेग में भारतवंशियों के एक समूह को संबोधित करते हुए कही। वह चार यूरोपीय देशों के दौरे के पहले चरण में शनिवार को सुबह वहां पहुंचे।

मोदी ने कहा- 'जब भारत सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हुए और अब आज का ऊर्जा संकट है। यह दशक आपदाओं का दशक बन रहा है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदलीं तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।'

मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में विश्व बैंक और आइएमएफ जैसी संस्थाओं ने कहा है कि यूक्रेन संकट और उसके बाद अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का विपरीत असर पूरी दुनिया पर होगा और विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा।

(संबंधित समाचार पेज 3 पर भी)

नीदरलैंड्स के हेग में शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

भारत की आकांक्षाएं अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं

पीएम ने कहा- 'भारत की आकांक्षाएं अब अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। भारत ओलिंपिक की मेजबानी करना चाहता है, वैश्विक विनिर्माण हब बनना चाहता है, ग्रीन एनर्जी लीडर और दुनिया का ग्रोथ इंजन बनना चाहता है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रिकार्ड गति से हाईवे निर्माण, रेलवे का अभूतपूर्व विद्युतीकरण किया गया है। सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कर रहा है। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, भारत उसे पाकर ही रहेगा।'

भारत की युवा पीढ़ी आसमान छूने को तैयार, देश बड़े सपने देख रहा

मोदी ने भारत-नीदरलैंड साझेदारी को नई दिशा देते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर विश्वसनीय, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति शृंखला बना रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में करीबी तौर पर काम कर रहे हैं। भारत-यूरोपीय संघ के बीच हाल में हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता इस साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा-'दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। भारत बड़े सपने देख रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम वाला देश है। प्रधानमंत्री ने इसका भी उल्लेख किया कि 16 मई का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन लोकसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले राजग को निर्णायक जनादेश मिला था। यह भारत के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था।

तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार रुपये देगी आंध्र सरकार

- आबादी कम होने से लोकसभा सीटें घटने की आशंका के बीच पहले दक्षिणी राज्य का फैसला
- राज्य की तेजी से घटती प्रजनन दर के बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है यह एलान
- इससे पहले दूसरे बच्चे के लिए भी 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की कर चुके हैं घोषणा

नरसन्नापेटा, प्रेट्र: आबादी कम होने के चलते लोकसभा में सीटें घटने की आशंका के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। यह कदम राज्य में तेजी से घटती प्रजनन दर को रोकने के प्रयासों के तहत उठाया गया है।

परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों को इस बात की आशंका है कि उत्तर भारत के मुकाबले उनकी आबादी कम होने के चलते लोकसभा में उनकी सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में इस तरह की पहल करने वाला आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का पहला राज्य है।

श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है और एक महीने के भीतर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'मैंने एक नया निर्णय लिया है। हम तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये देंगे। क्या यह सही निर्णय नहीं है।'

हालांकि, उन्होंने एक समय जनसंख्या नियंत्रण उपायों का समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आया गया है कि समाज जन्मदर बढ़ाने के लिए मिलकर काम करे। नायडू इससे पहले दूसरे बच्चे के जन्म पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। नायडू के अनुसार, कुछ दंपती दूसरी संतान तभी चाहते हैं, जब उनका पहला बच्चा लड़का न हो। उन्होंने आगाह किया कि इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। जनसंख्या तभी स्थिर रहती है, जब औसत प्रजनन दर 2.1 हो। इस बात पर भी जोर दिया कि कई देशों में घटती आबादी ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर डाला है।

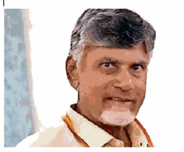

चंद्रबाबू नायडू। फाइल

पाकिस्तान तय करे, भूगोल में रहना चाहता है या इतिहास में: सेना प्रमुख

- जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले- आतंकवाद नहीं छोड़ा तो नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान
- आपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा- भारत अब घर में घुसकर देता है आतंक का जवाब
- तेजी से बदल रहा है युद्ध का स्वरूप, सैनिक से टाप कमांडर तक को उसी अनुरूप ढलना होगा

नई दिल्ली, एएनआइ: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तो उसे तय करना होगा कि उसे भूगोल का हिस्सा बने रहना है या इतिहास बन जाना है।

'सेना संवाद' कार्यक्रम में आपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक नीति पर चल रहा है और पाकिस्तान को उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

जनरल द्विवेदी ने कहा, 'मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहा और भारत के खिलाफ गतिविधियां जारी रखीं, तो उसे तय करना होगा कि उसे दुनिया के नक्शे में रहना है या इतिहास में बदल जाना है।'

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर के जरिये साफ कर दिया कि अब आतंक का जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का संदेश दिया। सेना प्रमुख ने नई पीढ़ी की तकनीकी क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तेजी से तकनीक आधारित युद्ध प्रणाली की ओर बढ़ रही है और 2026-27 को 'नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी' का वर्ष माना जा रहा है।

सेना की इंटर्नशिप योजना के लिए आए एक लाख आवेदन : उन्होंने बताया कि सेना की इंटर्नशिप योजना के तहत 100 पदों के लिए एक लाख आवेदन प्राप्त हुए। सेना ने अपने वर्कशाप, श्रेणी-ए प्रतिष्ठानों और मुख्यालयों को युवाओं के लिए खोला है, ताकि नई पीढ़ी के सरल लेकिन प्रभावी तकनीकी समाधान युद्धक्षेत्र में सेना की ताकत बन सकें।

जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और तकनीक महज 18 महीनों में पुरानी पड़ जाती है। ऐसे में सैनिक से लेकर शीर्ष कमांडर तक हर स्तर पर बदलाव के अनुरूप खुद को ढालना जरूरी है।

उन्होंने 'पूरे राष्ट्र की भागीदारी' की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य के युद्ध केवल सेना नहीं, बल्कि पूरे देश की सामूहिक शक्ति से लड़े जाएंगे। भारत को तकनीक, रणनीति और राष्ट्रीय एकजुटता के बल पर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में शनिवार को सेना संवाद को संबोधित करते सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। प्रेट्र

सेना प्रमुख खोलना चाहते हैं 'आहिस्ता जिंदगी' कैफे

प्रेट्र के अनुसार, जनरल द्विवेदी ने युवाओं के साथ संवाद के दौरान अपने एक निजी सपने के बारे में भी बताया। कहा कि वह 'आहिस्ता जिंदगी' नाम से एक कैफे खोलना चाहते हैं। यह कैफे लोगों के लिए संवाद, विचार-विमर्श और आत्मिक सुकून का केंद्र बनेगा। यहां चाय-काफी के साथ लोगों को आपस में बातचीत करने, किताबें पढ़ने और मुफ्त परामर्श सुविधा मिलेगी। तेज रफ्तार जिंदगी में लोगों को ठहरने, सोचने और सुकून के कुछ पल बिताने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि यह कैफे भोपाल में खोला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों के पलायन को रोकने की दिशा में भी योगदान देना चाहते हैं।

नई पीढ़ी या यानी 'जेन-जी' हमसे 10 गुना बेहतर

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई पीढ़ी यानी 'जेन-जी' की सराहना करते हुए कहा कि आज के युवा उनकी पीढ़ी की तुलना में '10 गुना बेहतर' हैं। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी ज्यादा अनुकूलनशील, सामाजिक रूप से जागरूक, वैश्विक सोच वाली और तकनीक में दक्ष है। उनके अनुसार, युवा कई बार कठिन समस्याओं का बेहद सरल समाधान लेकर आते हैं, जो युद्धक्षेत्र में निर्णायक साबित हो सकते हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा, 'हमें हर बार टैंक के मुकाबले टैंक की जरूरत नहीं होती। अगर कोई युवा कठिन समस्या का आसान समाधान दे देता है, तो वही भविष्य की लड़ाई जीतने में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।'

नीट-यूजी पेपर लीक करने वाली दूसरी लेक्चरर भी गिरफ्तार, एनटीए के वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर

नीलू रंजन ● जागरण

- सीबीआइ अब कुलकर्णी और मंढारे को पेपर पहुंचाने वाले की पहचान में जुटी
- एनटीए में चंद शीर्ष अधिकारियों को ही होती हैं अंतिम प्रश्नपत्र की जानकारी

नई दिल्ली : नीट-यूजी पेपर लीक मामले में केमिस्ट्री का पेपर लीक करने वाले लेक्चरर पीवी कुलकर्णी के बाद सीबीआइ ने अब बायोलाजी का पेपर लीक करने वाली लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंढारे को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुणे के रहने वाले हैं। कुलकर्णी की तरह बोटनी (वनस्पति विज्ञान) की लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ ने भी पूर्व में गिरफ्तार आरोपित मनीषा बाघमारे के घर पर स्पेशल क्लास में छात्रों को बोटनी और जूलाजी दोनों के प्रश्नपत्र व उत्तर बताए थे, जो कि बाद में नीट परीक्षा में हूबहू आए। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ की जांच नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के शीर्ष अधिकारियों पर टिक गई है।

सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कुलकर्णी और मंढारे की गिरफ्तारी के बाद नीट का पेपर पुणे, नासिक, गुरुग्राम होते हुए जयपुर तक पहुंचने और बाद में वाट्सएप और टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने की सारी कड़ियां खुल गई हैं और उनमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सिर्फ इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कुलकर्णी और मंढारे को ये पेपर किसने दिए?

पीवी कुलकर्णी।

मनीषा मंढारे।

मनीषा बाघमारे। फाइल

पेपर लीक के मास्टरमाइंड व मनीषा को 10 दिन की सीबीआइ कस्टडी में भेजा

जागरण संवाददाता के अनुसार, राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय गुप्ता ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार केमिस्ट्री के लेक्चरर पीवी कुलकर्णी और सह-आरोपित मनीषा बाघमारे को 10 दिन की सीबीआइ कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता ने तर्क दिया कि कुलकर्णी पेपर लीक मामले का मुख्य साजिशकर्ता है और वह एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था।

कुलकर्णी और मंढारे के पास थे केमेस्ट्री और बायोलाजी के सारे प्रश्न पेज>>5

किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक के हवाले कर दी पत्नी-बेटी

अहमदाबाद : गुजरात के मोरबी में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार की महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर छह माह तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि केवल 2000 रुपये किराया नहीं चुका पाने पर पीड़िता के पति ने ही मकान मालिक के साथ सौदा कर पत्नी और बेटी का यौन शोषण होने दिया। पुलिस ने मामले में मकान मालिक और पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार मूल रूप से सुरेंद्रनगर का रहने वाला है और करीब छह माह पहले रोजगार की तलाश में मोरबी आया था। आर्थिक संकट के कारण चार माह का किराया बकाया हो गया। (पेज-6)

देश में पहली बार पकड़ी गई 'जिहादी ड्रग' कैप्टागन की खेप

- एनसीबी ने 182 करोड़ की 227.7 किलोग्राम कैप्टागन जब्त कर अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का किया भंडाफोड़
- अमित शाह बोले- मोदी सरकार की ड्रग्स के प्रति जीरो टालरेंस नीति का बड़ा उदाहरण

नई दिल्ली में बरामद कैप्टागन टैबलेट। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने देश में पहली बार 'जिहादी ड्रग' के नाम से चर्चित कैप्टागन की बड़ी खेप बरामद करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एजेंसी ने 'आपरेशन रेजपिल' के तहत 182 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 227.7 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट और पाउडर जब्त किया है। इस मामले में अवैध रूप से भारत में रह रहे एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कार्रवाई के लिए एनसीबी की सराहना करते हुए इसे मोदी सरकार की नशीले पदार्थों के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' नीति का सशक्त उदाहरण बताया।

एनसीबी को एक विदेशी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी से सूचना मिली थी कि भारत को ट्रांजिट प्वाइंट बनाकर पश्चिम एशियाई देशों में कैप्टागन की तस्करी करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है। सूचना के आधार पर एजेंसी ने दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक मकान की पहचान की। 11 मई 2026 को मकान की तलाशी के दौरान चपाती काटने की मशीन में छिपाकर रखी गई करीब 31.5 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट बरामद की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि इसे सऊदी अरब के जेद्दा भेजा जाना था। जांच में यह भी सामने आया कि मकान में रह रहा सीरियाई नागरिक 15 नवंबर 2024 को पर्यटक वीजा पर भारत आया था, लेकिन 12 जनवरी 2025 को वीजा समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से यहीं रह रहा था।

पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने 14 मई को गुजरात के मुंद्रा स्थित कंटेनर फैसिलिटेशन स्टेशन में एक कंटेनर से करीब 196.2 किलोग्राम कैप्टागन पाउडर बरामद किया। यह कंटेनर भेड़ की ऊन के नाम पर सीरिया से आयात किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, खेप को सऊदी अरब समेत अन्य पश्चिम एशियाई देशों में भेजने की तैयारी थी, जहां कैप्टागन का दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनेटाइलीन और एम्फेटामाइन जैसे प्रतिबंधित मादक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैफीन, मेथाम्फेटामाइन और अन्य सिंथेटिक स्टिमुलेंट भी मिलाए जाते हैं।

2025 में 1980 करोड़ की ड्रग्स जब्त पेज>>3

भोजशाला में अब वर्ष के 365 दिन हो सकेगी पूजा-अर्चना

एएसआइ का नया आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के बाद एएसआइ ने भी जारी किया नया आदेश, मस्जिद का नाम हटा, आदेश में कमाल मौला शब्द नहीं, राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला व पाठशाला का ही उल्लेख

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर शनिवार को नया प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया है। एएसआइ ने पहली बार जारी अपने आधिकारिक आदेश में इस स्थल को 'राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला' के रूप में संबोधित किया है। पूर्व में प्रयुक्त 'कमाल मौला मस्जिद' संबंधी उल्लेख इस आदेश में नहीं किया गया है। आदेश में एएसआइ ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि भोजशाला संस्कृत शिक्षा और शोध का ऐतिहासिक केंद्र रही है तथा यह देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर है।

एएसआइ के अपने आदेश में भोजशाला परिसर में पूजा-अर्चना और अध्ययन संबंधी गतिविधियों के लिए निर्बाध प्रवेश देने की बात कही गई है। इससे अब वर्ष के सभी 365 दिनों तक पूजा का मार्ग खुल गया है। इससे पहले सप्ताह में एक दिन मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा की अनुमति थी। परिसर संरक्षित स्मारक बना रहेगा। धार जिला प्रशासन से चर्चा कर एएसआइ आगे की व्यवस्था तय करेगा, ताकि स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण प्रभावित न हो।

मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला परिसर को हाई कोर्ट द्वारा मंदिर की मान्यता देने के अगले दिन शनिवार को वहां जुटे श्रद्धालु। प्रेट्र

आस्था का उल्लास, मंदिर की मान्यता पर भावुक दिखे श्रद्धालु

धार, नईदुनिया प्रतिनिधि : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानते हुए शुक्रवार को दिए महत्वपूर्ण फैसले के अगले दिन शनिवार सुबह से श्रद्धालुओं और भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालु परिसर में मां वाग्देवी की प्रतिमा के स्थान पर पहुंचकर श्रद्धा और भावुकता के साथ नमन करते दिखे। कई महिलाएं मां सरस्वती और भगवान हनुमान के चित्र लेकर पहुंची थीं, लेकिन एएसआइ के सुरक्षाकर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। श्रद्धालुओं ने परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। (पेज-7)

16 मई को आसमान साफ रहा और औसत तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार की तुलना में एक डिग्री अधिक है। सबसे अधिक गर्म रिज क्षेत्र रहा। शुक्रवार को रिज क्षेत्र का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस था।

आज का मौसम

रविवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान में वृद्धि हो सकती है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
17 मई	42.0	25.0
18 मई	43.0	26.0
नोएडा		
17 मई	42.0	28.0
18 मई	42.0	29.0
गुरुग्राम		
17 मई	42.0	25.0
18 मई	42.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

100 करोड़ की योजनाओं की सीएम आज करेंगी शिलान्यास

नई दिल्ली : द्वारका विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत क्षेत्र की कायापलट करने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ के मेगा बजट को मंजूरी दी है। इस राशि से द्वारका क्षेत्र की अनियोजित कालोनियों की सड़कों, पार्कों, बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों ने इन जमीनी प्रोजेक्ट्स की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करने जा रही हैं। (जासं)

श्रमिक हिंसा मामले में भ्रामक जानकारी पर दो पर केस

नोएडा : वेतन वृद्धि को लेकर 13 अप्रैल को हुए श्रमिक हिंसा मामले में पुलिस का दावा है कि इंटरनेट मीडिया पर अभी भी भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है। बिगुल दस्ता समेत कई पेज के माध्यम से आरोपितों की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के मीडिया सेल कर्मी ने साइबर क्राइम थाने में दो फेसबुक खाताधारकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। (जासं)

गाजियाबाद में पत्नी की हत्या कर 80 वर्षीय पति पहुंचा थाने

गाजियाबाद : 80 वर्षीय पति ने चारपाई पर सो रही 72 वर्षीय पत्नी की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर बुजुर्ग मोदीनगर की रावली पुलिस चौकी पहुंचा और बोला मैं हत्यारा हूं.....मुझे जेल भेज दो।" पुलिस उसे हिरासत में लेकर मौके पर पहुंची तो पत्नी खून से लथपथ हालत में थी। (जासं)

मुख्यमंत्री ने दिए ईवी नीति के जल्द लागू होने के संकेत

डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी उपयोगिता

ईवी नीति दिल्ली वालों को उपलब्ध कराएगी सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर हो रही हैं। सीमित संसाधनों और कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण भविष्य में भी इन कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प बनकर उभरे हैं। बढ़ते प्रदूषण और डीजल-पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच राहत की एक नई किरण दिखाई दे रही है।

दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। पिछले महीने ही इस नीति का मसौदा (ड्राफ्ट) आम जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के लिए जारी किया गया था।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि इस नीति को बेहद व्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे

प्रतीकात्मक

शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पारंपरिक ईंधन की भारी किल्लत के बीच इस नीति की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति लागू होने से दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। यह नीति न केवल प्रदूषण के स्तर को कम करेगी, बल्कि आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को भी काफी हद तक हल्का करेगी।

दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है।

ईवी नीति से जनता को मिलने जा रहे हैं ये प्रमुख लाभ

- नए इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया) की खरीद पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी
- पूरी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, माल्स और आवासीय परिसरों में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।
- दो-पहिया, तिपहिया वाहनों पर चरणबद्ध प्रोत्साहन
- पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
- दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी व स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- स्कूल बसों में भी ईवी को बढ़ावा
- चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग ढांचे को मजबूती

दिल्ली सरकार में तैनात आइएएस भ्रष्टाचार के पुराने मामले में बर्खास्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में तैनात रहीं आइएएस पर एक पुराने मामले में गाज गिरी है। 2003 बैच की आइएएस पद्मा जायसवाल पर अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। वह कुछ माह पहले ही दिल्ली सरकार में आई थीं। वह दिल्ली सचिवालय स्थित प्रशासनिक सुधार विभाग में सचिव पद पर तैनात थीं और करीब एक माह से अवकाश पर थीं। उनसे पक्ष लेने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर फोन किया गया, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया।

गौरतलब है कि आठ माह पहले भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक यौन उत्पीड़न के मामले में लोक निर्माण विभाग में तैनात रहे आइएएस तालों पोतोम पर कार्रवाई हो चुकी है, सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। यौन उत्पीड़न के आरोप में वह अरुणाचल में गिरफ्तार हो गए थे। पद्मा जायसवाल पर सरकारी धन के गबन का आरोप है। यह पूरा मामला साल 2007-08 का है, जब वह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात थीं। आरोप है कि उन्होंने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक धन (जनता के लिए आए सरकारी राजस्व) का दुरुपयोग किया और गबन किया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि इन पैसों से कथित तौर पर उनके रिश्तेदारों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं।

दमकल विभाग में कर्मियों की भारी कमी, 6,600 पदों को जल्द भरे सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- वर्तमान में दिल्ली के 71 फायर स्टेशनों पर करीब 2,500 कर्मचारी कार्यरत, जरूरत 9,123 कर्मचारियों की

राजधानी में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं और आपातकालीन सेवाओं पर बढ़ते दबाव के बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग ने दिल्ली सरकार से प्राथमिकता के आधार पर 6,600 कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग की है। विभाग ने सरकार को भेजे प्रस्ताव में बताया है कि दमकल विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे अग्निशमन सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है।

विभाग के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली के 71 फायर स्टेशनों पर करीब 2,500 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि जरूरत 9,123 कर्मचारियों की है। इस हिसाब से विभाग में 72.5 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की कमी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था 24 घंटे की शिफ्ट प्रणाली पर आधारित है, जबकि स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल ने दमकलकर्मियों की थकान कम करने और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट लागू करने की सिफारिश की है।

विभाग ने बताया कि दिल्ली के लिए कुल 120 फायर स्टेशन स्वीकृत हैं, लेकिन अभी 49 फायर स्टेशन बनने बाकी हैं। इन सभी स्टेशनों के संचालन के लिए करीब 48 हजार फायर आपरेटरों की आवश्यकता होगी। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस संबंध में राज्य गृह

अग्निशमन मुख्यालय। फाइल

विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में दमकलकर्मी अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं। कई बार बड़ी आग लगने पर अलग-अलग स्टेशनों से कर्मचारियों को एक साथ बुलाना पड़ता है। ऐसे में जो कर्मचारी एक आपरेशन से लौटते हैं, उन्हें तुरंत दूसरी घटना के लिए रवाना कर दिया जाता है।

वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार दमकल विभाग के साथ मिलकर अगले 25 वर्षों के लिए फायरफाइटिंग मास्टर प्लान तैयार कर रही है। आने वाले वर्षों में कर्मचारियों, मशीनरी और अन्य जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और दमकल विभाग के आधुनिकीकरण में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

फर्जी दस्तावेज पर शेल कंपनियां खोल किया 128 करोड़ लेनदेन, छह गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- फर्जी जीएसटी बिल बनाकर सरकार से वसूला करीब दस करोड़ रुपये का आइटीसी
- 51.12 लाख नकद, 15 मोबाइल, दो कारें, लैपटाप, नकली मुहरें, जाली दस्तावेज बरामद

दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी दस्तावेज पर शेल कंपनियां खोलकर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मास्टर माइंड सहित छह को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान दरियागंज निवासी राजकुमार दीक्षित, शाहदरा निवासी नितिन वर्मा, जामा मस्जिद निवासी मोहम्मद. वसीम, चांदनी चौक निवासी आबिद मथुरा निवासी अमर कुमार और पन्ना निवासी विभाष कुमार मित्रा के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि गिरोह के सदस्यों ने फर्जी दस्तावेज पर 250 से अधिक शेल कंपनियां खोलकर 128 करोड़ का लेनदेन दिखाया है। इसके आधार पर सरकार से 10 करोड़ रुपये का आइटीसी वसूल लिया। गिरोह के सदस्यों से 51.12 लाख नकद, 15 मोबाइल, दो कारें, लैपटाप, मुहर, जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर रवि कुमार सिंह के मुताबिक जीएसटी विभाग को जांच में फर्जी दस्तावेज पर शेल कंपनियां खोलकर आइटीसी वसूले जाने की जानकारी मिली। जांच में टीम को पता चला कि दरियागंज निवासी नौवीं पास राजकुमार दीक्षित गिरोह का सरगना है, जो अपने भाइयों और अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज पर शेल कंपनियां खोलकर सरकार को चूना लगा रहा है। इसके लिए उसने दरियागंज में ही कार्यालय भी खोल रखा था, जहां छापा मारकर पुलिस ने उसे दबोच लिया। जांच में पता चला कि ये लोग आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक फर्जी शेल कंपनी बनाकर इसे पंजीकृत कराते थे। इसके बाद कागजों में ही उत्पाद खरीदे और बेचे जा रहे थे।

एलजी ने जल संचय अभियान का किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में पर्यावरण स्थिरता और जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए के जल संचय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के 101 पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, कायाकल्प और संरक्षण करना है।

पश्चिम विहार के डिस्ट्रिक्ट पार्क से हुई शुरुआत : शनिवार सुबह इस अभियान का शुभारंभ समारोह पश्चिम विहार स्थित डीडीए के डिस्ट्रिक्ट पार्क में किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक करनैल सिंह और डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान, डिस्ट्रिक्ट पार्क के भीतर स्थित लगभग 1.47 हेक्टेयर के जल निकाय को भी कायाकल्प कार्य के लिए शामिल किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान केवल एक सुंदरीकरण अभ्यास नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में एक केंद्रित प्रयास

जल संचय अभियान की शुरुआत पर भूमि को साफ करते उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू। जागरण

है। क्षेत्रीय विधायक करनैल सिंह ने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए जल निकायों को बचाना जरूरी है।

ठोस कार्ययोजना पर आधारित है यह अभियान : डीडीए ने इन जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत प्रथम चरण में मानसून से पहले किए जाने वाले कार्यों पर फोकस रहेगा। इसमें मुख्य रूप से ड्रेजिंग (कीचड़ निकालना), खोदाई, गाद हटाना और प्राकृतिक जलग्रहण चैनलों को साफ करना शामिल है ताकि मानसून के दौरान वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके। दूसरे चरण को पूरा करने का लक्ष्य मई 2027 रखा गया है। इस चरण में जल निकायों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में भाजपा सांसद चंदोलिया बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2020 के ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने कहा कि कोर्ट एक ही मामले में किए गए अपराधों को अलग-अलग कर नहीं देख सकता। मामला सात अक्टूबर 2020 का है। प्राथमिकी के अनुसार, करोल बाग के टैंक रोड इलाके में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल राज कुमार गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को क्रेन से हटवा रहे थे। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक स्कूटर हटाने को लेकर विवाद के बाद चंदोलिया ने रास्ता रोका, पुलिसकर्मी से बहस की और भीड़ को उकसाया।

एफआइआर में यह भी आरोप था कि जब हेड कांस्टेबल ने घटना की रिकार्डिंग करनी चाही, तो चंदोलिया ने क्रेन से नीचे खींचने और फोन छीनने की कोशिश की। बाद में फोन आरोपित के एक सहयोगी द्वारा ले लिया गया।

हमले में पुलिस को जल्द जांच पूरी करने और सुरक्षा देने का निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह एक महिला वकील पर उनके पति द्वारा किए गए जानलेवा हमले के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करे। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करे कि जांच निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से हो।

यह मामला कड़कड़डूमा जिला अदालत की एक महिला वकील से जुड़ा है, जिन पर 22 अप्रैल को सोनिया विहार में उनके पति मनोज कुमार ने तलवार से हमला किया था। एडवोकेट स्नेहा कलिता द्वारा सीजेआइ को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप व राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) योजना के तहत मुआवजे की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था।

बच्चों की कस्टडी मां को और मुफ्त शिक्षा का आदेश : सुनवाई के दौरान पीठ ने निर्देश दिया कि अब चूंकि पीड़िता

महिला वकील पर जानलेवा हमला

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पीड़िता तथा उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, इसलिए उनकी चार और एक साल की दोनों बेटियों की कस्टडी उन्हें सौंप दी जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दोनों बच्चियों को प्लेस्कूल और नियमित स्कूल सहित सभी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराए। स्कूल की फीस, यूनिफार्म, किताबें और परिवहन का पूरा खर्च दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग उठाएगा। साथ ही, दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार बच्चियों को वित्तीय सहायता या वजीफा भी दिया जाएगा। कोर्ट ने पीड़िता के इलाज और बच्चों की देखभाल के लिए 'नालसा' को तीन लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी करने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई में यह बात भी सामने आई कि गंभीर रूप से घायल पीड़िता को चार अस्पतालों में ले जाया गया था, जिनमें से तीन ने भर्ती करने से मना कर दिया।

एसी फटने से बैग बनाने वाली फैक्ट्री में आग, तीन फैक्ट्रियां भी आईं चपेट में

जागरण संवाददाता, नोएडा

- सेक्टर-63 डी ब्लाक की ईगल बिजनेस फैक्ट्री का मामला

एयर कंडीशनर (एसी) फटने से सेक्टर-63 डी ब्लाक स्थित बैग बनाने वाली फैक्ट्री के सेटबैक में आग लग गई। तब करीब 20 लोग फैक्ट्री में कार्य कर रहे थे। डीजल जेनरेटर सेट समेत कच्चा माल चपेट में आने से आग भड़कती गई। हवा चलने से पड़ोस की हैंडीक्राफ्ट व पीछे की दो बंद फैक्ट्रियों तक भी आग पहुंच गई। इससे तीनों फैक्ट्रियों में भी आग से नुकसान हुआ। अग्निशमन टीम ने नोएडा व गाजियाबाद से बुलाईं 16 गाड़ियों की मदद से करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि चारों फैक्ट्री में कोई हताहत नहीं हुआ। एसी फटने की वजह ओवर हीटिंग बताया जा रहा है। प्रबंधन आग लगने की वजह व नुकसान का आंकलन करने में जुटा है। बता दें कि बैग बनाने वाली कंपनी के परिसर में तीन बार पहले भी आग लग चुकी है।

नोएडा सेक्टर-63 डी ब्लाक में ईगल

सेक्टर 63 स्थित फैक्ट्री में लगी आग के बाद निकलता धुआं। जागरण

बिजनेस नाम की फैक्ट्री है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि शनिवार की दोपहर करीब दो बजे फैक्ट्री परिसर में आग लगने की सूचना मिली। टीम को चार गाड़ियों के साथ भेजा गया। आग परिसर के भूतल पर बने सेटबैक में लगी। कच्चा माल आदि ज्वलनशील सामान होने से आग विकराल होती गई। कर्मचारियों के आग बुझाने का प्रयास विफल रहा। विकराल हुई आग पड़ोसी शौर्य एक्सपोर्ट फैक्ट्री में भी पहुंच गई। इस पर अग्निशमन टीम ने गाजियाबाद से भी अग्निशमन वाहनों को बुलाकर आग बुझाना शुरू किया। दोनों फैक्ट्री में आग फैलने से रोकने का प्रयास किया गया। टीम बीए सेट पहनकर फैक्ट्री परिसर में घुसी। शीशे तोड़कर धुएं को निकाला। आग बुझाकर कूलिंग कराई।

पड़ोसी तीन फैक्ट्रियों में भी हुआ नुकसान : पड़ोस में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री चलाने वाले संजीव ने बताया कि पड़ोस की फैक्ट्री में शनिवार करीब दोपहर दो बजे एसी फटा था। आग भड़कने पर कर्मचारियों ने भी आग बुझाने में मदद की थी, पर हवा की दिशा उनकी फैक्ट्री की ओर होने से छत पर टिन शेड में रखे माल ने भी आग पकड़ ली। इससे उनका भी 15 लाख रुपये से ज्यादा का माल जल गया। साथ ही ईगल बिजनेस व पीछे की दो फैक्ट्री परिसर तक भी आग पहुंची। उन दोनों फैक्ट्री में भी नुकसान हुआ।

डीयू में पीजी दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू, सात जून तक करें आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- इस वर्ष पहली बार दस्तावेज और सीयूईटी-पीजी स्कोर डिजीलाकर व एपीआइ सेतु के माध्यम से स्वतः सत्यापित किए जाएंगे

डीयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दो वर्षीय स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु पंजीकरण प्रक्रिया शनिवार से शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी सात जून तक कामन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-पीजी) पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। दाखिला पूरी तरह से सीयूईटी के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

डीयू के अनुसार, इस वर्ष पहली बार अभ्यर्थियों के दस्तावेज और सीयूईटी-पीजी स्कोर को डिजीलाकर और एपीआइ सेतु के माध्यम से स्वतः सत्यापित किए जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक, वर्तमान में स्नातक पाठ्यक्रम के तीसरे या चौथे वर्ष में अध्ययनरत छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डीयू अब दो प्रकार के पीजी कार्यक्रम संचालित करेगा, एक वर्षीय और दो वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम। फिलहाल दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए

दिल्ली विश्वविद्यालय। फाइल

आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि एक वर्षीय मास्टर कार्यक्रमों के लिए अलग पोर्टल पर बाद में आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये प्रति कार्यक्रम तथा सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 250 रुपये प्रति कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

जनगणना

नजरी नक्शा बनाने के लिए शुरू हुआ मकानों का भौतिक सत्यापन, तेज गर्मी व उमस के बीच कर्मियों की परेशानी बढ़ा रही उलझाऊ मकान नंबर

मकानों की गणना को राजधानी की गलियों में उतरे बीएलओ

शशि ठाकुर ● जागरण

नई दिल्ली : लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह ठीक आठ बजे हाथों में कागजों की फाइल थामे बीएलओ सीमा पाठक और रवि कुमार अपने सुपरवाइजर व अन्य चार साथियों के साथ पहले दिन मकानों के भौतिक सत्यापन के लिए गलियों में पहुंचे। भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना टीम के सदस्यों ने आपस में बैठक कर वार्ड का विभाजन किया। इसके बाद दो-दो कर्मचारी अलग-अलग होकर संकरी और मुख्य गलियों में उतरे। उनके हाथों में मौजूद कागजों पर अंकित मकान नंबरों के आधार पर घर- घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ।

कर्मचारियों ने शांत की जिज्ञासा : सरकारी कर्मचारियों को सुबह- सुबह अपने दरवाजे पर देख स्थानीय निवासियों में भी उत्सुकता जाग गई। लोगों ने कौतूहल होकर पूछा कि क्या आप मकानों की गणना के लिए आए हैं? क्या आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी? इस पर बीएलओ सीमा पाठक ने बेहद शालीनता से लोगों की जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने बताया कि अभी हम व्यवस्थित कालोनियों में जाकर मकानों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं और नजरी नक्शा (रफ मैप) तैयार कर रहे हैं। यह शुरुआती काम दो दिनों तक चलेगा। इसके बाद मकानों की मैपिंग की जाएगी और निवासियों से 34 जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। लोगों से सटीक जवाब मिलने के बाद ही मकानों की गणना का यह कार्य संपन्न होगा।

लक्ष्मी नगर विधानसभा में मकानों का मैपिंग करते बीएलओ शिक्षक। जागरण

पूरी दिल्ली में उतरीं टीमें, एक कर्मी को मिला 50-55 इमारतों का जिम्मा

मकानों के भौतिक सत्यापन के पहले दिन केवल पूर्वी दिल्ली ही नहीं, बल्कि लुटियंस दिल्ली, करोल बाग और पुरानी दिल्ली समेत पूरी दिल्ली की गलियों में कर्मचारी घर- घर पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि महाभियान में केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड सहित विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। फील्ड प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए एक सुपरवाइजर की देखरेख में लगभग छह कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। पहले चरण के तहत एक कर्मचारी को औसतन 50 से 55 इमारतों के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लोग पूछते रहे सवाल

निरीक्षण के दौरान कई युवक आकर खुद ही पूछ रहे थे कि यह आप क्या कर रहे हैं। साथ ही गणना संबंधित आशंकाएं भी रख रहे थे। एक निवासी ने टीम से पूछा कि यह एसआइआर या मकानों की गणना।

डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर ने नहर में कूदकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, रोहतक : दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्मा राम सनातन धर्म कालेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जेलएलएन नहर में डूबने से मौत हो गई। पास में खड़ी स्कूटी के नंबर से शव की पहचान हुई। इसके बाद स्वजन को जानकारी दी गई। जांच में पता चला कि प्रोफेसर मानसिक रूप से परेशान थे और कई वर्षों से डिप्रेशन की दवा खा रहा था। इसी डिप्रेशन के चलते उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया।

मृतक की पहचान 32 वर्षीय भास्कर वशिष्ठ के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रह रहे थे। उसके पिता रूप किशोर ने बताया कि बेटा भास्कर वशिष्ठ स्कूटी लेकर शुक्रवार शाम ये कहकर निकला था कि वह रोहतक जा रहा है। शनिवार सुबह सूचना मिली कि बेटे की स्कूटी यहां खड़ी है और उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है।

सेंट स्टीफेंस कालेज की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जासं, नई दिल्ली : प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कालेज की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही डीयू रजिस्ट्रार ने चयन समिति पर सवाल उठाते हुए कालेज में नवनियुक्त प्राचार्य प्रो. सुसान एलियास की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और अब शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कालेज द्वारा की गई कई असिस्टेंट प्रोफेसरों की हालिया भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। विभिन्न विभागों में एड-हाक (तदर्थ) के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले शिक्षकों की याचिका पर राहत देते हुए हाई कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। साथ ही न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता छह एड-हाक असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाएं समाप्त करने पर रोक लगाई जाती है।

2023 से पहले शुरू हुई भर्ती के हजारों रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने पुरानी पेंशन देने के लिए उन कर्मचारियों की अंतिम सूची तुरंत तैयार करने को कहा है, जिनकी भर्ती का विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुआ था।

न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह 24 घंटे करना होगा काम : सूर्यकांत

जबलपुर में एक सेमिनार में सीजेआइ ने न्याय प्रक्रिया में तकनीकी एकीकरण पर दिया बल

न्याय प्रणाली में बिखरे हुए डिजिटल प्रयासों को एक मंच पर लाना समय की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर

देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट, पुलिस, जेल, फारेंसिक और मेडिको-लीगल सिस्टम का एकीकृत होना न्याय प्रक्रिया को मजबूत करेगा। जैसे छोटी नदियां मिलकर अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा का विशाल स्वरूप बनाती हैं, वैसे ही तकनीकी एकीकरण से न्याय प्रक्रिया में मजबूती आएगी। इसी तरह, अस्पतालों की भांति न्यायपालिका को भी 24 घंटे-सातों दिन की तर्ज पर कार्य करना होगा। न्याय प्रणाली में बिखरे हुए डिजिटल प्रयासों को एक मंच पर लाना समय की मांग है। वास्तव में डिजिटल तकनीक का उद्देश्य महज कागजों को कम करना नहीं, बल्कि देश के अंतिम छोर पर बैठे आम नागरिक तक त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय पहुंचाना है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म से मामलों के निपटारे में अभूतपूर्व तेजी आएगी।

सीजेआइ सूर्यकांत। फाइल

सीजेआइ शनिवार को जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तत्वावधान में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनः एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफार्म इंटीग्रेशन विषयक पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सीजेआइ ने कहा कि कोरोना के जटिल दौर में जब दुनिया भर की न्यायपालिका का कामकाज ठप था, तब भी भारतीय न्यायपालिका आधुनिक तकनीक का सदुपयोग कर वर्चुअल सुनवाई कर रही थी।

सीजेआइ सूर्यकांत ने कहा, युवाओं की नहीं, मैंने फर्जी डिग्री वालों की आलोचना की

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत ने शनिवार को एक बयान जारी कर अपनी 'परजीवी' और 'काकरोच की तरह होते हैं कुछ बेरोजगार युवा' वाली टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग द्वारा उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया है। सीजेआइ ने स्पष्ट किया कि उनकी यह आलोचना देश के युवाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री के सहारे विभिन्न पेशों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ थी।

सीजेआइ ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने उन लोगों की आलोचना की थी, जो वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन में फर्जी और बोगस डिग्री के सहारे घुस आए हैं। ऐसे ही लोग मीडिया, इंटरनेट मीडिया और अन्य पेशों में भी चुपके से घुस गए हैं और वे समाज के लिए 'परजीवी' की तरह हैं। उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो अपने पेशे में खुद को स्थापित करने में असफल होने के बाद आरटीआइ या इंटरनेट मीडिया एक्टिविस्ट बनकर संस्थाओं पर हमला करने लगते हैं। सीजेआइ ने उन व्याख्याओं को पूरी तरह से "आधारहीन" बताया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने देश के युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा, "मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है।" गौरतलब है कि यह पूरा विवाद शुक्रवार को तब शुरू हुआ जब वरिष्ठ वकील का दर्जा मांग रहे एक वकील की याचिका पर नाराजगी जताते हुए सीजेआइ ने कहा कि कुछ युवा काकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई जगह, उनमें से कुछ इंटरनेट मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआइ कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।

सीबीएसई में नौवीं से तीन भाषाएं अनिवार्य, दो भारतीय भाषाएं पढ़ना होगा जरूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एक जुलाई, 2026 से कक्षा नौ के विद्यार्थियों को तीन भाषाएं (आर1, आर2, आर3) होंगी पढ़नी
- कम से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होंगी, तीसरी भाषा को बोर्ड परीक्षा से छूट दी
- योग्य शिक्षकों की कमी होने पर कार्यात्मक ज्ञान वाले अन्य विषयों के शिक्षक पढ़ा सकेंगे

सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के तहत नौवीं और 10वीं कक्षा की भाषा अध्ययन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने कहा है कि एक जुलाई, 2026 से नौवीं में तीन भाषाओं (आर1, आर2, आर3) का अध्ययन अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यार्थी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो उसे तीसरी भाषा के रूप में तभी चुना जा सकेगा, जब बाकी दो भाषाएं भारतीय हों। अन्यथा विदेशी भाषा को अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ना होगा। यह व्यवस्था 2026-27 सत्र से लागू होगी।

बोर्ड के अनुसार, एनसीईआरटी द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम के अनुरूप यह बदलाव किया जा रहा है। सीबीएसई ने कहा कि नौवीं के विद्यार्थियों के लिए फिलहाल आर3 पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए 2026-27 संस्करण की छठी की आर3 किताबों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही स्कूलों को स्थानीय साहित्य, कहानियां, कविताएं और गैर-काल्पनिक सामग्री जोड़ने की अनुमति दी गई है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश 15 जून, 2026 तक जारी किए जाएंगे। अभी तक नौवीं में तीन भाषा नीति अनिवार्य नहीं थी।

सीबीएसई ने यह भी माना कि कई स्कूलों में भारतीय भाषाओं के योग्य शिक्षकों की कमी हो सकती है। ऐसे में अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अन्य विषयों के उन शिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेंगी, जिन्हें संबंधित भाषा का कार्यात्मक ज्ञान हो। सहोदय क्लस्टर के माध्यम से इंटर-स्कूल रिसोर्स शेयरिंग, वर्चुअल क्लास और सेवानिवृत्त भाषा शिक्षकों की मदद लेने का विकल्प भी दिया गया है।

आर3 भाषा का स्कूल स्तर पर मूल्यांकन : महत्वपूर्ण बात यह है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में आर3 भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा। हालांकि, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का उल्लेख सीबीएसई प्रमाणपत्र में होगा।

भाषाओं की श्रेणियां

- आर1 (पहली भाषा)- यह वह मुख्य भाषा होती है, जिसे स्कूल चुनता है। यह भाषा सीबीएसई की सूची में शामिल होती है, जैसे हिंदी या कोई क्षेत्रीय भाषा। आमतौर पर छात्रों की पढ़ाई की शुरुआत इसी भाषा से होती है।
- आर2 (दूसरी भाषा)- यह आर1 से अलग होती है। यह भी एक मानक भाषा होती है, जिसे स्कूल पढ़ाता है, जैसे अंग्रेजी या कोई दूसरी भारतीय भाषा।
- आर3 (तीसरी भाषा)- यह आर1 और आर2 दोनों से अलग होती है, इसमें छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं।
- इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए।

मोदी की नीदरलैंड्स के शाही परिवार से भेंट में प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग पर चर्चा

द हेग, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नीदरलैंड्स के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से रायल पैलेस में मुलाकात की और डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार, फिनटेक और ब्ल्यू इकोनमी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी शुक्रवार को यूएई में एक संक्षिप्त ठहराव के बाद नीदरलैंड्स पहुंचे, यह उनकी पांच-देशों की यात्रा का दूसरा चरण है जिसमें स्वीडन, नार्वे और इटली भी शामिल हैं।

मोदी ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया- रायल पैलेस में किंग विलेम-अलेक्जेंडर और उनकी महिमा रानी मैक्सिमा से मिले। प्रौद्योगिकी, नवाचार, सतत विकास, वाणिज्य और जल संसाधनों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-नीदरलैंड्स की मित्रता को बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करना अद्भुत था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा- 'दोनों पक्षों ने भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की।' भारत और नीदरलैंड्स ने हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश और जल, कृषि और स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को काफी बढ़ाया है।

- मोदी ने डच कंपनियों को भारत में डिजाइन, नवाचार और निर्माण के लिए आमंत्रित किया
- कहा- भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता

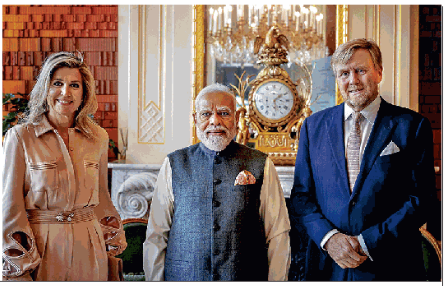

हेग स्थित रायल पैलेस में शनिवार को नीदरलैंड्स के राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएफपी

उन्होंने बताया कि यह साझेदारी रणनीतिक क्षेत्रों में भी विकसित हुई है जिसमें प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।

इसके अलावा मोदी ने हेग में आयोजित सीईओ गोलमेज सम्मेलन में डच कंपनियों को भारत में डिजाइन, नवाचार और निर्माण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि देश में विशाल अवसर उपलब्ध हैं।

उन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों और तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत स्थिरता का प्रतीक है और दुनिया में कोई भी देश इसके बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी की स्पीड से मेल नहीं खा सकता। इसी कारण भारत वैश्विक विकास में 17% का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देश भारत-नीदरलैंड्स की विश्वसनीय साझेदारी को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने जा रहे हैं।

नीदरलैंड्स ने चोल वंश के 11वीं सदी के ताम्र पत्र भारत को लौटाए

पीएम मोदी के इस दौरे पर नीदरलैंड्स ने भारत को एक खास तोहफा दिया। वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्र पत्र (तांबे की प्लेट्स) मोदी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में भारत को वापस सौंप दिए। मोदी ने इस अवसर को 'हर भारतीय के लिए एक आनंदमय क्षण' बताया। करीब 30 किलो वजनी ये ताम्र पत्र 21 बड़े और तीन छोटे प्लेटों का एक सेट है, जिनमें मुख्यतः संस्कृत और तमिल भाषाओं में शिलालेख अंकित हैं। यह 11वीं सदी में चोल राजाओं द्वारा जारी किए गए शाही चार्टर हैं। इन्हें 'लीडेन प्लेट्स' के नाम से भी जाना जाता है। मोदी ने कहा- 'ये चोलों की महानता को भी दर्शाते हैं। हम भारत में चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर गर्व महसूस करते हैं।' विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये केवल अतीत की कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि भारत की विरासत और सभ्यता की अनमोल कहानी हैं। इन ताम्र पत्रों की घर वापसी भारतीय लोगों के लिए एक गहरा भावनात्मक आकर्षण रखती है।

चोल वंश के ताम्र पत्रों के छल्ले पर लगी मुहर। प्रेट्र

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजेआइ की मौजूदगी जरूरी नहीं: केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि चयन समिति में न्यायपालिका के सदस्य को शामिल करना 'विधायी निर्णय' हो सकता है, लेकिन यह कोई 'संवैधानिक बाध्यता' नहीं है। केंद्र ने यह दलील मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दाखिल प्रति-हलफनामे में दी है।

2 जनवरी 2024 से लागू इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। नए कानून में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है।

- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा- चयन समिति में सीजेआइ को रखना संसद का फैसला, संवैधानिक बाध्यता नहीं
- सरकार बोली- 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित करता है

केंद्र ने हलफनामे में कहा कि संविधान में कहीं भी चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व का प्रविधान अनिवार्य नहीं किया गया है। यह कहना कि नियुक्तियों की वैधता के लिए न्यायपालिका की भागीदारी जरूरी है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद की भूमिका की गलत व्याख्या है। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग की वास्तविक स्वतंत्रता उसके संवैधानिक दर्जे, सुरक्षित कार्यकाल, हटाने संबंधी सुरक्षा उपायों तथा वेतन और कार्यों के वैधानिक संरक्षण से सुनिश्चित होती है। 2023 का कानून इन सभी प्रावधानों को बरकरार रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता जोड़ता है।

एसआइआर के पांच राज्यों में मतदान प्रतिशत के साथ मतदाता भी बढ़े

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बंगाल सहित पांच राज्यों में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) को विपक्ष भले ही मुद्दा बनाए हुए था, लेकिन हकीकत यह है कि एसआइआर के बाद इन राज्यों मतदाता और मतदान प्रतिशत दोनों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। 2021 यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बंगाल में इस बार जहां 34.23 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं असम में 2021 के मुकाबले 53.68 लाख अधिक मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी देखने को मिली है।

पांच राज्यों में 2021 की तुलना में मतदान प्रतिशत के साथ मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाता भी बढ़े है। गौरतलब है कि एसआइआर के बाद कराए गए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत भी बंगाल में 93.71, केरल में 79.53, तमिनलाडु में 86.03, पुडुचेरी में 91.19 व असम में 86.33 प्रतिशत मतदान हुआ है।

हर सैनिक की तरह मैं भी रिटायर हो जाऊंगा : सीडीएस जनरल चौहान

नई दिल्ली, प्रेट्र: चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि हर सैनिक की तरह वह भी जल्द सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन करीब आधी सदी की सैन्य सेवा से मिले अनुभव को भारतीय सशस्त्र बलों की नई पीढ़ी के अधिकारियों के साथ साझा करना चाहते हैं।

मानेकशा सेंटर में आयोजित 'सेना संवाद' कार्यक्रम में जनरल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के प्रशिक्षण काल को जोड़ दिया जाए तो वर्दी में उनकी यात्रा लगभग 49 वर्षों की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस लंबे अनुभव में उन्होंने सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को करीब से समझा है, जिसे वह भविष्य के सैन्य नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि नई पीढ़ी को बार-बार वही सब सीखने की जरूरत न पड़े।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों और सैन्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत में जनरल चौहान ने आपरेशन सिंदूर को भारत के पिछले सैन्य अभियानों से पूरी तरह अलग बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब भारत ने थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र समेत कई मोर्चों पर समन्वित तरीके से बहु-आयामी अभियान चलाया।

- करीब 49 वर्ष की सैन्य सेवा के अनुभव को नई पीढ़ी के अधिकारियों के साथ साझा करने की जताई इच्छा
- बोले- आपरेशन सिंदूर भारत के पिछले सैन्य अभियानों से पूरी तरह अलग और बहु-आयामी अभियान था

नई दिल्ली में सेना संवाद को संबोधित करते सीडीएस जनरल अनिल चौहान। प्रेट्र

सीडीएस ने कहा कि यह युद्ध पारंपरिक 'कांटैक्ट वारफेयर' से अलग था और इसमें नई तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल हुआ।

उन्होंने कहा कि आपरेशन सिंदूर में जीत के पैमाने भी अलग थे। पहले युद्धों में क्षेत्र पर कब्जा, दुश्मन के उपकरणों का विनाश और युद्धबंदियों की संख्या सफलता का पैमाना मानी जाती थी, लेकिन इस अभियान में सैकड़ों किलोमीटर दूर से सटीक हमले कर भारत ने अपनी तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया।

जनरल चौहान ने यह भी बताया कि उनकी अगली पुस्तक का विषय आपरेशन सिंदूर होगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करते हुए आपरेशन सिंदूर शुरू किया था।

2025 में 1980 करोड़ की ड्रग्स जब्त

प्रथम पृष्ठ से आगे

एनसीबी ने इसी महीने मुंबई से 349 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकीन जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब 1745 करोड़ रुपये आंकी गई थी। एक अन्य अभियान में एजेंसी ने 200 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन, गांजा और अन्य मादक पदार्थ भी बरामद किए थे।

एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2025 में चलाए गए 447 अभियानों में 1980 करोड़ रुपये मूल्य की 1.33 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। इन मामलों में 994 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 25 विदेशी नागरिक शामिल थे।

कैप्टागन को इसलिए कहा जाता है 'जिहादी ड्रग' : कैप्टागन एक सिंथेटिक उत्तेजक दवा है, जिसे 1960 में मानसिक विकारों और नार्कोलेप्सी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। बाद में इसकी लत लगाने वाली प्रवृत्ति और दुरुपयोग की आशंका के चलते इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया गया।

यह ड्रग लंबे समय तक जागे रहने, डर और थकान को दबाने, आक्रामकता बढ़ाने तथा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसी कारण पश्चिम एशिया के संघर्षग्रस्त इलाकों में लड़ाकों, चरमपंथियों और आतंकवादियों के बीच इसका व्यापक इस्तेमाल होने लगा। जिहादी हिंसा में शामिल आतंकियों के बीच प्रचलित होने के कारण इसे 'जिहादी ड्रग' कहा जाता है।

1980 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया, लेकिन गुप्त रूप से इसका अवैध कारोबार अब भी जारी है और इसे गोलियों के रूप में सप्लाई किया जाता है। कम उत्पादन लागत और अधिक मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में इसे 'गरीबों की कोकीन' भी कहा जाता है। भारत में इसकी खेप पकड़ा जाना चिंताजनक है। खासकर जब सरकार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान छेड़े हुए है। सरकार इस समस्या को समूल नष्ट करने की दिशा में भरसक कोशिश कर रही है।

व्यस्त और कामकाजी लोग कम समय में कर सकेंगे हजयात्रा

कोच्चि, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने शनिवार को भारतीय हजयात्रियों के इस वर्ष एक छोटा हज पैकेज शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सभी आवश्यक रस्मों को पूरा करते हुए हजयात्रा की अवधि को कम करना है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जार्ज कुरियन के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह पहल व्यापार और पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत व्यस्त लोगों के अनुरोध पर शुरू की गई है, जिन्हें 40 से 45 दिन काम से दूर रहना मुश्किल लगता है। नई व्यवस्था के तहत, हजयात्री लगभग 20 दिनों में हज की रस्में पूरी करके लौट सकेंगे। इस विशेष योजना के तहत लगभग 10 हजार हजयात्री यात्रा करेंगे।

हजयात्रा की पहली फ्लाइट 17 मई को कोच्चि से रवाना होगी और दूसरी फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से रवाना होने की योजना है। छोटा हज पैकेज 17 मई से पांच जून तक चलेगा।

यात्री सुरक्षा

एनएचएआइ के डाटालेक 3.0 से पहुंचेगा डाटा, टेलीकाम कंपनियां यात्रा कर रहे उपभोक्ताओं को देंगी अलर्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को सुरक्षित बनाने का है प्रयास, सफर के दौरान रीयल टाइम जानकारी देने की तैयारी

गूगल मैप व मैप माइ इंडिया पर नेशनल हाईवे के 'कैटल स्पाट' भी दिखेंगे

जितेंद्र शर्मा, जागरण

नई दिल्ली: कहीं रोड इंजीनियरिंग की खामियां, कहीं तेज रफ्तार तो कहीं वाहन चालकों की बेफिक्री...। कारण कई हैं, लेकिन परिणाम यही एक कि देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिनमें हर साल लगभग 1.80 लाख लोगों की जान चली जाती है। दुर्घटनाओं को कम करने के तमाम प्रयासों के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अब यात्री सुरक्षा के कुछ तकनीकी उपायों पर काम तेज किया है। इसके तहत लांच किए गए प्राधिकरण के पोर्टल डाटालेक का तीसरा संस्करण तैयार किया है, जिसमें न सिर्फ ब्लैक स्पाट, बल्कि कैटल स्पाट, ब्लाइंड कर्व सहित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के उन सभी स्थलों का डाटा है, जहां दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है। यह डाटा जल्द ही गूगल मैप और मैप माइ इंडिया पर दिखेगा। साथ ही यात्रा के दौरान मोबाइल मैसेज के माध्यम से यात्रियों को रीयल टाइम जानकारी भी प्राप्त होगी, ताकि वह पहले से सतर्क हो जाएं।

प्रतीकात्मक

देशभर में नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 80 हजार किमी है। एनएचएआइ सुरक्षा के लिए कुछ नए तरीके अपनाने जा रहा है। एनएचएआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण ने आवारा पशुओं की समस्या को भी अपने एजेंडे में शामिल किया है। पूरे हाईवे नेटवर्क पर सर्वे कराने पर 424 ऐसे स्थान हैं, जहां आवारा पशु अधिक बैठते हैं। इन्हें कैटल स्पाट के रूप में चिह्नित किया है। इसके साथ ही मैपिंग की गई है कि कहां-कहां ब्लैक स्पाट, डायवर्जन, ब्लाइंड कर्व सहित ऐसे बिंदु हैं, जहां हादसों की आशंका अधिक रहती है। दुर्घटना संभावित सभी स्थलों की जानकारी को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए डाटालेक का तीसरा संस्करण तैयार किया गया है। एनएचएआइ इसके लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) के साथ मिलकर काम कर रहा है। एनआइसी यह सारा डाटा एपीआइ सेतु पोर्टल के माध्यम से गूगल मैप और मैप माइ इंडिया तक पहुंचाएगा। इससे यात्रा के दौरान दुर्घटना बहुल स्थलों की जानकारी इन मैप साइट पर दिखेगी। एनएचएआइ ने जियो और एयरटेल से भी करार किया है। ये कंपनियां कैटल स्पाट और ब्लैक स्पाट की जानकारी इन स्थलों से डेढ़ किमी पहले ही यात्रियों को अलर्ट मैसेज भेज देंगी।

चुनौती हैं 1700 हिस्से, जहां नहीं है मोबाइल नेटवर्क

एनएचएआइ के चेयरमैन संतोष यादव ने इन तकनीकी प्रयासों के बीच नेटवर्क की समस्या का मुद्दा सरकार के सामने उठाते हुए सहयोग भी मांगा है। उन्होंने सरकार को जानकारी दे दी है कि नेशनल हाईवे पर 1700 हिस्से यानी स्ट्रेच ऐसे हैं, जहां कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता। इन स्ट्रेच की लंबाई 500 मीटर से लेकर आठ किलोमीटर तक भी है। इन हिस्सों में एनएचएआइ की कोई ऐसी तकनीक काम नहीं करेगी, जो मोबाइल नेटवर्क पर आधारित है। चेयरमैन ने सरकार से मांग की है कि नेटवर्क की समस्या का समाधान कराया जाए।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

15 हजार से भी अधिक मतों से सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में 2026 के विस चुनाव में हराया है। वह अपनी दूसरी सीट नंदीग्राम से भी 9665 मतों से जीते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार, 17 मई, 2026

तृणमूल के गढ़ में सुवेंदु की हुंकार- कहां है पुष्पा ?

दिखाए तेवर ▶ चुनाव के दौरान पुष्पा के किरदार से तुलना करने वाले तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान को दी चेतावनी

कहा- फलता में चुनाव समाप्त होने के बाद तथाकथित पुष्पा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी है

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सुवेंदु अधिकारी अपने पहले आधिकारिक जिला दौरे में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर पहुंचे। वहां प्रशासनिक बैठक की, उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम में डायमंड हार्बर लोकसभा अंतर्गत फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले जनसभा को संबोधित किया। मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने 29 अप्रैल को फलता में चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और ईवीएम से छेड़छाड़ तथा मतदाताओं को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद मतदान रद कर दिया था।

भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सुवेंदु ने खुद को पुष्पा बताकर चर्चा में आने वाले जहांगीर खान के बारे में फिल्मी अंदाज में पूछा कि कहां है? सुवेंदु का निशाना चुनाव में खुद को पुष्पा के किरदार से तुलना कर चर्चा में आने वाले तृणमूल प्रत्याशी व स्थानीय जहांगीर खान की ओर था। सुवेंदु ने जहांगीर खान का नाम लिए बिना उन्हें घोषित कुख्यात अपराधी बताते हुए चेतावनी दी कि चुनाव समाप्त होने के बाद तथाकथित पुष्पा की व्यवस्था करने की अब मेरी जिम्मेदारी है।

मालूम हो कि चुनाव के दौरान फलता से तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर ने खुद की तुलना फिल्म पुष्पा के किरदार से की थी। जहांगीर ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब उत्तर प्रदेश कैडर के चर्चित आइपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें चुनाव आयोग ने बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, की तुलना फिल्म सिंघम के पुलिस अधिकारी से की जा रही थी। एक प्रसारित वीडियो में अजय पाल शर्मा जहांगीर के परिवार को चेतावनी देते दिखाई दिए थे। वीडियो में अजयपाल कहते सुनाई दिए, अगर उसके लोग धमकी देना जारी रखेंगे तो हम ठीक से निपटेंगे... फिर रोना मत। इसके जवाब में जहांगीर ने कहा था कि यदि आप सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं। झुकेंगे नहीं।

दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में सुवेंदु अधिकारी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रेट्र

29 अप्रैल को फलता में वोटरों को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद मतदान रद कर दिया गया था

जहांगीर खान। फाइल

सुवेंदु का स्वागत करने पहुंचे टीएमसी विधायक

सुवेंदु के इस दौरे की सबसे बड़ी राजनीतिक सनसनी देखने को मिली। डायमंड हार्बर से तृणमूल के दो बार के मौजूदा विधायक पन्नालाल हलदर प्रशासनिक बैठक स्थल के बाहर गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री का इंतजार करते दिखे।

तोड़फोड़ करने वालों से ही की जाएगी नुकसान की भरपाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पर हमले की कोई भी घटना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों से ही नुकसान की वसूली की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस निष्क्रिय रही, तो वे खुद थाने में बैठकर काम कराएंगे।

दीदी-भतीजे के हर पाप का हिसाब होकर रहेगा

सुवेंदु ने आरजी कर कांड से लेकर लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के जरिए हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता और उनके सांसद भतीजे अभिषेक पर तीखा हमला बोला। दो टूक लहजे में कहा कि वह इन दोनों ही मामलों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। दीदी-भतीजे (ममता व अभिषेक) के हर पाप का हिसाब होकर रहेगा। कहा कि अब मेरे पास भतीजे की संपत्तियों की सूची है और जल्द ही मैं उनकी जांच शुरू कराऊंगा।

आरजी कर में महिला चिकित्सक के साथ हुए जघन्य कृत्य मामले में एक दिन पहले तीन आइपीएस अधिकारियों को निलंबित करने का जिक्र करते हुए सुवेंदु ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती ममता सरकार ने मुख्य आरोपितों को बचाने और सुबूतों को मिटाने की पुरजोर कोशिश की थी।

बंगाल में ट्रिपल इंजन की भूमिका निभा रहे भाजपा विधायक

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ नगरपालिकाओं में सीधे सफाई और नागरिक सेवाओं के लिए दे रहे निर्देश
▶ निकाय प्रमुख भी स्थानीय समीकरण देखते हुए भाजपा विधायकों के साथ बना रहे तालमेल

विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरपालिका स्तर पर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। तृणमूल के निकाय प्रमुखों या पार्षदों को भाजपा में शामिल कराए बिना ही भाजपा ने कई इलाकों में नगर सेवाओं पर प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, तृणमूल के जनप्रतिनिधि भी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा विधायकों के साथ समन्वय बनाकर चल रहे हैं।

कई नगरपालिकाओं में भाजपा के नव निर्वाचित विधायक सीधे पालिका प्रमुखों और पार्षदों से बैठक कर रहे हैं या फोन पर संपर्क साधकर सफाई, कूड़ा प्रबंधन और अन्य नागरिक सेवाओं को लेकर निर्देश दे रहे हैं। खास बात यह है कि अधिकांश मामलों में उन निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है।

बरानगर के भाजपा विधायक सजल घोष ने कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र के दो वार्डों में डस्टबिन से कूड़ा बाहर तक फैला देखा। इसके बाद उन्होंने संबंधित वार्डों के पार्षदों को तुरंत सफाई कराने का निर्देश दिया। दक्षिण दमदम नगरपालिका में चेयरपर्सन कस्तूरी चौधरी के साथ भाजपा के तीन विधायकों ने बैठक की।

सूत्रों के अनुसार चुनाव परिणाम आने के बाद कस्तूरी का नगरपालिका कार्यालय जाना लगभग बंद हो गया था।

सजल घोष। फाइल

भाजपा का दावा है कि विधायक तरुणज्योति तिवारी स्वयं उन्हें नगरपालिका कार्यालय लेकर गए, जिसके बाद बैठक हुई। फिलहाल चेयरपर्सन भाजपा विधायकों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही हैं।

बनगांव नगरपालिका में वहां के एकमात्र भाजपा पार्षद देवदास मंडल इस बार हाबड़ा से विधायक चुने गए हैं। देवदास हाल में नगरपालिका पहुंचे और निकाय प्रमुख से मुलाकात की। उन्होंने नागरिक सेवाओं को सुचारु रखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रशासनिक समस्या की जानकारी उन्हें दी जाए। आश्वासन दिया कि प्रशासन और सरकार के साथ संपर्क बनाकर शहर की सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की तैयारी में सुवेंदु सरकार

ओबीसी प्रमाणपत्र मामला

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

77 समुदायों के पांच लाख ओबीसी सर्टिफिकेट पर लटकी तलवार

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक बड़ा और नीतिगत फैसला लिया है। राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल किए गए 77 समुदायों के आरक्षण को बहाल करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने का निर्णय किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 मई 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में इन समुदायों के ओबीसी दर्जे को असंवैधानिक करार देते हुए रद कर दिया था, जिसके खिलाफ तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।

खबर है कि नई भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को औपचारिक पत्र भेजकर ममता सरकार द्वारा दो साल पहले दायर की गई इस याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से मामले पर

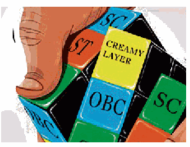

प्रतीकात्मक

त्वरित सुनवाई की अपील की है ताकि याचिका वापसी की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि बिना किसी उचित सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के, महज धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पर 75 मुस्लिम और दो हिंदू समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया था, जो संवैधानिक मानदंडों का खुला उल्लंघन है। भाजपा सरकार के इस कदम से 2010 के बाद जारी किए गए लगभग पांच लाख ओबीसी प्रमाण पत्र सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।

सब ही, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर विभाग ने वर्ष 2011 से अब तक जारी किए गए करीब 1.69 करोड़ एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों के व्यापक री-वेरिफिकेशन (पुनः सत्यापन) का आदेश दे दिया है। इनमें से लाखों प्रमाणपत्र तृणमूल के 'द्वारे सरकार' कैंपों के माध्यम से बांटे गए थे, जिन पर अब जालसाजी के आरोप लग रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के जाति प्रमाणपत्र भी रद कर दिए जाएंगे।

सुवेंदु अधिकारी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता: मिथुन

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

जाने-माने अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। सुवेंदु ने शनिवार को कोलकाता के न्यूटाउन स्थित मिथुन के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद सुवेंदु मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले जिला दौरे पर रवाना हुए, जिसकी शुरुआत उन्होंने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से की। सुवेंदु से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मिथुन ने कहा, बंगाल को सुवेंदु अधिकारी से बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता। मैं जनता को गारंटी इसकी देता हूं। वह सबसे अच्छे ही काम करेंगे।' मिथुन ने कहा कि और शपथ लेने के बाद पहले दिन से ही काम में जुट गए हैं।' मालूम हो कि हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में मिथुन ने भाजपा के लिए जमकर प्रचार किया था। मिथुन हाल में 'द बंगाल फाइल्स' में नजर आए थे, जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है।

'आरजी कर कांड में सीबीआइ अधिकारी ने सुबूत मिटाने में की मदद'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ भाजपा सांसद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा-सीमा पाहुजा को भी बनाया जाए आरोपित

आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या मामले की जांच को लेकर पूर्व मेदिनीपुर के तमलुक से भाजपा सांसद तथा कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शनिवार को सीबीआइ की जांच अधिकारी सीमा पाहुजा पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सीमा जांच को सही तरीके से आगे बढ़ाने में विफल रहीं और सुबूत मिटाने में भी मदद की।

हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का दावा-मामले में कई महत्वपूर्ण सुबूतों की हुई अनदेखी

अभिजीत गंगोपाध्याय

है कि जांच में जो भी लापरवाही हुई, वह सीमा पाहुजा के इशारे पर हुई। मांग की कि सीमा को भी मामले में आरोपित बनाकर जांच के दायरे में लाया जाए।

इस दिन दोपहर में अचानक आरजी कर पहुंचे अभिजीत चिकित्सकों का एप्रन पहनकर अस्पताल परिसर का दौरा करते दिखे। वह उस सेमिनार कक्ष के सामने भी पहुंचे, जहां अगस्त 2024 में महिला चिकित्सक का शव मिला था। वहीं खड़े होकर कहा कि कमरे से जांच के लिए महत्वपूर्ण सुबूत मिल सकते थे, लेकिन सीबीआइ ने उस दिशा में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। अभिजीत का आरोप

भाजपा सांसद ने अस्पताल की एक सीढ़ी का भी जिक्र किया। दावा है कि घटना के समय उस सीढ़ी से कोई भारी वस्तु, संभवतः शव नीचे ले जाया गया था। लेकिन सीबीआइ ने उस हिस्से को जांच के दायरे में नहीं लिया। उन्होंने सीमा को 'दायित्वहीन' करार देते हुए कहा कि जांच में कई अहम पहलुओं की अनदेखी की गई।

सीमा ने नर्स को वीडियो मिटाने के लिए कहा था : अभिजीत ने एक वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसे घटना के बाद एक नर्स ने रिकार्ड किया था। वह वीडियो सीमा ने अपने कब्जे में लिया और बाद में नर्स को उसे मिटाने के लिए कहा। भाजपा सांसद का आरोप है कि उस वीडियो को जांच में महत्व नहीं दिया गया और न ही अदालत में उसके अस्तित्व का उल्लेख किया गया। मालूम हो कि पहले मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी।

वहीं, आरजी कर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए नई डिवीजन बेंच का गठन किया है। अब इस पूरे मामले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की पीठ सुनवाई करेगी।

ईडी की कार्रवाई के बाद कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर की सेवाएं समाप्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ ममता सरकार ने शांतनु सिन्हा बिस्वास को दिया था दो साल का सेवा विस्तार

बंगाल सरकार ने ईडी की कार्रवाई के बाद कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ईडी ने बीते दिनों उन्हें गिरफ्तार किया था। शांतनु उन अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें पिछली ममता सरकार ने दो साल का सेवा विस्तार दिया था।

सेवा विस्तार पाने वाले अन्य अधिकारियों के विपरीत, शांतनु को इस्तीफा देने का अवसर नहीं दिया गया। सरकार ने सीधे तौर पर उनका सेवा विस्तार समाप्त कर दिया। बीते दिनों ईडी ने मनी लांड्रिंग और जमीन से जुड़े सिंडिकेट के कुछ मामलों के संबंध में कार्रवाई की, जिसमें एक कुख्यात और फिलहाल फरार हिस्ट्री-शीटर बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू भी शामिल है। पुलिस के 12 अन्य पुलिसकर्मी, जो शांतनु के सेवाकाल के दौरान उनके करीबी विश्वासपात्र थे, अब ईडी की जांच के दायरे में हैं।

आरोप है कि सोना पप्पू, गिरफ्तार

शांतनु सिन्हा बिस्वास

रियल एस्टेट कारोबारी जय कामदार और शांतनु के नेतृत्व वाले कुछ पुलिसकर्मियों का यह गठजोड़ कोलकाता और आसपास के इलाकों में विवादित जमीनों और संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर कब्जाने का काम करता था।

यह गिरोह असली जमीन मालिकों पर दबाव बनाने के लिए अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ फर्जी एफआइआर दर्ज करवाता था ताकि वे अपनी जमीन या संपत्ति बहुत कम कीमत पर इस सिंडिकेट को बेचने पर मजबूर हो जाएं।

ममता बनर्जी द्वारा गठित 'पुलिस वेलफेयर बोर्ड' भंग, सरकार का वसूली पर कड़ा प्रहार

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

▶ मुख्यमंत्री की पुलिस अफसरों को चेतावनी- अब शासक का नहीं, संविधान का चलेगा कानून

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को लेकर शनिवार को कड़े तेवर दिखाए हैं। अपने पहले जिला दौरे के दौरान डायमंड हार्बर में पुलिस अधिकारियों के साथ एक प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा गठित 'पुलिस वेलफेयर बोर्ड' को तत्काल प्रभाव से भंग करने का बड़ा एलान किया। सोमवार को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस बोर्ड का गठन पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए हुआ था, वह अंततः तृणमूल कांग्रेस के एक राजनीतिक विंग में तब्दील हो गया था, जिसका फायदा केवल शांतनु सिन्हा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों ने उठाया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य में 'शासक का कानून नहीं, बल्कि

ममता बनर्जी। फाइल

कानून का शासन' स्थापित होगा। उन्होंने पुलिस महकमे को निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए लोगों, थानों में प्रताड़ित महिलाओं और सरकारी योजनाओं के नाम पर 'कटमनी' देने वाले नागरिकों से सीधे पुलिस में एफआइआर दर्ज कराने की अपील की है।

अवैध मदरसों के खिलाफ होगी कार्रवाई: खुदीराम

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का मन बना लिया है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टुडू ने शनिवार को बांकुड़ा जिले के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में एक भी अवैध मदरसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि बंगाल की वर्तमान डबल इंजन सरकार अब उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह ही जीरो-टालरेंस की नीति पर काम करेगी।

उन्होंने कहा कि हम राज्य के सभी अवैध मदरसों को बंद करेंगे और इस नेटवर्क में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। भविष्य में भी ऐसी अवैध संस्थाएं सिर न उठा सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहेगा।

मैं घोर सनातनी हूं: दिग्विजय सिंह

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

▶ भाजपा विधायक से कहा - पहले आप लोग हिंदू-हिंदू करते थे
▶ उषा ठाकुर से इंदौर में धर्म पर चर्चा के दौरान दिया बयान

'मैं घोषणा करता आया हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मैं घोर सनातनी हूं।' पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में न सिर्फ यह बात कही, बल्कि महू से भाजपा विधायक उषा ठाकुर से यह भी कहा कि पहले आप लोग हिंदू-हिंदू करते थे, लेकिन मेरे कहने के बाद से आपने सनातनी होने की बात स्वीकार की। बता दें कि दिग्विजय सिंह सनातन विरोधी बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं।

असल में, दिग्विजय सिंह और भाजपा विधायक उषा ठाकुर इंदौर में शनिवार को एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले तो धर्म पर चर्चा छिड़ गई। उनके बीच के संवाद का वीडियो बहुप्रसारित हो गया। औपचारिक मुलाकात के दौरान उषा ठाकुर ने उनसे कहा कि भोजशाला पर फैसले का आपको सम्मान करना चाहिए तो दिग्विजय ने कहा- तुमने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया?

दिग्विजय का स्वागत करते हुए उषा ठाकुर ने उन्हें बड़े भाई कहकर पुकारा। उषा ने उनसे कहा कि हम अनादि काल

इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भाजपा विधायक उषा ठाकुर। वीडियो ग्रैब

से सनातनी हैं। तो दिग्विजय बोले- अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, हम क्या दुश्मन हैं उसके? उषा ठाकुर ने जवाब में कहा- आप व्यक्तिगत रूप से तो पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा- मैं सार्वजनिक रूप से फिर कह रहा हूं, अब और कैसे सार्वजनिक करूं कि मैं घोर सनातनी हूं।

सक्रियता

निगम-मंडलों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मांगने लगे मंत्रियों जैसा प्रोटोकाल और अन्य सुविधाएं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुख्यमंत्री व बड़े नेता भी करेंगे बातचीत, दी जाएगी नियमों की दी जानकारी

मप्र में मंत्रियों व निगम-मंडल के अध्यक्षों में समन्वय पर जोर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार मंत्रियों और निगम-मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सक्रिय हो गई है। हालिया राजनीतिक नियुक्तियों के बाद सोमवार 18 मई को निगम-मंडलों के नए अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव और भाजपा संगठन के बड़े नेता मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक विशेष सत्र को संबोधित कर नेताओं को मंत्रियों व विभागों के साथ मिलकर काम करने का पाठ पढ़ाएंगे। इस दौरान 18 विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके अधिकारों, वित्तीय सीमाओं और सरकारी कार्यप्रणाली की जानकारी देंगे। अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे अपने-अपने निगमों से जुड़े नीतिगत फैसले और काम विभागीय मंत्रियों की

डा. मोहन यादव। फाइल

अनुशंसा व समन्वय के साथ आगे बढ़ाएं।

सूत्रों के अनुसार, निगम-मंडलों में तैनात अध्यक्ष-उपाध्यक्षों ने मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के जैसा प्रोटोकाल और सुविधाओं की मांग करनी प्रारंभ कर दी है। दरअसल, निगम-मंडल के अध्यक्ष यह कहने लगे थे कि हम बिना चुने दर्जा मंत्री हैं, मंत्री और हममें इतना ही अंतर है। कई विभाग के मंत्रियों ने निगम के गाड़ियां अपने पास रखी हुई हैं। अध्यक्षों ने मंत्रियों से गाड़ियां वापस करने की मांग भी की है। कई अध्यक्षों ने नियुक्ति के तुरंत बाद मंत्रियों की तरह बड़ा स्टाफ, विशेष सुरक्षाकर्मी और आलीशान दफ्तर/बंगले की मांग शुरू कर दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने केवल नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम स्टाफ रखने की अनुमति दी है, लेकिन आगे किसी तरह मतभेद जैसी स्थिति न बने, इसके लिए भाजपा संगठन सक्रिय हुआ है। इसी कड़ी में सभी का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

दिया जाएगा संदेश- लक्ष्मण रेखा में रहकर ही काम करें : प्रशिक्षण के दौरान इन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि वे अपनी लक्ष्मण रेखा में रहकर ही काम करें। यह चेतावनी भी दी गई है कि कोई अध्यक्ष अपने विभाग के मंत्री को विश्वास में लिए बिना सीधे मीडिया में बयानबाजी करता है या फैसले लेता है, तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। समन्वय के लिए तैयार एजेंडे में कहा गया है कि समन्वय केवल एकतरफा नहीं है, मंत्रियों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे निगम-मंडल के अध्यक्षों को कमतर न आंकें।

विदेश में बसे भारतीयों के तमिलनाडु में वोट डालने के मामले में 10 गिरफ्तार

▶ चुनाव आयोग ने दिए फर्जी मतदान करने के आरोपों की जांच के आदेश

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विदेश में बसे भारतीयों द्वारा वोट देने का मामला सामने आया है। विदेश की नागरिकता ले चुके इन लोगों ने फर्जी पहचान पत्र या पहले बने हुए दस्तावेज का दुरुपयोग कर वोट डाला और वापस विदेश लौटने के लिए विमान में चढ़ने ही वाले थे, लेकिन अंगुली पर लगी अमिट स्याही के कारण पकड़े गए। पुलिस ने पूरे राज्य में इस तरह के नौ मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ये श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक हैं। वहीं एएनआइ के अनुसार इस मामले में 18 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है।

दरअसल 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद जब ये विदेश जाने के लिए हवाईअड्डे पहुंचे तो हवाईअड्डे के अधिकारियों को उनकी अंगुलियों पर अमिट स्याही देखकर संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद पुलिस ने चेन्नई और मदुरै हवाईअड्डों पर आरोपितों को गिरफ्तार किया। चुनाव आयोग ने विदेशियों द्वारा धोखाधड़ी से मतदान करने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिकता त्याग चुके लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अनिवासी भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20ए के तहत पंजीकरण करा सकते हैं और उन्हें मतदान केंद्र पर अपना मूल भारतीय पासपोर्ट पेश करना होता है।

हिमाचल में 51 शहरी निकायों के 439 पदों के लिए आज मतदान

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता के सेमीफाइनल के लिए मैदान सज गया है। चार नगर निगमों यानी धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन सहित 51 शहरी निकायों के 439 पदों के लिए रविवार को मतदान होगा। कुल 1147 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय 3.80 लाख मतदाता करेंगे। नगर निगमों में पार्टी चुनाव चिह्न और 51 शहरी निकायों के चुनाव में राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी कारण कांग्रेस और भाजपा ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।

इसी माह के अंत में पंचायतीराज की अन्य संस्थाओं के लिए भी मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक स्थानीय निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाने का आदेश दिया है।

590 करोड़ रुपये के हरियाणा में आइडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्माल फाइनेंस बैंक में घोटाले में तीन और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी जांच के घेरे में हैं। सरकार ने तीन और अफसरों से सवाल-जवाब करने की मंजूरी दे दी है।

नीट-यूजी की तैयारी कराने में छात्रों की मदद को उतरे शिक्षा मंत्रालय व एनटीए

विशेष व्यवस्था ▸ शिक्षा मंत्रालय ने साथी पोर्टल के जरिये शुरू किए क्रैश कोर्स

एनटीए ने अभ्यास एप पर छात्रों के लिए जारी की नई टेस्ट सीरीज

21 जून को अब दोबारा होनी है नीट-यूजी-2026 की परीक्षा

प्रतीकात्मक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी के पेपर को लीक होने से भले ही शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) नहीं बचा पायी है, लेकिन परीक्षा रद होने से अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्रों की दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारी कराने के लिए वह आगे आए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने जहां अपने साथी पोर्टल के जरिए दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए एक नया क्रैस कोर्स शुरू किया है, वहीं एनटीए भी अपने अभ्यास एप के जरिए इन छात्रों की मदद के लिए नई टेस्ट सीरीज जारी की है। यह दोनों ही सुविधा छात्रों को दोबारा परीक्षा होने तक जारी रहेगी।

मंत्रालय ने इस पोर्टल के जरिए करीब 35 दिनों का एक खास कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें छात्रों को नीट-यूजी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को तेजी से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आइआइटी व एनसीईआरटी से जुड़े विशेषज्ञों को भी इससे जोड़ा गया है। इसके साथ ही छात्रों के लिए टेस्ट सीरीज भी तैयार की गई है। यह कोर्स मुफ्त और प्रतिदिन आनलाइन होगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथी पोर्टल के जरिए शुरू किए गए क्रैश कोर्स की जानकारी को साझा किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि, मंत्रालय की इस पहल से पहले कई निजी कोचिंग संस्थान भी छात्रों की मदद के लिए आगे आए है, जिन्होंने छात्रों को नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए मुफ्त में पढ़ाने की पेशकश की है। इस क्रैस कोर्स में छात्रों को प्रतिदिन सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक क्लास लगेगी। साथ ही प्रतिदिन टेस्ट भी होगा,जबकि सप्ताह में माक टेस्ट भी लिया जाएगा। गौरतलब है कि नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को होगी।

एनटीए ने दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी बढ़ाई चौकसी : नीट-यूजी के पेपर लीक होने की घटना के बाद एनटीए ने मौजूदा समय में चल रही सीयूईटी-यूजी और जून में होने वाली यूजीसी-नेट परीक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी है।

साथ ही परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों व राज्यों को भी निर्देश दिया है कि वह परीक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरते। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी न होने पाए। गौरतलब है कि 2024 में नीट-यूजी व यूजीसी नेट के पेपर लीक होने की घटना के बाद सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व जिलों के कलेक्टर व एसपी को भी परीक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है।

दो संयुक्त सचिव और दो संयुक्त निदेशक तैनात किए गए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नीट-यूजी पेपर लीक के बाद सवालों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में केंद्र सरकार ने शनिवार को दो संयुक्त सचिव और दो संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों की तैनाती दी है। इनमें संयुक्त सचिव के पद पर भारतीय सांख्यिकी सेवा की 1998 बैच की अधिकारी अनुजा बापट व भारतीय राजस्व सेवा की 2004 बैच की अधिकारी रुचिता विज को तैनाती दी गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जारी किए गए आदेश में इसके साथ ही एनटीए में दो संयुक्त निदेशकों के पद पर भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी आकाश जैन व भारतीय लेखा व परीक्षक सेवा से अधिकारी आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया को तैनाती दी है। इन सभी को अगले पांच सालों के लिए एनटीए में तैनात किया गया है।

पेपर लीक पर राहुल-खरगे ने पीएम से कहा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें या बर्खास्त करें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ राहुल गांधी ने पेपर लीक को पैसे कमाने का जरिया बनाने का लगाया आरोप

▸ 'अमृत काल' भर्ती-परीक्षा छात्रों के लिए साबित हो रहा 'मृत काल' : खरगे

नई दिल्ली में शुक्रवार को वीडियो संदेश में बोलते राहुल गांधी। एएनआइ

पेपर लीक के चलते नीट परीक्षा रद होने के बाद छात्रों के बीच बढ़ती हताशा की घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जवाबदेही तय करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शिक्षण संस्थानों में सत्ता संरक्षित लोगों द्वारा गठजोड़ कर नीट पेपर लीक को पैसे कमाने का जरिया बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दो साल से रात दिन परिश्रम करने वाले 22 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फेरा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पेपर लीक माफिया सरकार के निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है और मोदी सरकार में "अमृत काल" भर्ती परीक्षा छात्रों के लिए "मृत काल" साबित हो रहा है।

राहुल गांधी ने शनिवार को एक वीडियो बयान में कहा कि पूरा देश जानता है कि परीक्षा से दो दिन पहले वाट्सएप पर नीट का पेपर बांटा जा रहा था, मगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं। संसदीय समिति ने सुधार की सिफारिशें की थी मगर शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए इसे कचरे में डाल दिया कि इसमें विपक्षी दलों के सदस्य बैठे हैं। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि देश के सबसे अहम शिक्षा क्षेत्र को आरएसएस, भाजपा और विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रोफेसर बनाए गए इनके लोगों के बीच पैसे बनाने का एक नेक्सस है। इस गठजोड़ ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया है और देश जानता है कि आरएसएस से हैं तो बिना विषय ज्ञान तथा अनुभव के भी आप कुलपति बन सकते हैं। यदि नहीं हैं तो कितना भी काबिल हों वीसी नहीं बन सकते। यही कारण है कि 80 बार पेपर लीक हुआ है और दो करोड़ युवाओं का भविष्य खराब हुआ है। नेता विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफे देने का आदेश देना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए और पेपर लीक के दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए।

पेपर लीक के सदमे से छात्र-छात्राओं के आत्महत्या की खबरों पर चिंता जताते हुए एक्स पोस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लखीमपुर खीरी के ऋतिक मिश्रा, दिल्ली की अंशिका पांडेय, राजस्थान के झुंझुनूं से प्रदीप मेघवाल, गोवा में रह रहे बेंगलुरु के छात्र सबने ये आत्मघाती कदम उठाया है। मोदी सरकार की भ्रष्ट और निकम्मी व्यवस्था ने उनके सपनों को रौंद दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब तो खुद 'फैक्ट चेक' करने लगे हैं और कल उन्होंने "इज आफ लिविंग" पर एक्स पर पोस्ट किया पर नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या पर चुप्पी साधे रहे। 2024 नीट पेपर लीक में जिन अधिकारियों पर सवाल उठे, उन्हें सजा नहीं मिली, बल्कि मलाईदार पद दे दिए गए और यही कारण है कि हर साल युवाओं का भविष्य लूटा जा रहा है। हालत ये है की अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हुए खरगे ने पीएम मोदी से कहा कि "परीक्षा-लीक पर चर्चा" कीजिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा।

नीट पेपर लीक की शिकायत करने वाले शिक्षक के बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ सीबीआइ टीम ने दर्ज किए सीकर के शशिकांत सुथार के बयान

▸ शिक्षक ने सीबीआइ को सौंपे डिजिटल साक्ष्य, एसआइ पर कार्रवाई

नीट-यूजी-2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआइ की टीम ने सीकर के शिक्षक शशिकांत सुथार के बयान दर्ज किए हैं। दरअसल, तीन मई को परीक्षा समाप्त होने के बाद शशिकांत को पेपर लीक होने की सूचना मिली थी। उन्होंने स्थानीय थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार, शशिकांत ने सीबीआइ को बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके मकान मालिक ने एक बहुप्रसारित पेपर दिखाया था। इस पेपर से नीट-यूजी की परीक्षा में रसायन विज्ञान के 45 व जीव विज्ञान के 90 प्रश्न पूछे गए थे। उन्होंने मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य (पीडीएफ और स्क्रीनशाट) सीबीआइ को सौंप दिए हैं। उनकी शुरुआती शिकायत के बाद ही पूरे देश में जांच शुरू हुई थी।

सीबीआई की टीम शुक्रवार और शनिवार को दो दिन सीकर में रही। शशिकांत सीकर के एक निजी कोचिंग संस्थान में रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं। उन्होंने छह मई की रात को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय को ई-मेल भेज कर पेपर लीक की सूचना दी थी। साथ ही उद्योग नगर पुलिस थाने में लीक पेपर को लेकर शिकायत देने का प्रयास किया। हालांकि, उस समय ड्यूटी पर मौजूद एसआइ ने शिकायत लेने से इन्कार कर दिया। अगले दिन सात मई को शशिकांत ने केंद्रीय एजेंसियों को फिर शिकायत भेजी। केंद्रीय एजेंसियों ने राजस्थान एसओजी को इस बारे में सूचना देकर सही तथ्यों की जानकारी देने के लिए कहा था।

बिंवाल परिवार की दो लड़कियां गायब: पेपर लीक मामले के आरोपित दिनेश बिंवाल, मांगीलाल बिंवाल एवं उसके पुत्र विकास के गिरफ्तार होने के बाद परिवार की दो लड़कियां सरकारी मेडिकल कालेजों से अचानक गायब हो गई हैं।

नीट पेपर के पुणे-नासिक से जयपुर तक पहुंचने की जुड़ गईं कड़ियां

नीलू रंजन • जागरण

▸ मनीषा बाघमारे ने हाथ से लिखे प्रश्नपत्रों को नासिक के शुभम को दिया, उसने उसका पीडीएफ बनाकर अहिल्यानगर के धनंजय और गुरुग्राम के यश को भेजा

शनिवार को मनीषा वाघमारे को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। एएनआइ

नई दिल्ली : नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआइ की अभी तक जांच में पेपर के पुणे, नासिक, गुरुग्राम से लेकर जयपुर तक पहुंचने की सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। पुणे से गिरफ्तार मनीषा बाघमारे पहले कोचिंग में पीवी कुलकर्णी की छात्रा रह चुकी हैं। नीट (राष्ट्रीयता पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) का पेपर हाथ में आने के बाद कुलकर्णी ने मनीषा से संपर्क किया और नीट के कुछ छात्रों की स्पेशल क्लास जुटाने को कहा।

इन छात्रों से लगभग 600 अंकों के साथ नीट परीक्षा पास कराने ताकि अच्छे मेडिकल कालेज में एडमिशन सुनिश्चित हो जाए, की गारंटी के साथ लाखों रुपये वसूले गए।

कुलकर्णी और मंढारे ने नीट की परीक्षा में आने वाले 180 में से 140 प्रश्नपत्र इन छात्रों को बता दिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इतने प्रश्न सही हल करने से लगभग 600 अंक सुनिश्चित हो जाते हैं।

सीबीआइ के सूत्रों के अनुसार मनीषा बाघमारे ने हाथ से लिखे प्रश्नपत्रों को नासिक के शुभम खैरनार को दिया। उसने उसका पीडीएफ बनाकर अहिल्यानगर के धनंजय लोखंडे और गुरुग्राम के यश यादव को भेज दिया। पहले कई बार नीट की परीक्षा दे चुका यश यादव जयपुर के मांगीलाल के बड़े बेटे के साथ कोचिंग कर चुका था, लेकिन दोनों को सफलता नहीं मिली थी। यश यादव ने मांगीलाल से संपर्क किया और छोटे बेटे के अच्छे अंकों के नीट पास कराने की गारंटी के साथ पेपर देने की बात कही। यहां तक कि मांगीलाल से यश यादव ने पहले पैसे भी नहीं लिए। परीक्षा में प्रश्नपत्र मिलने के बाद पैसे लेने के आश्वासन के साथ यश ने मांगीलाल के बेटे के परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अपने पास रख लिए थे।

मांगीलाल ने बेटे ने नीट पास करने के साथ और अधिक पैसा बनाने का फैसला किया और वहीं से गेस पेपर के नाम पर वाट्सअप और टेलीग्राम पर यह प्रसारित होने लगा।

तीन मई को हुई परीक्षा में गेस पेपर और मूल प्रश्नपत्र के प्रश्नों के हूबहू मेल खाने के बाद पेपर लीक का राजफाश हुआ और एनटीए को परीक्षा रद करने का फैसला करना पड़ा।

कुलकर्णी, मंढारे के पास थे केमेस्ट्री व बायोलाजी के सारे प्रश्न पत्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

सीबीएसई, जेईई, नीट समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए पूरे देश से शिक्षकों के पैनल बनाने का प्रोटोकाल है।

हर विषय के 100-150 शिक्षकों द्वारा अलग-अलग तैयार प्रश्नों को मिलाकर अंतिम प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। यानी किसी भी शिक्षक को यह नहीं पता होता है कि उसका कौन सा प्रश्न अंतिम प्रश्नपत्र में शामिल होगा। लेकिन कुलकर्णी और मंढारे के पास केमेस्ट्री और बायोलाजी के सारे प्रश्न थे, जिन्हें उन दोनों ने मनीषा बाघमारे के घर पर छात्रों को बताया।

जांच से जुड़े सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंतिम प्रश्नपत्र की जानकारी एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) में चंद शीर्ष अधिकारियों को होती है।

इन्हीं अधिकारियों पर प्रश्नपत्र के प्रिंटिंग प्रेस से छपने की प्रक्रिया की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है।

कुलकर्णी और मंढारे के प्रश्न पत्र तैयार करने वाली टीम में शामिल होने से इस आशंका की पुष्टि होती है कि इन दोनों को जानने वाले एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) के किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसकी पहुंच अंतिम प्रश्नपत्र तक थी, ने पेपर लीक किया।

बोटनी की शिक्षिका होने के बावजूद जिस तरह से मंढारे ने जूलाजी के प्रश्न भी छात्रों को बताए, उससे इस आशंका को और बल मिलता है।

पेपर तैयार करने वाली कमेटी में कैसे शामिल हुए कुलकर्णी व मंढारे? : सीबीआइ यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रश्न पत्र सिर्फ कुलकर्णी को लीक किए गए थे या फिर दोनों को।

मामले की जांच कर रही एजेंसी को एक बात और खटक रही है कि पुणे, लातूर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले कुलकर्णी और मंढारे को किसके कहने पर परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने वाली कमेटी में शामिल किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा करना परीक्षा प्रणाली की शुचिता के खिलाफ है।

1.63 करोड़ रुपये के गबन केस में गुरदासपुर की एसडीएम गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर

▸ तैनाती के दौरान चहेतों के खाते में डलवाई थी जमीन अधिग्रहण की रकम

5 सितंबर 2018 को एसडीएम ने डीसी के पास की थी शिकायत

डा अनुप्रीत कौर रंधावा। जागरण आर्काइव

पंजाब के तरनतारन जिले के पट्टी में जमीन अधिग्रहण के दौरान 1.63 करोड़ रुपये के गबन के मामले में गुरदासपुर की एसडीएम पीसीएस अधिकारी डा. अनुप्रीत कौर रंधावा को शनिवार सुबह उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया। डा. रंधावा के खिलाफ सात साल पहले जांच के बाद केस दर्ज किया गया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अनुप्रीत कौर को रविवार को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान एनएचएआइ की ओर से तरनतारन में जमीन अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इस दौरान सब डिवीजन पट्टी में तैनात अनुप्रीत कौर ने नौ जनवरी 2018 से 11 फरवरी 2019 तक जसबीर कौर, राजविंदर कौर, सरताज सिंह, बिक्रमजीत सिंह और गुरजंट सिंह नामक अपने चहेतों के बैंक खातों में एक करोड़ 63 लाख 67 हजार 970 रुपये की राशि डलवाई। हालांकि, जिन लोगों के खातों में राशि डाली गई, उनका अधिग्रहण से कोई संबंध नहीं था। अनुप्रीत के तबादले के बाद पट्टी के तत्कालीन एसडीएम नवराज सिंह बराड़ ने जब दस्तावेजों की जांच की तो उन्होंने राशि आवंटन में गबन पाया। उन्होंने पांच सितंबर 2018 को इसकी शिकायत तत्कालीन तरनतारन के डीसी को की। डीसी ने तत्कालीन एसएसपी ध्रुव दहिया को जांच सौंपी और वर्ष 2019 में एसडीएम अनुप्रीत के अलावा उन लोगों पर भी केस दर्ज किया, जिनके खातों में राशि गई थी।

किसानों के मुआवजे से जुड़े मामले में भी दर्ज हुई थी एफआइआर

रंधावा ने पाक सीमा पर कंटीली तार के पार वाली जमीन से संबंधित किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाले मुआवजे में भी गबन किया था। इस संबंध में उनके खिलाफ अलग एफआइआर दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से संबंधित दोनों एफआइआर की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जिसके चलते किसी भी आरोपित की तरनतारन पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई थी। बाद में रंधावा ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के कारण निलंबित भी रहीं।

एसएससी की जीडी परीक्षा से पहले नकल गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, देहरादून: 18 मई को आयोजित होने वाली स्टाफ सलेक्शन कमीशन (एसएससी) की कांस्टेबल जीडी आनलाइन परीक्षा से पहले एसटीएफ ने हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकल की आशंका को देखते हुए एसटीएफ उत्तराखंड ने नेहरू ग्राम स्थित सेंट जोंस एकेडमी केंद्र को सील किया है। इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसके तार 13 फरवरी 2026 को दून के परीक्षा केंद्र महादेवी कन्या पाठशाला में पकड़े गए हाईटेक नकल सेंटर से जुड़े हैं। इसी आरोपित ने परीक्षा केंद्र में नेटवर्किंग कर परीक्षा लैब, सर्वर रूम व अंडर ग्राउंड चेंबर तैयार किया था।

18 मई को एसएससी की कांस्टेबल जीडी की आनलाइन परीक्षा होनी है। परीक्षा को लेकर दो टीमों का गठन किया गया। एसटीएफ की टीम ने ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा उर्फ इंद्र निवासी निहाल विहार, दिल्ली को नेहरू ग्राम देहरादून स्थित सैंट जोंस एकेडमी से गिरफ्तार किया।

लखनऊ विवि के प्रोफेसर ने छात्रा को की आपत्तिजनक काल, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▸ कहा, 'तुम्हारे लिए पेपर आउट करा दिया है...आकर मिल लो'

▸ आडियो प्रसारित होते पर छात्रों में बढ़ा आक्रोश, धरने पर बैठे

'तुम्हारे लिए दोनों पेपर कोर और इलेक्टिव आउट कर दिए हैं...एक बार आकर मिल लो।' शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर यह आडियो प्रसारित होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि यह आडियो विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का है। आरोपित शिक्षक को निलंबित करने की मांग को लेकर छात्र प्राक्टर आफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपित शिक्षक के खिलाफ परीक्षा नियंत्रक ने हसनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। शुक्रवार देर रात पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया।

इंटरनेट मीडिया पर दो आडियो प्रसारित हो रहे हैं। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक डा. परमजीत सिंह ने छात्रा को तीन बार काल किया। कहा, 'तुम्हारे लिए दोनों पेपर आउट कर दिए हैं, एक बार आकर मिल लो। चार दिन के अंदर आ आओ।' यह आडियो प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र प्राक्टर कार्यालय पहुंच गए। छात्रों ने शिक्षक पर कालिख लगाने की कोशिश की और प्राक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। हसनगंज इंस्पेक्टर चितवन कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया है। छात्रा के बयान और आडियो की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपित शिक्षक बिजनौर जिले के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के रतनपुर खुर्द के रहने वाले हैं। छात्रों का कहना है कि पीड़ित छात्रा को शिक्षक ने 14-15 मई की रात कई बार काल कर अपने कार्यालय में बुलाने का दबाव बनाया। इसकी शिकायत छात्रा ने आंतरिक शिकायत समिति से की थी। मामले की जांच कर रही समिति ने आरोपित शिक्षक को बयान देने के लिए बुलाया था, जिसकी सूचना मिलने पर छात्र वहां पहुंच गए।

अहमदाबाद में पिछले तीन साल में 1.5 करोड़ पौधे लगाए गए: शाह

अहमदाबाद, आइएएनएस: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी विकास, पर्यावरण और बुनियादी ढांचागत पहलों की समीक्षा की। अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अमित शाह ने चल रहे 'ग्रीन लोकसभा - गांधीनगर लोकसभा' अभियान की समीक्षा की और कहा कि पौधारोपण और तालाबों का जीर्णोद्धार इस क्षेत्र की "नई पहचान" बन गया है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में 1.5 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं। इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, लोकसभा क्षेत्र के औसत तापमान में 2-3 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। इस अभियान का उद्देश्य हरित आवरण का विस्तार करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, पानी और हरा-भरा वातावरण उपलब्ध कराना है। शाह ने सुझाव दिया कि उन आवासीय समितियों की पहचान की जाए जहां 50 से अधिक पेड़ लगाए जा सकें।

प्रशासनिक विवाद

एफआरआइ यूनिवर्सिटी की वीसी बन गई पीएचडी की शोधार्थी

केंद्रीय सतर्कता आयोग में की गई शिकायत, यूजीसी और अखिल भारतीय सेवा के नियमों का बताया उल्लंघन, देहरादून स्थित अग्रणी संस्थान से जुड़े मामले में हितों के टकराव को लेकर भी उठ रहे सवाल

सुमन सेमवाल • जागरण

देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान। जागरण आर्काइव

देहरादून: वानिकी अनुसंधान में अग्रणी वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) की डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। भारतीय वन सेवा (आइएफएस) की वरिष्ठ अधिकारी ऋचा मिश्रा पर आरोप है कि वह एक ही समय में विश्वविद्यालय की कुलपति (वीसी) और उसी विश्वविद्यालय की पीएचडी शोधार्थी हैं। इस मामले ने विश्वविद्यालय प्रशासन, यूजीसी के नियमों और अखिल भारतीय सेवा (एआइएस) आचार संहिता के पालन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले में व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में की गई शिकायत के अनुसार, ऋचा मिश्रा का नाम एफआरआइ डीम्ड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक पीएचडी शोधार्थियों की सूची में दर्ज है। उनका रोल नंबर 21 पीएचडी 792 बताया गया है। उनका शोध विषय 'देहरादून के शहरी हरित क्षेत्रों का मूल्यांकन' है और पंजीकरण अवधि एक सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2027 तक दर्शाई गई है। इसके साथ ही वह विश्वविद्यालय की सर्वोच्च अकादमिक अधिकारी यानी कुलपति के पद पर भी कार्यरत हैं।

मामले का सबसे बड़ा विवाद हितों के टकराव (कान्फ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट) को लेकर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी कुलपति को ऐसे किसी भी कार्य से बचना होता है, जिसमें व्यक्तिगत हित और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच टकराव की स्थिति बने। आरोप है कि कुलपति होने के नाते ऋचा मिश्रा विश्वविद्यालय की प्रवेश, परीक्षा, शोध मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करने जैसी प्रक्रियाओं पर प्रभाव रखने की स्थिति में हैं, जबकि वह स्वयं उसी संस्थान की शोधार्थी भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति 'जज और वादी एक साथ' जैसी प्रतीत होती है। दस्तावेज में यह भी दावा किया गया है कि यह मामला अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, 1968 के प्रविधानों के विपरीत है। किसी अधिकारी को निजी हित और सार्वजनिक कर्तव्यों के बीच टकराव से बचना अनिवार्य है। अधिकारी अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर सकता।

आइसीएफआरई के पूर्व डीजी की पीएचडी हो चुकी वापस

इसी तरह के एक मामले में आइसीएफआरई के पूर्व महानिदेशक (डीजी) डा जीएस रावत ने कार्यरत रहने के दौरान पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। इसी तरह की एक शिकायत के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर उनकी डिग्री वापस ले ली गई थी। यह मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी।

लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश पर बंगाल में बवाल

जागरण संवाददाता, आसनसोल

▸ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने में की तोड़फोड़, किया पथराव

बंगाल के आसनसोल स्थित रेलपार क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने से संबंधित प्रशासनिक संदेश जारी होने के बाद शुक्रवार की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल काटा। बड़ी संख्या में जहांगीरी मोहल्ले के लोग स्थानीय पुलिस चौकी पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने लगभग आधा दर्जन पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, वहीं सड़क पर खडी अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पथराव भी किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के थानों से पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। परंतु, हालात नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिसकर्मियों को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई। पुलिस ने मामले में अबतक दर्जनभर लोगों को गिरफ्तार किया है। आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त डा. प्रणव कुमार के अनुसार स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है।

बताया गया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री सुवेंदु ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की मनाही का निर्देश दिया था। इसके बाद आसनसोल में कई धार्मिक स्थलों से लोगों ने स्वयं लाउडस्पीकर उतार दिया। इस बीच रेलपार इलाके में भी पुलिस ने माइक से इसकी घोषणा की और लोगों को निर्देश का उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

न्यूज गैलरी

मिजोरम में 10 करोड़ रुपये से अधिक का मादक पदार्थ जब्त

आइजल: मिजोरम में पुलिस ने दो अलग-अलग अभियानों में 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किया है। मिजोरम पुलिस ने बताया कि 13 मई को पुलिस की विशेष टीम ने एन. छिमलुआंग में गश्त के दौरान ट्रक को रोका। जब टीम अन्य माल लदे वाहनों की जांच में लगी हुई थी, तभी ट्रक का चालक और उसका सहायक मौके से फरार हो गया। पीछा करने के बावजूद, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। एक मैकेनिक की मदद से वाहन की जांच करने पर, गियर लीवर के पास से 900.29 ग्राम संदिग्ध हेरोइन से भरे 70 साबुन के डिब्बे बरामद किए गए जिनकी कीमत लगभग 1.8 करोड़ रुपये है। ट्रक और दो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। (एएनआइ)

देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में एसडीएम सहित चार निलंबित

देवास : मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंककला में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में चार अधिकारियों पर गाज गिरी है। टोंकखुर्द के एसडीएम, सोनकच्छ के एसडीओपी, चिड़ावद के नायब तहसीलदार और टोंककला के चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। बता दें कि गुरुवार सुबह हुए इस हादसे में पांच श्रमिकों की मौत हो गई थी और लगभग 20 घायल हुए। हादसे का शिकार हुए श्रमिक बिहार के थे। (नईदुनिया)

मनोज जरांगे की 30 मई से आंदोलन की चेतावनी

छत्रपति संभाजीनगर : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने मराठा समुदाय की अधूरी मांगों को पूरा करने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को 29 मई तक का अल्टीमेटम दिया और मांगें नहीं माने जाने पर 30 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। जरांगे ने मराठा आरक्षण उप-समिति को भंग करने की मांग की और दावा किया कि इस समिति ने समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है। (प्रेट्र)

नरेन्द्र मोदी ने इराक के प्रधानमंत्री को दी बधाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अली फलीह काजिम अल-जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर शनिवार को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया, अली फलीह काजिम अल-जैदी को हार्दिक बधाई। भारत इराक के साथ अपने दीर्घकालिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को अत्यंत महत्व देता है तथा सभी क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। (प्रेट्र)

लू घोषित करने के मापदंडों में बदलाव करेगा आइएमडी

बदलते मौसम के मिजाज और भीषण होती गर्मी के बीच बड़ा फैसला, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं वर्तमान मापदंड

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : बदलते मौसम के मिजाज और भीषण होती गर्मी के बीच मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। अब देश में लू घोषित करने के पुराने पैमानों को बदला जाएगा। मौजूदा मापदंड भारत की अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों, खासकर तटीय इलाकों के अनुकूल नहीं हैं, जिसके कारण सही समय पर चेतावनी जारी करने में दिक्कत आ रही है। एक अधिकारी ने कहा, "हमने लू की घोषणा के मापदंडों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है और ये बदलाव जल्द ही लागू किए जाएंगे। मापदंडों को अंतिम रूप देने से पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी परामर्श किया जाएगा।"

इस साल केरलम ने भीषण गर्मी और उमस का ऐसा दौर देखा, जिसने विज्ञानियों को भी चिंता में डाल दिया। पहली बार दक्षिण भारत (कर्नाटक-महाराष्ट्र तट) के करीब एक 'एंटी-साइक्लोन' सिस्टम बना। आमतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में दिखने वाले इस सिस्टम ने हवा को नीचे की तरफ धकेला, जिससे गर्म हवा सतह पर ही फंस गई। नतीजा यह हुआ कि केरलम में रातें भी तपती रहीं और रात का तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया।

प्रयागराज में गर्मी और लू बचने की कोशिश करता बाइक सवार परिवार। एएनआइ

वर्तमान में, मौसम विज्ञान विभाग तटीय क्षेत्रों में लू की चेतावनी तब जारी करता है जब अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है और दर्ज किए गए अधिकतम तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए, यह सीमा 40 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का अंतर होना चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह सीमा 30 डिग्री सेल्सियस है और सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का अंतर होना चाहिए। ये परिस्थितियां राज्य के कम से कम दो स्थानों पर दर्ज होनी चाहिए। केरलम जैसे राज्यों में उमस के कारण 'हीट स्ट्रेस' (गर्मी का तनाव) इतना बढ़ जाता है कि लोग हीटस्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर दो स्थानों पर पैमाना पूरा न होने के कारण आइएमडी 'लू' की आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाता था। अब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर इन नियमों को व्यावहारिक बनाया जा रहा है, ताकि समय रहते सटीक चेतावनी जारी कर लोगों की जान बचाई जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक, लगातार दो साल 'अल नीनो' के प्रभाव और अनियमित मानसून के कारण केरलम अब 'क्लाइमेट चेंज हाटस्पाट' बन चुका है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में पहुंचा

- इस बार केरल में मानसून 26 मई को जल्दी पहुंचने की उम्मीद
- आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत एक जून को होती है सस स

नई दिल्ली, प्रेट्र : मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ने दक्षिण-पूर्व अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पूरे निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के विजयपुरम समेत कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है।।

आइएमडी ने यह कहा कि अगले तीन-चार दिनों में मानसून के दक्षिण-पूर्व अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंडमान द्वीप समूह के शेष हिस्सों और अंडमान सागर के साथ-साथ पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी इस अवधि के दौरान मानसून की शुरुआत देखने को मिल सकती है।

इससे पूर्व आइएमडी ने शुक्रवार को कहा था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरल में इस बार 26 मई को आगमन की उम्मीद है। वैसे केरल में आमतौर पर मानसून की शुरुआत एक जून को होती है। इससे पहले, आइएमडी ने कहा था कि इस वर्ष भारत में मानसून के मौसम के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है। यह स्थिति इस मौसम के दौरान अल नीनो की स्थिति के उभरने के कारण हो सकती है, जो देश में कम वर्षा का कारण बनती है।

अगले कुछ दिन एनसीआर और पंजाब में लू चलेंगी

आइएएनएस के अनुसार, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में एनसीआर में तापमान में तेज वृद्धि की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में 17 मई को लू चलने के साथ ही अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। आइएमडी ने पंजाब में भी 20 मई तक लू चलने की आशंका जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है।

सीबीआइ की एफआइआर में डीजीपी विजिलेंस का नाम लेकिन आरोपित नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़: सीबीआइ की ओर से एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी (ईटीओ) से रिश्वत लेने के मामले में दर्ज एफआइआर में डीजीपी (विजिलेंस) एसएस चौहान का नाम भी शामिल है। एफआइआर में चौहान को आरोपित नहीं बनाया गया है लेकिन इसमें साफ लिखा है कि उनका रीडर ओपी राणा उनके नाम पर ही रिश्वत मांग रहा था। खास बात यह है कि पिछले महीने ही राज्य सरकार ने राज्य में स्थायी डीजीपी पद के लिए यूपीएससी को जिन अधिकारियों के नाम का पैनल भेजा है, उनमें वरिष्ठतम आइपीएस एसएस चौहान का नाम भी शामिल है। उधर रिश्वतकांड में फरार आरोपित इंस्पेक्टर ओपी राणा के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए रेड कार्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है सीबीआइ चौहान को पूछताछ के लिए बुला सकती है।

एफआइआर के अनुसार, यह मामला एक लंबित शिकायत को बंद कराने के नाम पर 13 लाख रुपये की रिश्वत मांगने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ईटीओ अमित कुमार ने आठ मई को विजिलेंस को शिकायत दी थी कुछ बिचौलिए पंजाब विजिलेंस अधिकारियों के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। आरोप था कि यह रकम विजिलेंस प्रमुख एसएस चौहान के नाम पर और उनके रीडर ओपी राणा के जरिए मांगी जा रही थी।

घर का किराया नहीं दे पाया तो मकान मालिक के हवाले कर दी पत्नी-बेटी

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद

- गुजरात के मोरबी में सामने आया मामला, छह महीने तक दोनों से दुष्कर्म करता रहा मकान मालिक
- पुलिस ने पीड़िता के पिता और मकान मालिक को गिरफ्तार किया, तीसरे आरोपित की तलाश जारी

गुजरात के मोरबी में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार की महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर छह माह तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि केवल 2000 रुपये किराया नहीं चुका पाने पर पीड़िता के पति ने ही मकान मालिक के साथ सौदा कर पत्नी और बेटी का यौन शोषण होने दिया। पुलिस ने मामले में मकान मालिक और पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार मूल रूप से सुरेंद्रनगर का रहने वाला है और करीब छह माह पहले रोजगार की तलाश में मोरबी आया था। परिवार ने दो हजार रुपये मासिक किराये पर मकान लिया था, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट गहरा गया और चार माह का किराया बकाया हो गया।

आरोप है कि इसके बाद मकान मालिक ने बकाया किराये के बदले महिला और उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। पीड़िताएं लंबे समय तक बेबसी में यह सब सहती रहीं। बाद में प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

प्रतीकात्मक

पुलिस उपाधीक्षक जेएम लाल ने बताया कि मामले में नाबालिग पीड़िता के पिता और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपित की तलाश जारी है।

सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद में टली सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद मामले में सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। इससे पूर्व अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पुलिस जांच की मांग को लेकर दलीलें रखी गईं।

शिकायतकर्ता पक्ष ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल उनकी मांग सीधे ट्रायल शुरू कराने की नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष पुलिस जांच करवाने की है। याचिकाकर्ता का कहना था कि रिकार्ड में कई ऐसे तथ्य हैं, जिनकी जांच जरूरी है और बिना जांच के सच्चाई सामने नहीं आ सकती। याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी, जबकि उनका नाम वर्ष 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हुआ था। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल हुआ।

सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या मामले में सीबीआइ ने कई स्थानों पर छापे मारे

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- जांच दल कोलकाता स्थित संयुक्त निदेशक को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सचिव (सहायक) चंद्रकांत रथ की हत्या मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान शुक्रवार देर रात शुरू हुआ और शनिवार तड़के तक जारी रहा। सीबीआइ ने बंगाल सरकार के अनुरोध पर इस हत्याकांड की जांच बंगाल पुलिस से अपने हाथ में ली है।

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने दिल्ली से विशेष अपराध शाखा के एक डीआइजी के नेतृत्व में सात सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। टीम में एजेंसी की विभिन्न इकाइयों के अनुभवी जांच अधिकारियों को शामिल किया गया है।

मालूम हो कि सुवेंदु के सहयोगी चंद्रकांत की छह मई को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के दो दिन बाद हुई थी। मामले में बंगाल पुलिस अब तक तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपित मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से पकड़ा गया था, जबकि तीसरे आरोपित राज सिंह को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया गया।

चंद्रकांत रथ। फाइल

दिल्ली में मारा गया छापा

सीबीआइ की टीम ने दिल्ली के सुशांत विहार में छापेमारी की। यह छापेमारी शुक्रवार देर रात से शनिवार तड़के तक की गई, लेकिन यहां से किसी को हिरासत में लेने की बात सामने नहीं आई है। बंगाल सरकार के अनुरोध पर सीबीआइ ने इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की जांच राज्य पुलिस से अपने हाथों में ले ली है।

सुवेंदु पर हमले की धमकी देने वाला आरोपित गिरफ्तार

राब्यू, जागरण • कोलकाता : बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर आत्मघाती हमला करने की धमकी देने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने गार्डेनरीच इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 27 वर्षीय हसनैन इकबाल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसने अल कायदा की मदद से मुख्यमंत्री पर हमला कराने की धमकी वाला ईमेल भेजा था। कोलकाता पुलिस ने बताया कि भवानीपुर थाने को 14 मई को एक धमकी भरा ईमेल मिला था।

मौलवी की सलाह पर सुंदर लड़की से निकाह के लिए दी नरबलि

जागरण संवाददाता, जयपुर

- राजस्थान का मामला, तलाकशुदा आरोपित ने वारदात को दिया अंजाम
- आरोपित की हरकतों से फिर से निकाह करवाने को तैयार नहीं थे स्वजन

आधुनिक युग में विज्ञान व तकनीक ने समाज को नई दिशा दी है, लेकिन आज भी अंधविश्वास लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही नजारा राजस्थान के पाली जिले में देखने को मिला। जहां सुंदर लड़की से निकाह के लिए 30 वर्षीय मुस्लिम युवक ने मौलवी के कहने पर 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। मौलवी ने कहा था कि नरबलि देने पर ही तुम्हारा निकाह होगा। ऐसे में आरोपित ने अपने ही गांव के एक बच्चे की हत्या कर दी। इससे पहले भी वह एक बच्चे की हत्या करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित ने पिछले साल एक भैंस के बछड़े का सिर काटने के साथ ही एक गाय का गुप्तांग काट दिया था। दोनों प्रकरणों के कारण आरोपित की पहली पत्नी उसको तलाक दे चुकी है। स्वजन उसकी हरकतों के कारण फिर से निकाह करवाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में करीब एक माह पहले वह एक मौलवी के संपर्क में आया। पुलिस ने बताया कि बच्चा मदरसे से वापस घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपित उसे गांव के बाहर स्थित तालाब के पास ले गया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आरोपित ने मृतक के स्वजन को गुमराह करने का प्रयास किया। आरोपित के सूचना देने के बाद स्वजन जब शव के पास पहुंचे तो वहां तंत्र-मंत्र का सामान पड़ा हुआ था।

प्रतीकात्मक

डेढ़ सेंटीमीटर के अधिक के कर्व ने रोकी ट्रेनें

मनोज श्रीवास्तव • जागरण

- दस माह बाद भी सीआरएस की आपत्ति को दूर नहीं कर सका रेलवे का सेतु निर्माण खंड
- घाघरा घाट पुल के एक पिलर में मिला अधिक घुमाव, ट्रेनों के पटरी से उतरने का खतरा

गोंडा : रेलवे ने 1117.80 करोड़ रुपये खर्च कर 10 माह पहले 61.72 किलोमीटर लंबी गोंडा कचहरी-बुढ़वल के बीच तीसरी लाइन तैयार करा ली थी, लेकिन उस पर ट्रेनों का संचालन आज तक नहीं हो पाया। कारण, दस माह पूर्व सीआरएस (मुख्य संरक्षा आयुक्त) ने लाइन के निरीक्षण में जो आपत्ति जताई थी, उसका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जांच में सामने आया कि तीसरी रेल लाइन के लिए बने घाघरा घाट पुल के एक पिलर में डेढ़ सेंटीमीटर कर्व (घुमाव) अधिक हो गया है, जिससे ट्रेनें पटरी से उतर सकती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्रीय बजट में तीसरी लाइन बनाने की घोषणा हुई, जिसका निर्माण 2022-23 में शुरू हुआ। 11 अरब 17 करोड़ 80 लाख की लागत 61.72 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जानी है। चार खंडों में बांटकर यह कार्य किया जाना था, जिसमें तीन खंड पूरा हो गया है। चौथे खंड में पड़ रहे गोंडा जंक्शन मुख्यालय से गोंडा-कचहरी में लाइन बिछाई जानी बाकी है।

घाघरा पर तीसरी रेल लाइन के लिए बनाए गए पुल पर एक पिलर में है कर्व (घुमाव) जागरण

जुलाई, 2024 में गोंडा कचहरी से कर्नलगंज तक पहले खंड में कार्य पूर्ण हो गया। दूसरा खंड कर्नलगंज से घाघरा घाट तक है, जिसमें सरयू व घाघरा घाट पर नया पुल बनाया गया। घाघरा घाट पर बनाए गए करीब नौ सौ मीटर पुल के एक पिलर में डेढ़ सेंटीमीटर अधिक घुमाव हो गया। इससे ट्रेनें पटरी से उतर सकती हैं। दस माह पूर्व तीन व चार जुलाई को हुए पूर्वोत्तर मंडल के मुख्य संरक्षा आयुक्त प्रणजीव सक्सेना के निरीक्षण में घाघरा घाट पर बनाए गए तीसरी रेलवे लाइन के पुल के एक पिलर में डेढ़ सेंटीमीटर घुमाव अधिक होने समेत कई खामियां मिली थीं, जिन्हें दुरुस्त कराने का निर्देश रेलवे के सेतु निर्माण खंड को दिया था लेकिन दस माह बाद भी यह दुरुस्त नहीं हो पाया। ऐसे में इस लाइन पर ट्रेनें नहीं चल पाईं। जबकि रेल मंत्रालय ने यह लाइन विशेष रूप से मालगाड़ियों के आवागमन के लिए बनाई थी। दोनों लाइन पर 70 जोड़ी से अधिक सवारी गाड़ी व 60 जोड़ी से अधिक मालगाड़ी चल रही हैं। मालगाड़ी आने व लाइन न क्लीयर होने के कारण प्रतिदिन 10 से 15 यात्री ट्रेनें लेटलतीफी का शिकार हो रही हैं। मालगाड़ियों के लिए यह विशेष लाइन बन जाने के बाद सवारी ट्रेनों को लाइन क्लीयर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता और वे कम समय में लखनऊ पहुंच जातीं। सीआरएस के निरीक्षण में घाघरा घाट पुल पर कुछ खामियां मिली थीं, जिन्हें दूर कराया जा रहा है। जल्द ही इन पर भी ट्रेनें चलने लगेंगी।

गले को चीर किशोर के मुंह से निकला दीवार का नुकीला सरिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन

- मध्य प्रदेश के खरगोन में खेलते समय हुआ हादसा, इंदौर किया गया रेफर
- सीआइएसएफ परिसर की बाउंड्री वाल का नुकीला सरिया आर-पार घुस

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में बच्चों के साथ खेल रहे 16 वर्षीय किशोर के गले में सीआइएसएफ परिसर की बाउंड्री वाल का नुकीला सरिया आर-पार घुस गया। हादसा इतना भयावह था कि सरिया गले और जबड़े को चीरते हुए मुंह से बाहर निकल आया। रेस्क्यू के बाद किशोर को इंदौर के अस्पताल में ले जाया गया। यहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। डाक्टर उपचार में जुटे हैं।

बच्चे सड़क किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे की चप्पल सीआइएसएफ परिसर की आठ फीट ऊंची सुरक्षा दीवार के दूसरी ओर जा गिरी। साथियों के कहने पर वह चप्पल लेने के लिए दीवार के उस पार उतर गया। चप्पल वापस फेंकने के बाद जब वह दीवार पर चढ़कर लौटने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे दीवार पर लगे नुकीले लोहे के सरिए सीधे उसके गले में धंस गया। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद बच्चे घबरा गए और चीख-पुकार मच गई।

किशोर की गर्दन और मुंह में फंसा बाउंड्री वाल का सरिया। वीडियो ग्रैब

किशोर सरिए में बुरी तरह फंसा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। सरिया ऐसे निकाला जाता तो उसकी जान जा सकती थी, इसलिए कटर मशीन मंगाई गई और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सरिए को काटकर किशोर को बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए इंदौर रेफर कर दिया।

कश्मीर में मस्जिदों से उठी आवाज, नशे का यार- कौम का गद्दार

नवीन नवाज • जागरण

- चार हजार से अधिक मस्जिदों में मौलवी नशे के खिलाफ लोगों को कर रहे जागरूक

श्रीनगर : आतंकवाद से मुक्त हो रहे जम्मू-कश्मीर को अब नशे से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन से लेकर आमजन उठ खड़ा हुआ है। कश्मीर में मस्जिदों से सुबह-शाम युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया जा रहा है। चार हजार से ज्यादा दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों और धार्मिक संस्थाओं से लोगों से नशा तस्करों का बहिष्कार करने और उनके खिलाफ प्रशासन की मदद करने को कहा जा रहा है। कश्मीर के बाजारों, गली-मोहल्लों में निकल रहीं रैलियों में 'नशे को भगाना है-कश्मीर को बचाना है' और 'नशे का जो यार है-कौम का गद्दार है' जैसे नारे गूंज रहे हैं।

श्रीनगर की जामा मस्जिद, हजरतबल, बाबा रेशी, अशमुकाम, जनाब साहिब सौरा और कई अन्य इबादतगाहों में शुक्रवार की नमाज के बाद नशे के खिलाफ बयान, तकरीरें और जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। लगभग 955 से ज्यादा उलेमा और मौलवी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों, मोहल्लों को नशे से पाक बनाने के लिए आगे आएं। कश्मीर के प्रमुख मजहबी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हर एक कश्मीरी की, हर उलेमा और मौलवी की भी है। इसलिए सभी मजहबी नेता नशे को समाप्त करने के लिए कोशिश करें।

मीरवाइज मौलवी उमर फारूक। आर्काइव

वर्ग पहेली-3337

बाएं से दाएं:-
1. दिलासा देना, आशा दिलाना (4)। 3. बुद्धि, विचार (3)। 6. कागज की चौकोर थैली, खोल (3)। 7. जो पूरा न पका हो (4)। 9. चिड़ियों की चह-चह की ध्वनि (3)। 10. अप्राप्य, दुष्प्राप्य (3)। 12. मध्य प्रदेश का एक जिला (4)। 14. सहने योग्य (4)। 17. आकार में बहुत बड़ा (3)। 20. तमाचा (3)। 21. प्राचीन काल से चला आता हुआ (4)। 22. पकड़ने की क्रिया (3)। 23. रुकना, ठहरना (3)। 24. काबुल का रहने वाला (4)।

ऊपर से नीचे:-
2. छोटी नाली (3)। 3. जड़ से गायब (4)। 4. आभास होना, चमकना (4)। 5. सफल (4)। 7. यदि (3)। 8. जो मोटा न हो (3)। 11. रात्रि, निशा (3)। 13. मदारी का खेल (3)। 15. अलग करना या निकालना (3)। 16. यूनान का निवासी (3)। 17. विशालकाय (4)। 18. सना हुआ, तर (4)। 19. हजम कर जाना (4)। 21. रास्ता, मार्ग (3)।

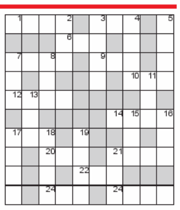

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

	अ		स			ज		ह	
त	ल	ष	र			हा	नि	क	र
	ह		स	मा	प	न		ला	
उ	दा	स		न			अ	ना	म
		र		बे	हे	नी	य		
		क	र	ता	ल		मि		
सं	तो	ना			थ		त	को	ना
	न		क	त	र	न		नों	
सं	पू	र्ण	ता			ज	य	का	र
	रा		र			र		न	

जागरण सुडोकू-3337

6		5		2		3		7
	2			3			6	
7		4	6		5		1	
3			8			9		1
	7	9		1	2		5	
8				5				2
2	4		1				9	
		6		9		1		
9			5		7		2	8

कल का हल

3	2	4	7	1	5	9	8	6
1	5	6	9	4	8	3	2	7
9	8	7	3	6	2	1	5	4
6	7	3	5	9	4	8	1	2
4	9	2	8	3	1	7	6	5
8	1	5	2	7	6	4	9	3
7	4	8	6	2	9	5	3	1
2	3	9	1	5	7	6	4	8
5	6	1	4	8	3	2	7	9

आज का भविष्यफल : रविवार 17 मई, 2026

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। **राहुकाल:** सायं 04:30 से 06 बजे तक। **दिशाशूल:** पश्चिम। **पर्व एवं त्योहार**- पुरुषोत्तम मास, अधिक मास प्रारंभ।

कल 18 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल- पूर्व

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया 17 घंटे 54 मिनट तक, तत्पश्चात तृतीया रोहिणी नक्षत्र 11 घंटे 33 मिनट तक, तत्पश्चात मृगसिरा नक्षत्र सुकर्मा योग 21 घंटे 48 मिनट तक, तत्पश्चात धृति योग वृष में चंद्रमा 22 घंटे 05 मिनट तक तत्पश्चात मिथुन में।

मेष: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। दांपत्य जीवन में सुधार आएगा।

वृष: मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। धार्मिक कार्य संपन्न होगा।

मिथुन: पारिवारिक सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

कर्क: धन, पद, प्रतिष्ठा में प्रगति होगी। सत्ता का सहयोग रहेगा।

सिंह: पिता का सहयोग मिलेगा। यात्रा उत्साहवर्धक होगी।

कन्या: बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

तुला: रिश्तों में निकटता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृश्चिक: जीवनसाथी का सहयोग रहेगा। बड़ा कार्य संपन्न होगा।

धनु: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मकर: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। संतान दायित्व की पूर्ति होगी।

कुंभ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धन, सम्मान में वृद्धि होगी।

मीन: सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा की स्थिति सुखद होगी।

58 लंगर संगठनों को अनुमति दी गई है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अभी तक बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने के लिए। 57 दिन तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी।

रविवार विशेष

स्क्रीन में डूबा बचपन हो रहा बीमार

आज के मशीनी युग में बच्चों की दुनिया तेजी से बदल रही है। आलम यह है कि किताबों, खेल के मैदानों और दोस्तों के बीच खिलने वाला बचपन अब धीरे-धीरे मोबाइल स्क्रीन में सिमटता जा रहा है। पढ़ाई की जरूरत के रूप में बच्चों के हाथों में पहुंचे स्मार्टफोन अब उनकी दिनचर्या, मनोरंजन और सामाजिक व्यवहार का स्थायी हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसका प्रभाव केवल आंखों तक सीमित नहीं है, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, नींद की गड़बड़ी, मोटापा, अवसाद और गेमिंग डिसआर्डर जैसी समस्याएं तेजी से सामने आ रही हैं। सीतापुर, धनबाद और जालंधर से जुटाई गई रिपोर्टें इस बदलते परिदृश्य को तीन अलग-अलग आयामों में सामने लाती हैं। कहीं परिवार मोबाइल जोन बनाकर स्क्रीन टाइम सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किशोर डिजिटल निर्भरता की मानसिक गिरफ्त से निकलने के लिए उपचार ले रहे हैं, तो कहीं खेल के मैदानों की जगह मोबाइल स्क्रीन ने ले ली है, जिससे पार पाना अब समय की मांग बन गया है।

किशोरों को जकड़ रहीं डिजिटल बेड़ियां

हंसमुख स्वभाव, पढ़ाई में मन लगाने वाले किशोर को अब खाने-पीने की सुध नहीं रहती। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। 14 साल के बेटे की हालत देख घरवाले डाक्टर के पास पहुंचे, तो उन्होंने मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि किशोर गेमिंग डिसआर्डर का पीड़ित है। उसने मन में बनाई काल्पनिक दुनिया को हकीकत मान लिया है। छह माह इलाज चला। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है।

सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डा. संजय कुमार कहते हैं कि यह महामारी जैसा है। इससे बच्चे अवसाद व एंग्जाइटी में फंस रहे हैं। धनबाद में 10 से 17 वर्ष के करीब 15 प्रतिशत बच्चे इसके शिकार हैं। ऐसे अधिकतर मामले एकल परिवार में देखने को मिलते हैं, जहां माता-पिता दोनों कामकाजी हैं। डा. कुमार के मुताबिक गेमिंग डिसआर्डर से प्रभावित बच्चे शादी या पार्टी में जाने से बचते हैं। उन्हें घर में मोबाइल चलाना पसंद होताहै। ऐसे अभिभावकों की काउंसिलिंग की जा रही है, ताकि वे बच्चे को डाक्टर के पास लाएं।

ग्रुप गेम का चलन बढ़ा रहा दुष्प्रभावः मोबाइल पर गेम में पैसे लगाना, आउटडोर गेम्स को तरजीह न देने की स्थिति खतरनाक है। किशोर व युवा तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। ग्रुप बनाकर गेम खेलने का चलन बढ़ा है। डा.संजय हाउसिंग कालोनी के किशोर के बारे में बताते हैं, वह भी गेमिंग डिसआर्डर का शिकार था। स्वजन के समझाने पर जान देने तक की बातें करता था। एक दिन तो कलाई भी काट ली। काउंसिलिंग व इलाज से वह ठीक हुआ।

(धनबाद से डा. मोहन गोप)

बच्चों को गेमिंग डिसआर्डर से बचने की सलाह देते डा. संजय कुमार ● जागरण

काल्पनिक दुनिया से बाहर आई बिटिया, बनेगी डाक्टर

डा. कुमार बताते हैं कि कार्मिक नगर की 16 वर्षीय किशोरी का व्यवहार घर वालों के प्रति बदल-बदला सा रहने लगा था। मम्मी-पापा से बहस करती थी। डाक्टर के परामर्श के बाद ठीक हुई। फिर से क्लास में अच्छे अंक ला रही है। अब कहती है कि डाक्टर बनेगी।

यह मोबाइल बच्चों की दिनचर्या दोस्ती और मनोरंजन पर हावी

कोरोनाकाल के दौरान शुरू हुई आनलाइन पढ़ाई ने बच्चों की दिनचर्या में स्क्रीन को स्थायी जगह दे दी। पहले मोबाइल और लैपटाप केवल जरूरत तक सीमित थे, पर अब वही पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्ती का माध्यम बन गए।

माडल टाउन में रहने वाली 13 वर्षीय अनीशा बताती है कि पहले उसे केवल पढ़ाई के लिए दो घंटे फोन मिलता था, पर अब पढ़ाई खत्म होने के बाद भी फोन हाथ में ही रहता है। दरअसल, ग्राउंड में जाने का मन ही नहीं करता। इसी तरह 15 वर्षीय रोहन की दिनचर्या आज के बदलते बचपन की तस्वीर पेश करती है। सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक स्कूल, फिर यूट्यूब पर गेमिंग वीडियो, शाम को इंस्टाग्राम रील। रोहन कहता है कि सच में मैदान जाने का न तो टाइम मिलता है और न ही मन करता है। बठिंडा के विश्वास पब्लिक स्कूल की शिक्षिका प्रवीण मानती हैं कि केवल स्क्रीन को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। स्कूल में पीटी (फिजिकल ट्रेनिंग) के पीरियड बढ़ाए गए हैं। स्पोर्ट्स फेस्ट शुरू किए गए हैं। अभिभावकों को भी चाहिए कि शाम को बच्चा बोर हो रहा है तो उसे पार्क ले जाएं। लूडो खिलाएं। स्टोरी सुनाएं। शिक्षिका मीनाक्षी शर्मा कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाने को स्क्रीन दी गई थी, पर अब वही उनकी पढ़ाई, खेल व दोस्ती सब कुछ बन गई। इससे उनकी सोचने और समझने की आदत प्रभावित हो रही है।

ओलिंपियन संजीव कुमार ने दिए सुझाव

ओलिंपियन संजीव कुमार कहते हैं कि खेल मैदानों का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले 50 से 60 बच्चे खेलते दिखाई देते थे, वहां अब मुश्किल से पांच से सात बच्चे नजर आते हैं। एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों के अनुसार 10 से 16 वर्ष के बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम 4.2 घंटे से बढ़कर 6.7 घंटे तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी अनिवार्य की जाए। घर में स्क्रीन फ्री समय तय हो। माता-पिता खुद मोबाइल का सीमित इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। मोहल्ला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं और सामूहिक गतिविधियां शुरू हों।

मोबाइल पर रील देखता बच्चा ● जागरण

जालंधर के अर्बन एस्टेट में शाम के समय खाली पड़ा मैदान।

इसलिए स्क्रीन से चिपक रहे हैं बच्चेः मनोवैज्ञानिक डा. अतुल मदान बताते हैं कि मोबाइल गेम्स और शार्ट वीडियो बच्चों के दिमाग को तुरंत आनंद देने का काम करते हैं। बच्चों का मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है, इसलिए उसे तुरंत मिलने वाला रिवार्ड ज्यादा आकर्षित करता है। वह कहते हैं कि मैदान में खेलने में मेहनत, धैर्य, हार-जीत और इंतजार शामिल होता है, जबकि स्क्रीन पर सब कुछ तुरंत मिल जाता है। यही कारण है कि बच्चे धीरे-धीरे वास्तविक गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं।

पढ़ाई से शुरू होकर लत तक पहुंचा सफरः मनोचिकित्सक डा. अमन सूद बताते हैं कि शुरुआत पढ़ाई से हुई थी, फिर मनोरंजन जुड़ा और अब कई मामलों में मोबाइल लत का रूप ले रहा है। आठ से 14 वर्ष तक के बच्चे स्क्रीन एडिक्शन की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। चिड़चिड़ापन, नींद में कमी, आंखों की परेशानी और मोटापा इसके सामान्य लक्षण बनते जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। अभिभावक अलर्ट रहें।

(जालंधर से जगदीश कुमार)

मोबाइल से दूरी बनाकर कम कर रहे स्क्रीन टाइम

तकनीकी युग में मोबाइल जहां आवश्यकता बन गया है, वहीं इसका अधिक प्रयोग बच्चों की आंखों व मस्तिष्क को कमजोर कर रहा है। लगातार स्क्रीन पर समय बिताने से बच्चों की आंखों में निकट दृष्टि दोष (मायोपिया), चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, मोटापा, एकाग्रता में गिरावट आ रही है। इन बढ़ते खतरों को लेकर प्रशासन के साथ आमजन भी चिंतित व सजग हो रहे हैं। जागरूक लोग स्क्रीन टाइम कम करने को लेकर सतर्कता भी बरत रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर ने सभी विद्यालयों में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को मोबाइल के बजाय डायरी पर गृहकार्य (होमवर्क) व प्रोजेक्ट वर्क देने के आदेश दिए हैं। वहीं, व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग सतर्कता बरत रहे हैं। कोई घर में मोबाइल जोन बनाकर, तो कोई खेल गतिविधियों में स्वयं शामिल होकर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कराने का काम कर रहा है।

जिलाधिकारी डा. राजा गणपति आर ने मोबाइल के उपयोग से बच्चों में हो रहीं समस्याओं को देखते हुए सार्थक पहल की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने से बच्चों में मानसिक व नेत्र की विकृतियां आ रही हैं। उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों को गृह कार्य व प्रोजेक्ट कार्य डायरी पर देने का आदेश दिया है। इसका कई विद्यालयों में अनुपालन भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ने आदेश का उल्लंघन करने पर विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

बच्चों को लगा चश्मा तब हुए सजगः नई बस्ती के शत्रुघ्न रस्तोगी के तीन बच्चे हैं। बच्चों के पास एक- एक, उनकी पत्नी के पास एक और दो मोबाइल सेट उनके पास यानी घर में कुल छह मोबाइल हैं। वह बताते हैं कि मोबाइल पर ज्यादा समय व्यतीत करने से दो बच्चों को चश्मा लग गया। इससे संभावित खतरों को लेकर सजग हो गया और घर में तीन वर्ष पहले मोबाइल जोन बना दिया। इसके तहत रात आठ बजे सबके मोबाइल जमा कराने के बाद स्विच्ड आफ कराकर एक टेबल पर रख दिए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 4.30 बजे जब वह टहलने के लिए निकलते हैं तब मोबाइल आन कर देते हैं। इस सतर्कता से अब बच्चों की आंखों से संबंधित समस्या में कमी आई है। इससे उनके घर में आपस में बातचीत का समय भी बढ़ गया है। (सीतापुर से जगदीप शुक्ल)

शहर के जीडी गोयनका स्कूल में होमवर्क नोट करते विद्यार्थी ● जागरण आर्काइव

बेटी के बदलते व्यवहार ने किया सचेत

रश्मि वर्मा लखनऊ पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। वह बताती हैं कि उनकी चार वर्ष की बेटी खाने-पीने के लिए मोबाइल की जिद करती थी। मना करने पर हाथ-पैर पटती थी। उसके व्यवहार में आ रहे बदलाव को महसूस किया और जब वह मोबाइल मांगती है तो उसके साथ खेलती हूं। अब धीरे-धीरे उसके स्क्रीन टाइम में कमी आई है। अभिभावकों को बच्चों की भावना को समझना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए।

हमारे विद्यालय में बच्चों के मोबाइल के प्रयोग पर मनाही है। होमवर्क या प्रोजेक्ट वर्क सिर्फ डायरी पर ही दिया जाता है। अखबार व पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही इससे जुड़ीं साप्ताहिक प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं।

नीरा मिश्रा, प्रधानाध्यापक, गुरुकुल विद्या पब्लिक स्कूल

बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए जिलाधिकारी ने विद्यालयों में मोबाइल पर गृह कार्य व प्रोजेक्ट वर्क नहीं देने के निर्देश दिए हैं। इसका अधिकांश विद्यालयों ने अनुपालन भी करा दिया है। बच्चों को डायरी पर गृह कार्य दिया जाने लगा है।

अखिलेश प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

बच्चों को मोबाइल के बजाय डायरी पर गृहकार्य व प्रोजेक्ट वर्क देने के आदेश के बाद घर के माहौल व बच्चों के व्यवहार में बदलाव आया है। मोबाइल पर होमवर्क मिलने पर बच्चे इसके बहाने काफी देर तक समय बिताते थे। मांगने पर जिद करते थे और वह चिड़चिड़े भी हो रहे थे। अब डायरी पर होमवर्क मिलने से उनका स्क्रीन टाइम काफी हद तक कम हुआ है।

नीरज गुप्ता, अभिभावक, आलमनगर

भोजशाला पर निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी मस्जिद कमेटी

- एआइएमपीएलबी ने कहा - ऐतिहासिक तथ्यों, आधिकारिक रिकार्ड, पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत है फैसला
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के विवादित परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है

नई दिल्ली, प्रेट्र : आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (एआइएमपीएलबी) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में आए फैसले को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने दावा किया कि यह फैसला ऐतिहासिक तथ्यों, आधिकारिक रिकार्ड और पुरातात्विक साक्ष्यों के विपरीत है। बोर्ड ने घोषणा की है कि मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, जिसमें बोर्ड पूरा कानूनी सहयोग देगा।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के इस विवादित परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के उस दशकों पुराने आदेश को रद कर दिया है, जिसके तहत मुस्लिमों को वहां जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत थी। एआइएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि यह फैसला 'प्लेसिस आफ वर्शिप एक्ट, 1991' (उपासना स्थल अधिनियम) की मूल भावना और संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैसले में सदियों पुराने मुस्लिम धार्मिक जुड़ाव और राजस्व रिकार्ड की अनदेखी की गई है।

बोर्ड के अनुसार, एएसआइ के अपने आधिकारिक रिकार्ड और साइनबोर्ड पर इस स्थल को हमेशा 'भोजशाला / कमाल मौला मस्जिद' के रूप में दर्शाया गया है, जो इसके साझा धार्मिक दर्जे को स्वीकार करता था।

साल 2003 की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति थी। इलियास ने कहा कि यह व्यवस्था दोनों समुदायों के दावों की एएसआइ द्वारा दी गई मान्यता थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर अपने ही पुराने रुख से यू-टर्न ले लिया है।

भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास, मंदिर की मान्यता पर भावुक दिखे श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार

- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भोजशाला को मंदिर मानने के निर्णय से धार में उत्साह का वातावरण
- शनिवार को श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, सत्याग्रह आंदोलन से जारी है परंपरा

बहुचर्चित भोजशाला परिसर में शनिवार का दिन लंबे समय बाद एक अलग ही भावनात्मक, धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण का साक्षी बना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मानते हुए शुक्रवार को दिए महत्वपूर्ण फैसले के अगले दिन सुबह से श्रद्धालुओं और भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का यहां पहुंचना शुरू हो गया। शाम तक परिसर के बाहर और भीतर लोगों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालु निर्धारित शुल्क (एक रुपया प्रति व्यक्ति) देकर परिसर में प्रवेश करते रहे और मां वाग्देवी की प्रतिमा के स्थान पर पहुंचकर श्रद्धा, आस्था और भावुकता के साथ नमन करते दिखाई दिए।

सुबह जैसे ही भोजशाला के द्वार खुले, वैसे ही परिसर के बाहर श्रद्धालुओं का उत्साह साफ दिखाई देने लगा। कई महिलाएं मां सरस्वती और भगवान हनुमान के चित्र लेकर पहुंची थीं लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सुरक्षाकर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। श्रद्धालुओं ने परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल, अभी तक भोजशाला में हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा की अनुमति थी।

संघर्ष की हर पीड़ा निर्णय के साथ सार्थक हो गई : मंदिर पक्ष में आए फैसले के बाद भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े बुजुर्ग कार्यकर्ताओं और हिंदू समाज के वरिष्ठ लोगों की आंखों में संतोष, भावुकता और वर्षों के संघर्ष के बाद विजय की खुशी एक साथ दिखाई दी। 90 वर्षीय हिंदू नेता विमल गोधा ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के कई दशक भोजशाला मुक्ति आंदोलन को समर्पित किए हैं। उन्होंने वह दौर भी देखा है, जब भोजशाला की बात उठाना ही संघर्ष माना जाता था। अब लगता है जैसे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प पूरा हो गया हो। आंदोलन से जुड़े रहे 75 वर्षीय सुरेशचंद्र भंडारी ने कहा कि यह आंदोलन सांस्कृतिक अस्मिता और इतिहास को बचाने की लड़ाई भी था।

धार। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद शनिवार को भोजशाला परिसर भक्तों की श्रद्धा, उत्साह और भावुकता से सराबोर नजर आया। हनुमान चालीसा का पाठ करते श्रद्धालु। नईदुनिया

निर्णय में हिंदू-जैन संबंधों का भी विशेष उल्लेख

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर।

- हाई कोर्ट ने कहा- दोनों परंपराओं के बीच सांस्कृतिक व धार्मिक समानताएं
- सरस्वती, अंबिका और जैन तीर्थंकरों के संदर्भों पर की विस्तार से टिप्पणी

धार भोजशाला मामले में शुक्रवार को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निर्णय में केवल पूजा अधिकार और ऐतिहासिक दावों पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि हिंदू और जैन परंपराओं के संबंधों पर भी विस्तार से टिप्पणियां की गईं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय परंपराओं में हिंदू और जैन आस्थाओं के बीच कई सांस्कृतिक व धार्मिक समानताएं दिखाई देती हैं। इसी कारण दोनों परंपराओं के मंदिरों में एक-दूसरे की प्रतिमाएं मिलना असामान्य नहीं माना जा सकता। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हिंदू और जैन दोनों परंपराओं में होती है। किसी हिंदू देवी प्रतिमा के साथ जैन तीर्थंकर या साधक की आकृति का मिलना स्वाभाविक माना जा सकता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में साझा प्रतीकों और सांस्कृतिक प्रभावों का इतिहास पुराना रहा है।

निर्णय में यह बात उस संदर्भ में लिखी गई है जब भोजशाला परिसर से जुड़ी प्रतिमाओं को लेकर हिंदू और जैन पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे थे। जैन पक्ष की ओर से कुछ प्रतिमाओं को अंबिका और जैन विद्या देवी स्वरूप बताया गया, जबकि हिंदू पक्ष ने उन्हें वाग्देवी का स्वरूप बताया। कोर्ट ने इस संदर्भ में ऋग्वेद में वर्णित मां सरस्वती के उल्लेख और प्रतिमा से जुड़े ऐतिहासिक अध्ययनों का भी हवाला दिया। इस मामले में एक याचिकाकर्ता सलेकचंद जैन ने भोजशाला को जैन गुरुकुल घोषित करने की मांग करते हुए पूजा की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने रतलाम के एक जैन मंदिर का उदाहरण भी दिया। वहां शिवलिंग और गणेश प्रतिमा भी स्थापित हैं। कोर्ट ने इसे साझा धार्मिक परंपराओं का उदाहरण बताया और कहा कि दोनों परंपराएं एक ही सर्वोच्च सत्ता की उपासना के भाव से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं।

जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राबर्ट वाड्रा को जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी राबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने वाड्रा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी है। वाड्रा कोर्ट द्वारा जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा रही है।

न्यायाधीश ने कहा कि मैं केवल जमानत दाखिल करने के लिए कह रहा हूं, कोई अन्य शर्त नहीं। ईडी ने इस मामले में राबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किए बिना ही अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी की ओर से वर्चुअल माध्यम से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है।

सौतेले पिता को अपना नहीं मान पाया बालक, फंदे पर लटककर दे दी जान

जागरण संवाददाता, मेरठ

- प्रियंका ने 16 साल पहले दान सिंह से किया था प्रेम विवाह, उसे छोड़कर मनीष से कर ली थी शादी
- इस रिश्ते को लेकर सहपाठियों ने भी की थी तल्ख टिप्पणी, इस कारण और बढ़ गया तनाव का स्तर

पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुआ मानसिक तनाव 13 साल के प्रिंस की जान का दुश्मन बन गया। मां ने पिता का साथ छोड़कर चार माह पहले किसी अन्य से शादी कर ली, लेकिन वह सौतेले पिता को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पुलिस के मुताबिक, सौतेला पिता अनुसूचित जाति से है। स्कूल में उसके सहपाठियों ने भी इस रिश्ते को लेकर कई बार टिप्पणी की थी। इससे उत्पन्न तनाव को बालक बर्दाश्त नहीं कर पाया और बुधवार शाम उसने फंदे से लटककर जान दे दी।

प्रियंका सिंह ने 16 साल पहले उत्तराखंड निवासी दान सिंह से प्रेम विवाह किया था। दान सिंह सिक्योरिटी गार्ड और प्रियंका एक शोरूम में काम करती है। प्रियंका के बेटे दीपेश की उम्र 15 और प्रिंस की उम्र 13 साल थी। प्रिंस कक्षा चार में पढ़ता था। बताते हैं कि प्रियंका ने दान सिंह से रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद उसकी मुलाकात चाय दुकानदार मनीष कुमार से हुई। प्रियंका ने चार महीने पहले मनीष से शादी कर ली थी। प्रियंका और उसके दोनों बच्चे मनीष के घर से अलग किराये के मकान में रहते थे। सीओ शुचिता सिंह के मुताबिक प्रियंका के दूसरी शादी करने के बाद दोनों बच्चे मानसिक तौर पर परेशान थे। मनीष को प्रिंस अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था।

प्रतीकात्मक

बांकेबिहारी मंदिर की दान पेटिका का बदला आकार

जागरण संवाददाता, वृंदावन : ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में ग्रीष्मकालीन फूल बंगला की व्यवस्था में परिवर्तन के बाद अब उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने मंदिर में लगी दान पेटिकाओं के आकार में बदलाव कर दिया है। छोटे आकार की स्टेनलेस की नई दान पेटिकाओं को रेलिंग के सहारे लगवाया जा रहा है। इससे श्रद्धालु रेलिंग से चलते हुए भी दान अर्पित कर सकते हैं। नई व्यवस्था से दान में मिलने वाली धनराशि बढ़ने की संभावना बताई जा रही है।

मंदिर में श्रद्धालुओं को दान अर्पित करने के लिए 18 दान पेटिका अलग-अलग स्थान पर लगाई गई थीं। साढ़े तीन फीट ऊंची और दो फीट चौड़ी इन दान पेटिकाओं में दान राशि डालने की जगह अंदर की ओर झुकी हुई थी। समिति के सामने यह जानकारी आई कि मंदिर सेवायतों के सेवादार इन पेटिका के ऊपर डलिया व अन्य सामान रख देते थे। इससे पेटिका में श्रद्धालु दान नहीं डाल पाते। सेवादार श्रद्धालुओं से राशि यह कहकर लेते थे कि वे पेटिका में डाल देंगे। बाद में वह धनराशि स्वयं रख लेते थे। इसके बाद समिति ने डिजायन में बदलाव का निर्णय लिया।

गुजरात के भावनगर में मेयर का कार्यकाल पूरा हुआ तो संभाली अपनी वेल्डिंग की दुकान

शत्रुघ्न शर्मा ● जागरण

अहमदाबाद : गुजरात के भावनगर में महापौर का कार्यकाल पूरा करने के बाद भरत भाई बारड अपनी वेल्डिंग की दुकान पर पहुंच गए और आज भी नियमित रूप से अपना यह काम करते हैं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि वार्ड सदस्य चुने जाने के बाद भी राजनेता सुख-सुविधा को महत्व देने लगते हैं लेकिन भावनगर के पूर्व महापौर भरत भाई एक ऐसे शख्स हैं जो आज भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पण और ईमानदारी के चलते लोगों के बीच लोकप्रिय हैं।

वर्ष 2024 से 2026 के बीच करीब ढाई वर्ष तक भावनगर के महापौर रहने के बावजूद आज भी वे किराए के मकान में रहते हैं, 10वीं तक पढ़ाई के बाद परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्होंने चार दशक पूर्व वेल्डिंग का काम शुरू किया था, मेयर का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने यह काम वापस संभाल लिया। उन्होंने बताया कि उनकी मां फूल माला बेचकर परिवार का गुजारा चलाती थी, उन्होंने हमेशा ईमानदारी व समर्पण भाव से लोगों की सेवा करने की नसीहत दी थी। वह आज भी उनकी इस नसीहत पर अमल करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं।

महापौर रहते उन्होंने कभी भी गलत काम कर पैसा कमाने की नहीं सोची। ईमानदारी वह समर्पण भाव से शहर के लोगों की सेवा की। भाजपा ने पार्टी के प्रति समर्पण भाव और उनकी निष्ठा को देखकर ही उन्हें महापौर का पद सौंपा था, पद के अनुकूल कार्य करने को ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी।

अपनी दुकान पर वेल्डिंग करते (बाएं) भावनगर के पूर्व महापौर भरत भाई बारड (दाएं)। इंटरनेट मीडिया

दैनिक जागरण

संकट की उपेक्षा करने से वह टल नहीं जाता

प्रधानमंत्री की चेतावनी

पांच देशों के अपने दौरे के तहत संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि यदि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से सुधार नहीं होता तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीब हो जाएगी। उन्होंने यह चेतावनी देते हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और उसके चलते होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से उपजे संकट का उल्लेख किया। उनका यह कहना भी सही है कि यह दशक आपदा का दिखता है, क्योंकि पहले कोविड महामारी ने विश्व को आर्थिक संकट में धकेला, फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव शुरू हो गया। इसके दुष्परिणामस्वरूप खाड़ी देशों से होर्मुज समुद्री मार्ग के जरिये होने वाली ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो गई। यह आपूर्ति अब तक बाधित है। इसके चलते पूरी दुनिया ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आने के कारण लगभग सभी देशों को पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पिछले दिनों भारत ने भी उनके दाम बढ़ाए। इसके आसार हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम फिर से बढ़ाने पड़ सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और महंगाई बढ़ती है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीबों पर पड़ता है।

एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात और कोई नहीं हो सकती कि उनमें से तमाम के सामने फिर से गरीब होने का संकट खड़ा हो गया है। यह खतरा केवल भारतीयों के सामने ही नहीं, अन्य विकासशील एवं निर्धन देशों के लोगों के सामने भी है। युद्धों से केवल ऊर्जा आपूर्ति ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ता है और इसके नतीजे में भी महंगाई बढ़ती है। इसमें संदेह है कि विश्व की एक बड़ी आबादी के समक्ष संकट बढ़ जाने के बाद भी शक्तिशाली देश जिम्मेदारी का परिचय देंगे और टकराव एवं तनाव कम करने के लिए सक्रिय होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय में अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति से तमाम देशों को तंग किया है। अब यह भी स्पष्ट है कि उसने नतीजों की परवाह किए बिना इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया। चूंकि इसका ठिकाना नहीं कि विश्व में स्थिरता और शांति कब आएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार ऐसी नीतियों पर ध्यान दे, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वास्तव में समर्थ बना सकें। कल्याणकारी नीतियां वोट के लिए नहीं, गरीब तबके को वास्तव में सबल बनाने के लिए चलाई जानी चाहिए।

सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं

झारखंड में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी को दी गई स्वीकृति एक सकारात्मक और दूरगामी कदम है। एमबीबीएस और पीजी की 250 नई सीटों के जुड़ने से राज्य के विद्यार्थियों को अपने ही प्रदेश में बेहतर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अब तक सीमित सीटों के कारण अनेक छात्रों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। मेडिकल सीटों में वृद्धि का सीधा लाभ स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा। अधिक डाक्टर तैयार होने से अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर होगी और ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर इलाज पहुंच सकेगा। झारखंड में बंगाल और बिहार से भी मरीज आते हैं। रिम्स और देवघर एम्स जैसे संस्थानों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के विस्तार की आवश्यकता और बढ़ जाती है। सरकार को केवल सीटें बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेडिकल कालेजों में आधुनिक सुविधाएं, पर्याप्त शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होगा। निजी मेडिकल संस्थानों की ऊंची फीस मध्यम वर्ग के लिए चुनौती है, इसलिए सरकारी चिकित्सा शिक्षा को मजबूत बनाना समय की मांग है। यदि राज्य सरकार त्वरित और गंभीर पहल करे, तो झारखंड चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई पहचान बना सकता है।

> मेडिकल की सीटें बढ़ाने की स्वीकृति से शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी लाभ होगा

विदेशी मुद्रा बचाने की चुनौती

संजय गुप्त

सरकारी तंत्र को यह समझना होगा कि जाम से मुक्ति पाकर अरबों रुपये का ईंधन बचाया जा सकता हैं। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी

अवधेश राजपूत

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण ढाई माह से होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित होने से विश्व में गैस और तेल का जो संकट खड़ा हुआ, वह अब तक जारी है। इसका प्रभाव भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ा है। भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट से बड़े पैमाने पर तेल और गैस की आपूर्ति होती थी। पिछले ढाई माह से इस आपूर्ति में खासी कमी आई है। जैसे-तैसे तेल और गैस से लैस कुछ जहाज होर्मुज स्ट्रेट से निकलकर भारत आ पा रहे हैं। यह अलग बात है कि अभी तक भारत में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कोई गंभीर संकट खड़ा नहीं हुआ। भारत सरकार की इसके लिए सराहना करनी होगी कि उसने तेल-गैस की जो वैश्विक चुनौती खड़ी हुई, उसका सामना बखूबी किया। जब तमाम देशों ने पेट्रोल और डीजल के दाम होर्मुज स्ट्रेट बाधित होने के चंद दिनों बाद ही बढ़ा दिए थे, तब भारत ने करीब 75 दिन बाद बढ़ाए और वह भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा था। विश्व में जब भी किसी वस्तु की किल्लत होती है तो उसकी कीमतें बढ़ती ही हैं। यदि पश्चिम एशिया संकट सुलझा नहीं तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे आयात बिल बढ़ेगा। इसे देखते हुए ही पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल की बचत करें, विदेश यात्राएं कम करें, वर्क फ्राम होम काम करें और कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदें।

सब जानते हैं कि आम भारतीय सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। इस समय विश्व के किसी देश में लोगों के पास सबसे अधिक सोना है तो वह भारतीयों के पास है। लगभग 40 हजार टन सोना भारतीय घरों में है। चूंकि भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, लिहाजा उसका आयात होता है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 72 अरब डालर का सोना खरीदा। डालर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से सोने के आयात में विदेशी मुद्रा की खपत अधिक हो रही है। बहुत कम भारतीयों की ओर से अपने सोने को गिरवी रखकर बैंकों से पैसा लेने के कारण यह एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में ही पड़ा रहता है। भारतीयों में सोना खरीदने की ललक के पीछे यह माना जाता है कि उनका बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार पर अधिक भरोसा नहीं। कई लोग अपनी दो नंबर की कमाई सोने में खपाते हैं। चूंकि भारत में आम जन का सोने के प्रति विशेष मोह है, इसलिए सरकार को बैंकिंग व्यवस्था और शेयर बाजार में निवेश को लेकर लोगों के भरोसे की कमी के कारणों पर सोचना चाहिए।

विदेशी मुद्रा की सबसे अधिक खपत पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में होती है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ना है, लेकिन तथ्य यह भी है कि भारत में शायद वाहनों का माइलेज सबसे कम होगा। एक लीटर पेट्रोल या डीजल में भारतीय वाहन सबसे कम सफर कर पाते हैं। इसका कारण हमारी सड़कों का आधारभूत ढांचा कमजोर होना और उनके निर्माण की खराब डिजाइनिंग है। रही-सही कसर सड़कों पर अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से पूरी हो जाती है। अक्सर टोल-नाकों पर भी जाम लगता है। इस सबके चलते लाखों लीटर पेट्रोलियम उत्पादों की बर्बादी होती है। ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता, जिनके चलते जाम लगता है अथवा वाहन धीमी गति से चल पाते हैं, लेकिन इसके लिए जैसी राजनीतिक और सामाजिक इच्छाशक्ति चाहिए, उसका घोर अभाव ही दिखता है। बड़े शहरों की बात तो दूर, अब छोटे-छोटे शहरों में भी जाम लगता है और कभी-कभी तो घंटों तक, लेकिन इसकी चिंता न तो केंद्र सरकार करती है, न राज्य सरकारें और और न ही उनके स्थानीय निकाय।

प्रधानमंत्री की अपील पर कई नेताओं ने अपनी कारों का काफिला छोटा किया है या फिर मोटरसाइकिल, मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे कदम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तो ठीक हैं, पर ईंधन की खपत में कोई ठोस कमी तो जाम की समस्या के समाधान से ही होगी। हाल में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यदि दिल्ली में एमसीडी के टोल नाकों को पूरी तरह इलेक्ट्रानिक कर दिया जाए तो इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि जाम से छुटकारे के चलते ईंधन की बचत भी होगी। दिल्ली की तरह देश के दूसरे शहरों में न जाने कितने ऐसे टोल नाके और ट्रैफिक बाधित करने वाले चौक पाइंट होंगे, जहां अरबों रुपये का ईंधन बर्बाद होता है। सरकारी विभागों को यह समझना होगा कि जाम से मुक्ति पाकर अरबों रुपये का ईंधन बचाया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। चूंकि अपने देश में सड़कों पर अतिक्रमण आम है, इसलिए जाम लगता है और जब जाम लगता है तो ईंधन की बर्बादी होती है। सड़कों पर अतिक्रमण करना अपने यहां एक सामाजिक समस्या बन गई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भी राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है। हमारी नौकरशाही समस्याओं के समाधान के दीर्घकालिक उपायों पर गंभीरता से कम ही विचार करती है।

भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है, आर्थिक संपन्नता के मामले में जिसकी तुलना कई यूरोपीय देशों से की जा सकती है। आज यह समर्थ आबादी शायद ही मितव्ययिता का परिचय दे पाए। बेहतर होगा सरकार इस बारे में सोचे कि कैसे ऐसे विकल्प तैयार हों, जिससे यह तबका विदेशी मुद्रा की बचत कर सके। तभी शायद वह इस तोहमत से बच सकेगा कि वह अनावश्यक खर्चे करता है। तमाम भारतीय घूमने या खरीदारी के लिए विदेश जाते हैं। इसमें अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके अतिरिक्त देश में इलेक्ट्रानिक्स और अन्य आयातित वस्तुओं की खरीद भी खूब होती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि देश में भारतीयों की जरूरत की तमाम वस्तुएं निर्मित नहीं होतीं या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। जब तक आयातित सामग्री के बेहतर विकल्प नहीं होंगे, तब तक समाज का आभिजात्य वर्ग विदेशी मुद्रा खर्च पर नियंत्रण में सहयोग नहीं दे पाएगा। चूंकि तत्काल कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सरकार को अभी से ऐसे दूरगामी उपाय करने चाहिए, जिससे भविष्य में अभिजात्य भारतीय पर्यटन, खरीदारी, शादी-ब्याह के लिए विदेश जाने की जरूरत न समझें।

response@jagran.com

त्याग पथ पर चलते मंत्री महोदय

हास्य-व्यंग्य

मंत्री जी सड़क पर सरपट दौड़े जा रहे थे। तीन-चार अधिकारी छाता लिए उनके पीछे-पीछे भाग रहे थे। सूरज सिर पर चमक रहा था, मगर मंत्री जी की चमक के आगे वह भी पस्त दिखाई दिया। भोलू यह सब देखकर भौंचक्का था। उसने अपनी जिंदगी में देवताओं को कभी धरती पर उतरते नहीं देखा था। आज यह सब देखकर उसकी आंखें फटी जा रही थीं। उसकी आंखें भर आईं। यहां तक कि सड़क का तारकोल भी मारे शर्म के पिघला जा रहा था। सड़क के गड्ढे गर्व से भरे जा रहे थे। भोलू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, वह सोच में पड़ गया। इतने घाम और ताप में सरकार उसकी ही सुध लेने सड़क पर निकले हैं। उसके भीतर भावनाओं का ज्वार उठ गया।

इस सबसे अनजान मंत्री जी ठीक उस कोण पर अपने कदमों को गति दे रहे थे, जहां से कैमरे में केवल वही दिखें, उनका काफिला नहीं। हालांकि अभी तक उनकी एक भी 'रील' नहीं बन पाई थी। ब्रेक लेते ही मैंने झट से अपना माइक उनके आगे कर दिया। वे देशहित में पसीने-पसीने हो चुके थे। 'बाइट' देने से पहले फुसफुसाए, 'मीडिया कभी पाजिटिव खबरें नहीं दिखाता। उसे यह समझना चाहिए कि जनता की सेवा करना कोई हंसी-ठट्ठा नहीं है। पहले केवल काम करना पड़ता था, अब काम से ज्यादा रील बनाना जरूरी है। इसकी 'रीच' सीधे 'जेन-जी' तक पहुंचती है। उसका टारगेट अब रोजगार नहीं रील है। इसलिए हमारी सरकार भी इस पर जोर दे रही है। चलिए, आपको जिस काम के लिए बुलाया गया है, उसे संपन्न कीजिए।'

संतोष त्रिवेदी

चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन क्षेत्र का त्याग ही पर्याप्त नहीं था, सो मंत्री जी ने काफिला भी त्याग दिया

मैंने रिकार्डर आन कर दिया। सबसे पहले भोलू को फ्रेम से बाहर किया। उसकी कहीं जगह नहीं बन रही थी। लंबे फोकस में मंत्री जी उभर के आ रहे थे। पसीने की मात्रा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए चेहरे पर इत्र की बूंदें चमक रही थीं। मेरा पहला सवाल यही था, 'मंत्री जी, आपको इतनी कड़कती धूप में पैदल क्यों उतरना पड़ा? जनता बेचैन है।' मंत्री जी ने चेहरे पर उतर आई इत्र की बूंदों को पोछते हुए गंभीर मुद्रा ओढ़कर बोला, 'जनता की परेशानी दूर करने के लिए ही मैं हूं। देश इस समय संकट से गुजर रहा है। मैंने पैदल चलने की शुरुआत कर दी है। अब जनता का दायित्व है कि वह इस अभियान को आगे बढ़ाए। जो सुविधाएं जनता भोग रही हैं, जल्द देशहित में उनका त्याग कर दे। मैंने तो सिर्फ त्याग सीखा है। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र का त्याग करना पर्याप्त नहीं था, सो अब अपना काफिला भी त्याग रहा हूं।'

'मगर कुछ मंत्री मेट्रो, बस, रिक्शा और साइकिल से चल रहे हैं और आप पैदल! इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?' मैंने सवाल पूछ लिया। मंत्री जी पहले से तैयार थे। उन्होंने जूते उतारते हुए उत्तर दिया, 'मुझे अपनी मिट्टी बड़ी प्यारी है। इसकी असली सुगंध तभी मिलती है, जब इसके करीब आया जाए। मेट्रो, बस, रिक्शा आदि सामान्य प्रयोग हैं। इनमें फिर भी ऊर्जा क्षय होती है। मैंने अपने श्रम का आश्रय लिया है। हमारा किसान,मजदूर और युवा आज इसी के भरोसे है। इसलिए मुझे सड़क पर उतरना पड़ा।' 'जनता के लिए आपका संदेश?' मैंने समापन करते हुए पूछा। 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है' कहते हुए मंत्री जी अपने काफिले की ओर लौट गए। इंटरनेट मीडिया में अगले ही पल मंत्री जी वायरल हो गए। जिस भोलू को मैंने फ्रेम से बाहर किया था, फिलहाल उसकी कोई खबर नहीं है।

response@jagran.com

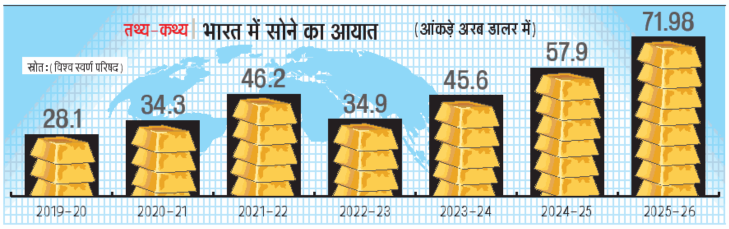

ऊर्जा

आसक्ति और भक्ति

दो अस्मिताओं के बीच कदाचित ऐसा गहन, अटूट, अत्यंत सौहार्दपूर्ण तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि अन्य सभी अभिलाषाएं, सरोकार गौण हो जाते हैं। यह दैविक संयोग है। इस संबंध में दूसरा पक्ष ईश्वर, कोई परालौकिक शक्ति, जीव या स्थान भी हो सकता है। आसक्ति और भक्ति में विभेद समझना आवश्यक है। विभिन्न प्राथमिकताओं के कारण स्वजन से अत्यधिक लगाव यानी आसक्ति की परिणति व्यक्ति के दीर्घकालिक हित में नहीं रहती, बल्कि आध्यात्मिक विकास में बाधक हो सकती है। जीवनसाथी, संतान या प्रियजन के उचित मार्ग से विचलित होने पर प्रायः प्रेमवश दृढ़ता से प्रतिरोध नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप कर्ता को अंततः हानि पहुंचती है। कोई तो प्रियजन के न रहने पर नैराश्य से कदापि उबर नहीं पाता। ममता, वात्सल्य, मैत्री या संतति से अगाध प्रेम किसी भी पक्ष के उन्नयन में सहायक नहीं रहता। संतति का मोह अनेक वरिष्ठजनों एवं वृद्धों के संताप का कारण बन रहा है। आसक्तिपूर्ण संबंधों के मूल में प्रायः स्वार्थ, संशय, भय या आशंकाएं मिलेंगी।

इसके विपरीत भक्ति की आधारशिला आस्था है। आराध्य से जुड़ाव के लिए भक्त अधीर या उद्विग्न नहीं होता। उसे ईश्वरीय योजनाओं को लेकर कोई शंका नहीं होती, चूंकि वह आश्वस्त रहता है कि ईश्वर उसके हैं। उसे यह भी ज्ञान रहता है कि समस्त चराचर जगत के संचालक केवल उसी के नहीं, बल्कि उनके अनेक दायित्व हैं। वे उन सभी के हैं, जो निःस्वार्थ, शुद्ध और परहित भाव से ईश्वरीय विधान के अनुरूप कार्यरत हैं। अतः वह ईश्वर पर एकाधिकार की चेष्टा नहीं करेगा। इनसे ऊपर, सच्चे भक्त को अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्टि नहीं होती, जिस स्थिति-परिस्थिति में प्रभु उसे प्रदान करते हैं, वह उसे स्वीकार्य होती है। यही स्वीकार्यता जीवन की सुगमता बढ़ाती है।

हरीश बड़थ्वाल

हर वायरस में कोविड देखना गलत

मुकुल व्यास

> **एंडीज वायरस को नियंत्रण में रखना जरूरी हैं, लेकिन यह कोविड की तरह महामारी का खतरा नहीं हैं**

पिछले दिनों एक क्रूज जहाज पर कुछ यात्रियों के हंता वायरस से संक्रमित होने की खबर ने कोविड के दिनों की याद ताजा कर दी। मार्च 2020 में एक क्रूज जहाज रूबी प्रिंसेस के सिडनी में डाक होने के बाद कोविड फैल गया था। जहाज से उतरे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 575 लोग कोविड से संक्रमित थे। इसके बाद यह वायरस और दूसरे लोगों में भी फैल गया। अतः अब एमवी होंडियस जहाज पर हंता वायरस की मौजूदगी पर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तत्काल सावधानी बरतना और क्वारंटीन जैसे कदम उठाना स्वाभाविक था। होंडियस के यात्री एंडीज वायरस के संपर्क में आए, जो कि एक प्रकार का हंता वायरस है, जो चूहों से फैलता है।

हंता वायरस एक ऐसा वायरस समूह है, जो आमतौर पर चूहों, गिलहरियों और चूहों जैसी अन्य प्रजातियों (रोडेंट) द्वारा फैलाया जाता है। लोग अक्सर तब संक्रमित होते हैं जब वे संक्रमित चूहों के मूत्र, मल या लार के छोटे-छोटे कणों को सांस के जरिये अपने शरीर में ले लेते हैं। ज्यादातर हंता वायरस के बारे में यह नहीं मालूम है कि वे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं या नहीं, लेकिन एंडीज वायरस इसका अपवाद है। संक्रमित चूहों से इंसानों में फैलने के बाद यह एकमात्र ऐसा हंता वायरस है जिसके एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के पुष्ट प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोगों के बीच आसानी से फैल जाता है। यह तब हो सकता है जब लोग एक-दूसरे के बहुत करीब हों।

यह कोविड फैलाने वाले सार्स-कोव-2 वायरस से बिल्कुल अलग है। सार्स-कोव-2 हवा के जरिये बहुत तेजी से फैलता है। लोग बीमार होने का अहसास होने से पहले ही दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। शुरुआती अनुमानों से पता चला था कि सार्स-कोव-2 से संक्रमित हर व्यक्ति औसतन लगभग दो या उससे ज्यादा लोगों में वायरस फैलाता था, जिनका पहले कभी इस वायरस से सामना नहीं हुआ था। एंडीज वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास स्थितियों का एक साथ होना जरूरी है। जैसे भीड़भाड़ वाली, खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर संक्रमित लोगों का लंबे समय तक एक-दूसरे के बहुत करीब रहना। एमवी होंडियस जहाज पर ठीक ऐसा ही हुआ। एंडीज वायरस के लिए कोई खास दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वायरस के फैलने की खबर मिलते ही विज्ञानी सक्रिय हो गए। स्विट्जरलैंड की प्रयोगशालाओं ने एक मरीज से मिले वायरस के पूरे जेनेटिक कोड का अनुक्रमण करके उसे कुछ ही दिनों के भीतर सार्वजनिक कर दिया। एंडीज वायरस को नियंत्रण में रखना जरूरी है, लेकिन यह कोविड की तरह महामारी का खतरा नहीं है। हर वायरस संक्रमण में कोविड देखने की प्रवृत्ति गलत है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

रंग में भंग

नीट पेपर लीक ने न केवल लाखों छात्रों का बड़ा नुकसान किया, बल्कि बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली जीत से उत्साहित भाजपा के राजनीतिक उत्साह को भी फीका कर दिया। जिस समय असम में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ठीक उसी समय नीट परीक्षा रद किए जाने की खबर सामने आ गई। इसके बाद टीवी चैनलों पर असम में सरकार गठन का सीधा प्रसारण पीछे छूट गया और उसकी जगह नीट-यूजी परीक्षा रद होने की खबर ने ले ली। चर्चा यह भी रही कि इस मामले में शिक्षा मंत्रालय और एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात पर फटकार लगाई गई कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही परीक्षा रद करने की जानकारी सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी। यह घोषणा एक-दो घंटे बाद भी की जा सकती थी। मगर तब तक जीत के उत्साह पर नीट पेपर लीक का साया पड़ चुका था।

राजरंग

रूसी पिस्तौल

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की छवि वैश्विक स्तर पर एक बेहद सौम्य और संतुलित नेता की है, और वे हैं भी ऐसे। वह अपनी बात बहुत सहजता से रखते हैं, लेकिन रूस के हितों से जुड़े मुद्दों पर इंच भर भी पीछे नहीं हटते। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक दिलचस्प घटना हुई। एक पत्रकार का फोन बार-बार बजने लगा, जिस पर लावरोव ने हल्के व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि 'अगर अगली बार आपका फोन बजा, तो हमारे सुरक्षाकर्मी पिस्तौल निकाल लेंगे।' इस पर वहां मौजूद लोगों ने ठहाके लगाए, लेकिन माहौल कुछ देर के लिए गंभीर भी हो गया। पता चला कि ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरान और यूएई के विदेश मंत्रियों के बीच तीखी बहस हो गई थी, जिसमें बीच-बचाव करने की तनावपूर्ण जिम्मेदारी लावरोव ने भी निभाई थी। वह कभी ईरान को समझा रहे थे, तो कभी यूएई को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। जब वह प्रेस कांफ्रेंस में पहुंचे, तब पहले से ही तनाव में थे। रही-सही कसर उस अनचाहे फोन काल ने पूरी कर दी।

आपदा या 'इवेंट'

पश्चिम एशिया का युद्ध ईंधन संकट के लिहाज से वैश्विक आपदा का रूप ले चुका है। इसी कारण पीएम नरेन्द्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की है, जिसे लोगों और संस्थानों ने गंभीरता से लिया भी है, लेकिन नेताओं और अफसरों ने इस आपदा को भी एक इवेंट में बदल दिया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े एक केंद्रीय मंत्री एक दिन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल से पहुंचे। इसके पहले मीडिया को संदेश भेजा गया- 'प्लीज कवर दिस इवेंट।' प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। केवल एक मंत्री ही नहीं, बल्कि अखबारों के पन्ने और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म नेताओं और अफसरों की इस कथित 'त्याग भावना' के प्रदर्शन से भरे पड़े हैं। कोई ई-रिक्शा से यात्रा कर रहा है, तो कोई साइकिल चलाकर संदेश देने का प्रयास कर रहा है। सवाल यह है कि मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी आखिर कितने दिन बिना लग्जरी कारों के चल पाएंगे?

कहीं खुशी कहीं गम

केरल में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया भले ही लंबी चली, मगर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी हाईकमान के निर्णय को सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि केरल चुनाव के बाद एआइसीसी में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे कई नेताओं को इस फैसले ने मायूस कर दिया है। इसकी वजह यह है कि सतीशन को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की केरल की राजनीति में वापसी फिलहाल टल गई है। सात वर्षों से अधिक समय से एआइसीसी में राहुल गांधी के सबसे विश्वासपात्र नेताओं में शामिल केसी वेणुगोपाल के साथ तालमेल बिठाना कई नेताओं के लिए सहज नहीं रहा है। विशेषकर उत्तर भारत के पार्टी नेताओं को उम्मीद थी कि केसी वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और उनकी जगह कोई हिंदी भाषी नेता नया संगठन महासचिव बनेगा। मगर मौजूदा परिस्थितियों में केरल लौटना तो दूर, केसी वेणुगोपाल अभी दिल्ली की राजनीति में लंबी पारी खेलते दिखाई दे रहे हैं।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

आजकल

इतिहास लेखन बाधित करता स्लीपर सेल

भारतीय राजनीति में इतिहास पर निरंतर चर्चा होती रहती है। किसी अन्य दल पर दोषारोपण के लिए नेता अक्सर इतिहास से ही तथ्यों का सहारा लेते हैं। परंतु ऐसे में यदि इतिहास लेखन सही से नहीं किया गया हो, तो उसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध कही जा सकती है। केंद्र में वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी की सरकार गठन के बाद से इतिहास लेखन की भारतीय दृष्टि को अपनाने और उसे स्थान देने की चर्चा तो हो रही है, परंतु उसके उद्देश्य को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। लिहाजा इसकी राह में आ रही बाधाओं की भी पहचान की जानी चाहिए

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के जिम्मे है देश का इतिहास लेखन कार्य।

इतिहास एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा भारतीय राजनीति में निरंतर होती रहती है। भारत में राजनीतिक दल हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण करने में अब तक लिखे इतिहास का सहारा लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय इतिहास को समग्रता में देखे जाने और लिखने की बात प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई बार कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ वर्षों पहले काशी की एक गोष्ठी में कहा था कि इतिहास लेखन में दूसरे की गलतियों को रेखांकित करने से बेहतर होगा कि अपनी लकीर लंबी की जाए। कहना न होगा कि देश का शीर्ष नेतृत्व भारतीय इतिहास को समग्रता में लिखे जाने और देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करता है। वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से वामपंथी इतिहास लेखन की जगह भारतीय दृष्टि से इतिहास लेखन की बात की जाने लगी थी। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लगभग चार वर्ष बाद 2018 में भारत के समग्र इतिहास लेखन का सोच भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च-आइसीएचआर) में आया। चार वर्षों तक वहां इस पर मंथन होता रहा।

वर्ष 2022 में भारत के समग्र इतिहास की योजना पर कार्य आरंभ हुआ। उस समय के समाचार पत्रों में आइसीएचआर के चेयरमैन राघवेन्द्र तंवर के हवाले से ये बातें प्रकाशित हैं कि आइसीएचआर भारत के समग्र इतिहास के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वामपंथी इतिहासकारों ने इसको इतिहास के पुनर्लेखन से जोड़कर इसकी आलोचना आरंभ कर दी। एक वामपंथी सांसद ने 2022 के दिसंबर में संसद में इस पर प्रश्न भी उठाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उस प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया था कि इतिहास का पुनर्लेखन नहीं किया जा रहा है। आइसीएचआर ने भारत के समग्र इतिहास लेखन पर एक प्रोजेक्ट आरंभ किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पर प्रश्न उठाया था।

प्रश्न यह नहीं है कि इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है या इतिहास लेखन के एकांगी प्रविधि से उत्पन्न रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इतिहास लिखा जा रहा है। आइसीएचआर ने 2018 में जो सोचा, वह आठ वर्षों बाद भी भौतिक रूप से आकार नहीं ले सका है। अब तक भारत के समग्र इतिहास का एक भी खंड प्रकाशित नहीं हो पाया है। जबकि इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए इतिहासकार सुष्मिता पांडे की नियुक्ति संपादक के पद पर की गई थी। उनके साथ प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी से नरेन्द्र शुक्ल को प्रतिनियुक्ति पर लाकर इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। दो और युवा विद्वानों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था। नरेन्द्र शुक्ल वापस जा चुके हैं। कहना न होगा कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के वेतन आदि का खर्च तो आइसीएचआर उठा ही रहा है। इस बीच आइसीएचआर के सदस्य सचिव रहे उमेश कदम पर 2022 में गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे। वह यहां से कार्यमुक्त हो गए। भारत के समग्र इतिहास के पहले खंड पर कार्य आरंभ हो चुका था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि उमेश कदम ने पदमुक्त होने के बाद पत्र लिखकर आइसीएचआर को अपने लिखित कार्यों के उपयोग से रोक दिया था। पहले खंड के लिए उन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर लिखा था। उसकी जगह नए व्यक्ति की खोज करना और लिखवाने में समय लगा, बताया गया। इस बात को भी चार वर्ष बीत गए। अभी तक पहला खंड नहीं आ पाना आइसीएचआर की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। प्रभारी सचिव ओमजी उपाध्याय को आशा है कि जल्द पहला खंड प्रकाशित होगा। यह मान भी लिया जाए कि 2022 में यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा और पहला खंड 2026 में आ जाएगा तो इस हिसाब से तो आठ खंड को प्रकाशित होने में 32 वर्ष लगेंगे।

इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत का समग्र इतिहास का पहला खंड परिचयात्मक होगा। इस खंड में भारत के समग्र इतिहास लेखन की आवश्यकता को स्थापित किया जाएगा। इस बात की चर्चा होगी कि भारत के इतिहास लेखन का आधार भू-राजनीतिक न होकर भू-सांस्कृतिक होगा। पहला खंड दो-ढाई सौ पृष्ठों का होना था। बढ़ते बढ़ते वह लगभग 1,100 पृष्ठों का हो गया। इसके प्रकाशन के बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि 1,100 पन्नों के पहले खंड को तीन विशेषज्ञों के पास भेजा गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वो इसका मूल्यांकन करके अपनी राय दें। विशेषज्ञों के लिखे हुए को विशेषज्ञों से मूल्यांकन करवाने की क्या आवश्यकता है। क्या आइसीएचआर को इस प्रोजेक्ट से जुड़े विशेषज्ञों पर भरोसा नहीं है। इस प्रोजेक्ट की संपादक सुष्मिता पांडे विदुषी हैं। आइसीएचआर के अध्यक्ष राघवेन्द्र तंवर स्वयं विद्वान इतिहासकार हैं। ऐसे में मूल्यांकन के लिए बाहर के विद्वानों के पास भेजने की आवश्यकता क्यों? इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि अगर पहला खंड परिचयात्मक और इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता बताने वाला है तो 1,100 पृष्ठों का भारी भरकम खंड क्यों? क्या ये खंड दो-ढाई सौ पृष्ठों का नहीं होना चाहिए जो पहले तय किया गया था। तय तो यह भी किया जाना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा? क्या अनंत काल तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जाना उचित रहेगा? क्या आइसीएचआर इसको निश्चित समय सीमा में पूरा नहीं कर सकता है। बहुत संभव है कि आइसीएचआर में अब भी वामपंथियों के स्लीपर सेल सक्रिय हों और इस प्रोजेक्ट को अपने आकाओं के कहने पर लटकाने का उपक्रम कर रहे हों। आइसीएचआर में गड़बड़ियों का समाचार भी आता रहता है। चाहे वह 'मदर आफ डेमोक्रेसी' पुस्तक का प्रकाशन हो या सुभाषचंद्र बोस नाम की पुस्तक का गलत शीर्षक प्रकाशन का मसला हो।

दरअसल आइसीएचआर की समस्या बौद्धिक कम प्रशासनिक अधिक प्रतीत होती है। वर्ष 2022 में उमेश कदम के पद छोड़ने के बाद से वहां स्थायी सदस्य सचिव नहीं हैं। पिछले वर्ष मई में अल्केश चतुर्वेदी को मंत्रालय ने सदस्य सचिव नियुक्त किया, लेकिन वह इस पद पर अपना योगदान नहीं दे सके। कारण मंत्रालय और आइसीएचआर बेहतर बता सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व फिर से सदस्य सचिव पद के लिए इंटरव्यू हुआ। पैनल तय करके नाम मंत्रालय भेज दिए गए, लेकिन अब तक किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी। अब तो यह भी संदेह होता है कि आइसीएचआर के उच्च पदों पर बैठे लोग ही नहीं चाहते हैं कि वहां सदस्य सचिव के पद पर कोई स्थायी नियुक्ति हो। अगर सदस्य सचिव आ जाते हैं तो वह संस्था को चलाएंगे, इससे यथास्थितिवादियों को परेशानी हो सकती है। लेकिन चार वर्षों से इतनी महत्वपूर्ण संस्था में सदस्य सचिव का नहीं होना शिक्षा मंत्रालय के निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न खड़े करता है। आइसीएचआर ऐसी संस्था है जिसकी सक्रियता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों को उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बशर्ते कि सक्रिय हो।

खरी खरी

देश में खेल-तेल का झमेला

राजेंद्र कुमार सिंह

आज देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी इसके अच्छे दिन थे। यह मस्ती में इठलाता हुआ कुलांचे भर रहा था और विश्व की सफलता की ऊंची चोटियों को छूने का प्रयास कर रहा था। लेकिन न जाने किसकी नजर लगी कि इसके सारे अरमान धराशायी हो गए। जो उत्साह कभी उमंग बनकर छलकता था, वह अचानक आह में बदल गया। जिस खेल में देश स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहा था, आज उसी का तेल निकल गया।

अभी महज कुछ माह पहले तक कहां हम फाइव ट्रिलियन डालर इकोनमी बनने के लिए हम यत्र-तत्र-सर्वत्र खर्च को अंजाम दे रहे थे, जबकि आज स्थिति यह है कि खाने और दौड़ाने-दोनों में इस्तेमाल होने वाले तेल पर रोक-टोक की नौबत आ गई है। देश मानो इस समय बीमारी की अवस्था से गुजर रहा है। इसलिए, हे देशवासियों! खाने और गाड़ियों में उपयोग होने वाले तेल के अत्यधिक प्रयोग से बचना समय की मांग है। जैसे किसी बीमारी में परहेज जरूरी होता है, वैसे ही इस संकट से उबरने के लिए संयम आवश्यक है।

यदि लोग थोड़ी सावधानी बरतें और जरूरत से ज्यादा उपभोग न करें, तो काफी बचत संभव है। आजकल कई घरों में दो-तीन प्रकार के तले-भुने व्यंजन बनाने की आदत-सी हो गई है। इस प्रवृत्ति पर लगाम लगानी होगी। कम तेल का उपयोग न केवल देशहित में है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अधिक तेल का सेवन दिल को फ्यूज कर सकता है और फिर आदमी स्वयं 'ब्रेकिंग न्यूज' बन जाता है।

यदि हम सीमित दायरे में रहकर संसाधनों का उपयोग करें, तो देश को इस संकट से बाहर निकाला जा सकता है। खपत कम होगी तो जो देश आज लाचार और बीमार-सा दिखाई पड़ रहा है, वही फिर से स्वस्थ होकर दहाड़ेगा। जैसे सूर्यग्रहण या चंद्रग्रहण के समय लोग छोटे-छोटे उपाय करते हैं, वैसे ही आज देश को भी सामूहिक सहयोग और संयम की जरूरत है।

हम सबको मिलकर देश की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसे तमाशा बनाने के बजाय समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और देशहित में सकारात्मक सोच के साथ आगे आएंगे।

यदि आप सरकारी या निजी नौकरी में हैं, तो कोशिश करें कि सामूहिक रूप से एक ही वाहन से कार्यालय जाएं। जहां 'वर्क फ्राम होम' की संभावना हो, वहां उसे प्राथमिकता देना देशहित में बेहतर कदम हो सकता है। कोरोना काल में हमने आनलाइन कार्यों की उपयोगिता देखी ही है। यदि हम समझदारी और कल्पनाशीलता के साथ कदम बढ़ाएं, तो देश पर आए इस संकट को दूर कर सकते हैं। विकास का जो पहिया डगमगा गया है, उसे फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।

वाहनों का उपयोग तभी करें जब अत्यंत आवश्यक हो। अन्यथा साइकिल का प्रयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण-दोनों के लिए लाभकारी है। यदि यात्रा टाली जा सकती हो, तो उसे टालने का प्रयास करें। विशेषकर ऐसे समय में विदेश यात्राओं से बचना चाहिए। नेताओं को भी फिलहाल विदेश यात्राओं से परहेज करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग अभी विदेश दौरे पर हैं, शायद उनके लिए यह आवश्यक रहा होगा।

अंततः, देश हम सबका है। यदि हम थोड़े संयम, समझदारी और सहयोग की भावना से काम लें, तो हर संकट का समाधान संभव है। लेकिन कुछ लोग कहें कि यह सब आसान नहीं है।

(लेखक व्यंग्यकार हैं)

पोस्ट

जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की पेशकश की है!
पल्लवी घोष@_pallavighosh

केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो इस साल सितंबर तक जारी रहेगा। चीनी महंगी होने से रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। पिछले साल चीनी उत्पादन कम हुआ था तो इस साल मानसून को लेकर अनुमान अच्छा नहीं है।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

नेताओं के काफिले बड़े होने के दो कारण होते हैं- सुरक्षा या भौकाल। सुरक्षा तो सर्वोपरि है, जिस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पर भौकाली नेताओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा भी जांच-परख कर ही दी जानी चाहिए। सुरक्षा देना किसी को उपकृत करने का माध्यम न बने।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस विशेष विमान के बजाय सामान्य उड़ान में पुणे से बेंगलुरु गए। वित्तीय अनुशासन और दक्षता पर जोर के इस दौर में उन्होंने मितव्ययिता का बड़ा संदेश दिया।
अखिलेश आनंद@akhileshanandd

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने आवश्यक हो गए थे?

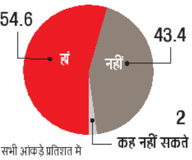

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या भोजशाला पर निर्णय से अन्य विवादित उपासना स्थलों के समाधान की उम्मीद जगी है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

पढ़-लिखकर लोगे भला कहां उखाड़ पहाड़,
पर्चा पाने के लिए करिए ठोस जुगाड़।
करिए ठोस जुगाड़ सफलता तलवा चूमे,
बिना पढ़े ही आप डाक्टर बनकर घूमें!
चीटर होते पास चालबाजी ही सिखकर,
घर बैठे सिर पीट रहे बच्चे पढ़-लिखकर!!
-ओम प्रकाश तिवारी

रचनाकर्म

माओवादी आतंक से मुक्ति की गाथा

सुजाता शिवेन

'माओवादी आतंकवाद राष्ट्र के युवाओं के विरुद्ध एक बड़ा अन्याय और गंभीर पाप है।' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब यह बात कही थी, तब किसी ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हीं के कार्यकाल में भारत इस अन्याय और पाप को अपने माथे से मिटा देगा। गृह मंत्री अमित शाह की अगुआई में माओवाद के विरुद्ध चली लंबी और दृढ़ लड़ाई में देश आज प्रायः माओवाद-मुक्त है। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। यह उस सिद्धांत की जीत है, जिसने हमेशा राष्ट्र को प्रथम माना। लेखक तुहिन ए. सिन्हा ने अपनी पुस्तक 'नक्सल टेरर वैंक्विश्ड' में नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की इस जीत को इतिहास, सिद्धांत, व्यावहारिकता, राजनीति और प्रशासनिक निश्चय की कसौटी पर परखा है। वे यह स्थापित करते हैं कि विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों वाले दल ने मई, 2014 में दिल्ली की सत्ता संभाली तो देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सुरक्षाबलों का जो नजरिया बदला, उसी ने यह सफलता दिलाई।

सिन्हा लिखते हैं कि अतीत की अनिर्णायक और प्रतिक्रियावादी शासन-प्रणाली से अलग वर्तमान सरकार ने कई स्तरों पर नक्सलवाद के विरुद्ध सुदृढ़ रणनीति अपनाई। सशक्त राजनीतिक सोच, दृढ़ प्रशासनिक निश्चय, जमीनी स्तर पर नीतिगत बदलाव, स्थानीय स्तर पर विकास की बयार, जन भागीदारी और सुरक्षा टुकड़ियों के साथ स्थानीय पुलिस का समन्वय ऐसे कारक थे, जिन्होंने उस स्वप्न और वादे को आकार दिया, जिसका दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। उनकी रणनीति ने जबरदस्त परिणाम दिए। वर्ष 2014 के बाद से अब तक माओवादी हिंसा में लगभग 100 प्रतिशत की कमी आई है। इतना ही नहीं, किताब लिखे जाने तक वर्ष 2014 के मुकाबले माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 100 से घटकर दो तक सिमट गई है। पिछले चार वर्षों में लगभग एक हजार माओवादी मारे गए।

पुस्तक मोदी सरकार के दृष्टिकोण को एक युगांतकारी बदलाव के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें 'आतंक के प्रति शून्य-सहिष्णुता' की अवधारणा पर जोर दिया गया। यह एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत बना, जिसमें सैन्य-दृढ़ता, खुफिया-समन्वय, कानूनी-सुधार और कल्याणकारी-पहल को समन्वित रूप से महत्व दिया गया। माओवाद को कमजोर करने में सरकार की सफलता सिर्फ सुरक्षाबलों के अभियान तक नहीं रुकी, बल्कि प्रभावित इलाकों में संसाधन और कल्याणकारी योजनाएं झोंक दी गईं।

यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की माओवादी आतंक के विरुद्ध कारगर लड़ाई और उस दिशा में प्राप्त अपूर्व सफलता की कहानी कहती है एवं इसे युगांतकारी परिवर्तन बताती है...

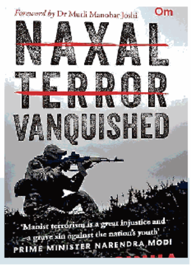

पुस्तक : नक्सल टेरर वैंक्विश्ड
लेखक : तुहिन ए. सिन्हा
प्रकाशक : ओम बुक्स इंटरनेशनल
मूल्य : 284 रुपये

पुस्तक चार खंडों के दस अध्यायों में बंटी है। आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति, माओवाद भारत के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा क्यों था? क्या यूपीए सरकार के लापरवाह रवैये ने माओवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई को कमजोर किया? सलवा जुडुम से जुड़ी उम्मीद और उसकी रुकावटों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने की पहल और अभियान का ब्योरा तो देती ही है, 'शहरी नक्सलियों' को बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का एक ऐसा नेटवर्क बताती है, जिसने कथित तौर पर माओवादी विद्रोहियों को नैतिक मजबूती दी। पुस्तक विश्वविद्यालय परिसर और चुनिंदा नागरिक संगठनों को 'मार्क्सवादी अराजकता' के समर्थक के रूप में भी दिखाती है। पुस्तक 'आदिवासियों के लिए मोदी' और 'नक्सल मुक्त भारत' को विकसित भारत की कड़ी मानती है। हालांकि, सिन्हा के भाजपा से जुड़ाव के चलते कुछ लोगों को यह पुस्तक एकतरफा लग सकती है, लेकिन उसमें शामिल तथ्य बताते हैं कि इसका उद्देश्य माओवादी आतंक के अंत को राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में दर्ज कराना भर है।

महत्वाकांक्षा के लिए देश से गद्दारी

मुकेश चौरसिया

भारत का बहुत समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां ऐसे अनेक प्रतापी राजा-महाराजा और शूरवीर हुए, जिन्होंने समय आने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका जीवन आज भी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। ऐसे राष्ट्रप्रेमी शूरवीरों पर सभी को गर्व है, लेकिन विभिन्न कालखंडों में ऐसे भी अवसर आए, जब कइयों ने अपने तुच्छ हितों और महत्वाकांक्षाओं के लिए गद्दारी कर अपने राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। इसका भारी खामियाजा देश को उठाना पड़ा। पुस्तक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर देश के साथ विश्वासघात करने वाले ऐसे ही गद्दारों के बारे में विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करती प्रतीत होती है।

पुस्तक में बताया गया है कि हमारा देश विश्वासघातियों का शिकार रहा है। ऐसे लोगों के कारण देश को अनेक बार अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ा। इन्हीं गद्दारों में राजा आंभी का नाम भी लिया जाता है, जिसने राजा पोरस के विरुद्ध आक्रमणकारी सिकंदर का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान के दौर में भी गद्दार के रूप में जयचंद का नाम लिया गया। जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, तब पृथ्वीराज चौहान का कुछ राजाओं ने साथ दिया, लेकिन जयचंद ने साथ नहीं दिया था। इसके पश्चात इस तरह की गद्दारी अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, नादिरशाह आदि के काल में भी देखने को मिली थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ऐसे अनेक देशद्रोही हुए, जिन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और उन्हें गिरफ्तार कराने में अंग्रेजों की मदद की थी। यह दौर अब भी नहीं थमा है। किसी न किसी रूप में आज भी देशद्रोही षड्यंत्र रच रहे हैं और देश को तोड़ने व उसकी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। पुस्तक में पोरस से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौर तक के गद्दारों के बारे में बताया गया है।

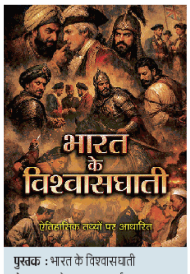

पुस्तक : भारत के विश्वासघाती
लेखक : राकेश कुमार आर्य
प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन
मूल्य : 400 रुपये

तमिल राजनीति का वैचारिक दर्पण

हाल में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु की राजनीति को केवल चुनावी अंकगणित या दलगत प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं समझा जा सकता। सत्ता के पीछे यहां एक लंबा इतिहास, भाषाई अस्मिता, सामाजिक विमर्श और उत्तर-दक्षिण की बहस सक्रिय है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक काल तक जाती हैं। हिंदी-विरोध से द्रविड़ पहचान और संघीय अधिकारों की बहस तक, तमिल राजनीति का हर स्वर इतिहास की गहरी प्रतिध्वनियां समेटे हुए है। ऐसे में 'कुली लाइंस' और 'वाह उस्ताद' जैसी उल्लेखनीय कृतियों से अपनी बौद्धिक उपस्थिति दर्ज करा चुके प्रवीण कुमार झा की 'द्रविड़ राजनीति : पेरियार से जयललिता तक' आधुनिक भारत और तमिल राजनीति के इतिहास को समझने की एक गंभीर वैचारिक आवश्यकता बन जाती है। 19वीं शताब्दी में आर्य और द्रविड़ नस्लों के विभाजन की अवधारणा ने स्वतंत्रता के बाद भी भाषा व संस्कृति संबंधी बहसों को प्रभावित किया। पुस्तक इसी औपनिवेशिक पृष्ठभूमि से होती है, जहां आर्य-द्रविड़ को नस्ली श्रेणियों के रूप में गढ़ने की प्रक्रिया की पड़ताल की गई है।

यतीन्द्र मिश्र

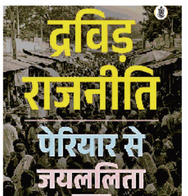

पुस्तक : द्रविड़ राजनीति : पेरियार से जयललिता तक
लेखक : प्रवीण कुमार झा
प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन
मूल्य : 350 रुपये

लेखक के अनुसार थियोसोफिकल सोसायटी की पृष्ठभूमि के बिना द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत को समझना संभव नहीं है। इसी संदर्भ में ए. ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का उल्लेख आता है। उस समय तमिल समाज में ब्राह्मण वर्चस्व और उसे संतुलित करने के कांग्रेस प्रयासों के बीच रामास्वामी 'पेरियार' जैसे ब्राह्मण-विरोधी का उभार द्रविड़ आंदोलन को निर्णायक दिशा देता है। लेखक आगे पेरियार और आंबेडकर को दलित विमर्श के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उनका विश्लेषण भी प्रस्तुत करते हैं। दक्षिण भारत में गांधी के हिंदी प्रचार अभियान का विवरण है, जिसके बाद उत्तर-दक्षिण का राजनीतिक-सांस्कृतिक समीकरण उभरता है। एम. जी. रामचंद्रन, करुणानिधि, जयललिता, तमिल ईलम और राजीव गांधी की हत्या जैसे प्रसंगों के माध्यम से पुस्तक ध्रुवीकरण की उस अदृश्य रेखा को समझने का प्रयास करती है, जिसे राजनीति ने और गहरा किया है। इसके अंत में आम तमिल लोगों से की गई बातचीत भी दर्ज है। लेखक का सहज, संवादधर्मी और प्रवाहपूर्ण शैली में संदर्भों, तथ्यों, फुटनोट्स और नाटकीय प्रसंगों के सहारे एक गंभीर विषय को रोचक बनाना प्रशंसनीय है।

कई-कई अर्थों में जीवन

लगभग 20 वर्ष पहले प्रकाशित कविता-संग्रह 'बार-बार यायावर' से प्रतिष्ठित कवि विनोद खेतान ने हिंदी कविता में एक संवेदनशील स्वर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। तब से अब तक का यह लंबा अंतराल केवल वर्षों का फासला नहीं, जीवन, समय और मनुष्य को नए सिरे से समझने की एक गहरी रचनात्मक यात्रा है। यही कारण है कि लगभग दो दशक बाद आया उनका नया कविता-संग्रह 'कई कई अर्थ' केवल नई कविताओं का संकलन नहीं लगता, जीवन के अनेक छूटे और अनकहे अर्थों को टटोलने वाली एक परिपक्व काव्य-यात्रा की स्वाभाविक अगली कड़ी प्रतीत होती है। भूमिका में विनोद खेतान बचपन से शब्दों और किताबों के प्रति अपने गहरे आकर्षण का उल्लेख करते हैं, जिसकी छाप संग्रह की अनेक कविताओं में भी दिखाई देती है। बचपन की स्मृतियों को सहेजती कविताओं में वे बदलते समय के बीच मनुष्य की खोती सहजता और प्रकृति से टूटते रिश्तों की पड़ताल करते हैं। पीपल के पेड़ से जुड़ा अज्ञात डर, जाड़े में कांथा की गरमाहट और बरसात में भीगने का उल्लास उस जीवन-संसार की स्मृतियां हैं, जो आज की पीढ़ी से दूर होता जा रहा है।

पुस्तक : कई कई अर्थ
लेखक : विनोद खेतान
प्रकाशक : प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
मूल्य : 300 रुपये

'पिता आशीर्वाद देते हैं, रक्षा-कवच की तरह' के जरिये विनोद खेतान अपने पिता की स्मृतियों को जीवन की सबसे भरोसेमंद नैतिक और भावनात्मक उपस्थिति की तरह पुनर्जीवित करते हैं। मां और भाई के गुजर जाने की पीड़ा, भीतर की रिक्तता और मौन असहायता कविताओं में अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति पाती है। कविताओं का संसार यहां परिवार और आत्मीय रिश्तों से आगे दशरथ मांझी, गुलजार, अशोक भौमिक, गालिब, रविशंकर और अज्ञेय जैसे व्यक्तित्वों तक फैलता है। 'एक बच्चे ने तय किया है कि उसका होना/बाढ़ की विभीषिका से भी ज्यादा ताकतवर है' 'कोसी की बाढ़' और 'बाढ़ में बच्चा' जैसी कविताओं में वे प्राकृतिक आपदा के बीच मनुष्य की जिजीविषा और अस्तित्व की अदम्य शक्ति को रेखांकित करते हैं। संग्रह की छोटी-छोटी कविताओं में भी विनोद खेतान बेहद सीमित शब्दों में जीवन की विडंबनाओं, रिश्तों की दरारों और समय की अनकही बेचैनियों को दर्ज कर लेते हैं। बिना किसी भाषाई आडंबर के वे जीवन की जटिलतम अनुभूतियों को इतनी सहजता से व्यक्त करते हैं कि पाठक अनायास ही उन संवेदनाओं का सहभागी बन जाता है। समय की टूटती संवेदनाओं, गहराते एकांत और बदलते सामाजिक यथार्थ की यही सूक्ष्म पड़ताल इस संग्रह को विशिष्ट बनाती है।

आठ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री दो प्रतिशत घटी

नई दिल्ली : रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्राप टाइगर ने शनिवार को बताया कि जनवरी-मार्च 2026 के दौरान देश के आठ प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री की दो प्रतिशत घटकर 95,973 इकाई रही है। जनवरी-मार्च 2025 में इन शहरों में 98,095 घरों की बिक्री हुई थी। इसका प्रमुख कारण मांग में नरमी और नए घरों की आपूर्ति में स्थिरता रहा है। बीती तिमाही में इन शहरों में नए घरों की आपूर्ति 93,065 इकाई पर स्थिर रही है जो पिछले वर्ष समान अवधि में 93,144 इकाई थी। (प्रेट्र)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक तकनीकी परत नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजी से दुनिया भर के उद्यमों के लिए एक आपरेटिंग आधार बनता जा रहा है।
- एन. चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टीसीएस

रुपये में गिरावट से नहीं मिलेगा ईंधन मूल्य वृद्धि का लाभ

एसबीआइ रिसर्च ने कहा, डालर की कीमत में दो रुपये की और वृद्धि से तेल कंपनियों की राहत पर फिर जाएगा पानी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: दो दिन पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, लेकिन इससे उनको तभी राहत मिलेगी जब डालर के मुकाबले रुपया स्थिर रहे। एसबीआइ की शोध रिपोर्ट के अनुसार, तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से ओएमसी को इस साल 53 हजार करोड़ रुपये की कमाई होगी, जो मार्च-अप्रैल, 2026 में कीमत वृद्धि नहीं करने से हुई हानि की भरपाई में मदद करेगी। हालांकि, अगर डालर के मुकाबले रुपये की कीमत में दो रुपये की गिरावट होती है तो इस कमाई पर पानी फिर जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ओएमसी 86-87 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करती हैं जिसका भुगतान डालर में होता है। कमजोर रुपये का मतलब होगा कि उन्हें कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डालर देना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कीमत वृद्धि के साथ रुपये की गिरावट को रोकना भी जरूरी है, तभी देश में बढ़ते ऊर्जा बिल पर लगाम लग सकेगी और इकोनमी को बढ़ती ऊर्जा लागत से बचाया जा सकेगा।

एसबीआइ के मुताबिक, ओएमसी फिलहाल प्रतिदिन करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं, जो सालाना आधार पर 3.6 लाख करोड़ रुपये के करीब होगा। इस तीन रुपये की वृद्धि से वित्त वर्ष 2026-27 में इन कंपनियों को लगभग 52,500 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है, जो उनके अपेक्षित घाटे का महज 15 प्रतिशत है। यह राहत तेल कंपनियों को तभी होगी, जब रुपया सालाना अनुमानित औसत 94 रुपये प्रति डालर पर स्थिर रहे। अगर भारतीय मुद्रा महज दो रुपये और कमजोर होकर 96 पर पहुंच गई, तो तीन रुपये कीमत वृद्धि से होने वाला पूरा फायदा निष्प्रभावी हो जाएगा।

- हाल ही में तीन रुपये बढ़ी है पेट्रोल और डीजल की कीमत
- मूल्य वृद्धि से ओएमसी को 53 हजार करोड़ की कमाई होगी

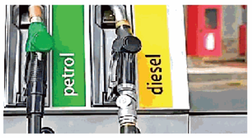

87 प्रतिशत तक कच्चा तेल आयात करती हैं तेल विपणन कंपनियां

1,000 करोड़ रुपये का तेल कंपनियों को हर रोज हो रहा नुकसान

कच्चे तेल की कीमतों में बहुत राहत की संभावना नहीं

जहां तक कच्चे तेल की कीमतों का सवाल है तो उसमें बहुत राहत मिलने की संभावना भी नहीं दिख रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) के मुताबिक, उत्पादन घटने के कारण कीमतें ज्यादा ही रहेंगी। यह मानते हुए कि जून से होर्मुज जल मार्ग से क्रूड आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य होने लगेगी, तब भी वर्ष 2026 में वैश्विक तेल आपूर्ति औसतन 39 लाख बैरल कम रहेगी और कुल उत्पादन घटकर 10.2 करोड़ बैरल प्रति दिन रह जाएगा। वैसे युद्ध की वजह से वैश्विक मांग भी कम होगी, लेकिन मांग व आपूर्ति के बीच अंतर बना रहेगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 15-20 आधार अंक की वृद्धि होगी

रिपोर्ट में बताया गया है कि पेट्रो उत्पादों की कीमत वृद्धि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तत्काल 15-20 आधार अंक बढ़ेगा। सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कमी की थी, जिससे केंद्र को 1.1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। क्रूड महंगा ही होता रहा तो सरकार आगे भी उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। एसबीआइ के मुताबिक, अगर आगे उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया जाए तो केंद्र के राजस्व में अतिरिक्त 1.9 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 0.5%) की कमी हो सकती है, जबकि राज्यों को 80,000 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

आठ प्रतिशत बढ़ा कच्चा तेल

नई दिल्ली, आइएएनएस: इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी रही है। सप्ताह के दौरान वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 7.84 प्रतिशत और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआइ) क्रूड में 10.48 की वृद्धि दर्ज की गई। शुक्रवार को बाजार बंद होने पर बेंचमार्क क्रूड कांट्रैक्ट्स तीन प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने से होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जल्द ही कोई हल निकलने की उम्मीदें कम हो गईं। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 109.26 डालर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआइ क्रूड 105.42 डालर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

इस बार जल्दी खत्म नहीं होगा मुश्किलों से भरा हुआ दौर!

डाटकाम बुलबुले के फटने से लेकर 2008 के संकट तक, नोटबंदी से लेकर कोविड क्रैश और यूक्रेन युद्ध तक, और बीच में आए हर तेल के झटके तक। डाटा हर बार इस बात की पुष्टि करता रहा है। बार-बार। आज मैं उस परंपरा से एक कदम पीछे हट रहा हूं। अमेरिका-ईरान युद्ध एक ऐसी असाधारण स्थिति है, जिस पर मेरी आम सलाह लागू नहीं होती। ज्यादातर संकट बाजार के सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। यह संकट असल चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है।

धीरेंद्र कुमार, संपादक, हिंदी डाट वैल्यूरिसर्चआनलाइन डाट काम

बोनस

सोचिए, ज्यादातर बाजार संकट असल में होते क्या हैं। कंपनियां लड़खड़ाती हैं। कोई सेक्टर अचानक अप्रासंगिक हो जाता है। मूल्यांकन कमाई से आगे निकल जाते हैं। घबराहट फैलती है। कीमतें गिरती हैं। लेकिन फैक्ट्रियां वहीं खड़ी रहती हैं। मजदूर वहीं होते हैं। सप्लाई चेन, ग्राहक, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता- सब बरकरार रहती है। बदलती है तो बस मनोदशा या नकदी का प्रवाह या वह कीमत जो कोई भविष्य की कमाई के लिए चुकाने को तैयार है। ये तो एक मूल रूप से स्वस्थ शरीर के भीतर के उतार-चढ़ाव हैं, जो आखिरकार गुजर जाते हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष दूसरी किस्म का है। जो नुकसान हो रहा है, वह सेंटीमेंट को नहीं, बल्कि असल ढांचे को हो रहा है। अगर दुनिया की कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो रहा है, जिसके 10-15 प्रतिशत होने का अनुमान है, तो हम किसी साइकिल में नहीं हैं। हम एक पुनर्निर्माण के चरण में हैं, जो अभी शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि तबाही अभी रुकी नहीं है। तेल से मिलने वाले पेट्रोल, डीजल, खाद, प्लास्टिक जैसे तमाम इंडस्ट्रियल इनपुट्स मनोदशा बदलने से बहाल नहीं होंगे। ये तभी बहाल होंगे, जब मरम्मत होगी, पाइप बिछेंगे और रिफाइनरियां फिर से खड़ी होंगी। इसमें तिमाहियां नहीं, कई साल लगेंगे।

भारतीय निवेशक के लिए यह सब कोई दूर की बात नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। वैश्विक कीमत में हर डालर की बढ़ोतरी का असर कुछ समय बाद पेट्रोल पंप पर, खाद के बिल में, सीमेंट की लागत में और किसी घर के रसोई के बजट में दिखता है।

तेल की ऊंची कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। इसका दूसरा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ता है। इक्विटी फंड में शामिल सीमेंट, आटो और कंज्यूमर गुड्स जैसी कंपनियों की लागत बढ़ जाती है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव आता है। इसलिए निवेशक के पोर्टफोलियो को असली चोट अचानक गिरावट से नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में कमजोर कमाई से लग सकती है।

इसका मतलब यह नहीं कि घबराकर निवेश बेच दिया जाए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान बढ़ाता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि रिकवरी को लेकर उम्मीदें थोड़ी बदली जाएं। इस बार बाजार की वापसी तेज नहीं, बल्कि धीमी और असमान हो सकती है। कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा रह सकता है, जिससे महंगाई जल्दी काबू में आने की संभावना कम है। ब्याज दरों में राहत भी देर से मिल सकती है।

इस दौरान सबसे ज्यादा असर आम लोगों की बचत और खर्च पर पड़ेगा, जबकि उनका इस संघर्ष से सीधा संबंध नहीं है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

देनदारी में कमी से वोडाफोन को 51,970 करोड़ रुपये का लाभ

- छह साल बाद लाभ में आई तीसरी बड़ी दूरसंचार कंपनी
- पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को 34,552 करोड़ रुपये का लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र: मुश्किलों से जूझ रही देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के दौरान 51,970 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया कि लगभग छह सालों में यह उसका पहला मुनाफा है और जिसका मुख्य कारण कानूनी देनदारियों में मिली राहत है। जनवरी-मार्च 2025 के दौरान कंपनी को 7,167 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

दूरसंचार विभाग ने 30 अप्रैल को बताया था कि पुनर्मूल्यांकन के बाद वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया राशि 64,046 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इससे 31 दिसंबर, 2025 तक की 80,502 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी समाप्त हो गई और 24,880 करोड़ रुपये की संशोधित वित्तीय देनदारी को मान्यता दी गई। इससे 55,622 करोड़ रुपये का अंतर और अन्य संबंधित प्रविधानों के शुद्ध प्रभाव को 'लाभ और हानि विवरण' में दर्ज किया गया।

एजीआर देनदारी में कमी के कारण यह पूरे वित्त वर्ष में भी मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। बीते वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 34,552 करोड़ रुपये का लाभ हुआ, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 27,384 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने आदित्य बिरला समूह की इकाई से 4,730 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है।

अब बिना मंजूरी नहीं हो सकेगा चांदी का आयात

नई दिल्ली, प्रेट्र: कीमती धातुओं पर आयात शुल्क को बढ़ाकर छह से 15 प्रतिशत किए जाने के बाद अब सरकार ने चांदी आयात के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत चांदी आयात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यानी अब चांदी का आयात पूर्व मंजूरी के बिना नहीं हो सकेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में बताया कि यह बदलाव 99.9 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता वाली चांदी के साथ सोने और प्लेटिनम के साथ इस्तेमाल होने वाली चांदी पर भी लागू होंगे।

यह बदलाव कीमती धातुओं के आयात पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है, ताकि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। यह बदलाव निर्यात इकाइयों और स्पेशल इकोनमिक जोन (एसईजेड) पर लागू नहीं होंगे।

डीआइआइ ने किया 18,520 करोड़ का निवेश

- सप्ताह के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशक चार कारोबारी सत्रों में शुद्ध खरीदार रहे
- इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 13,580 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

मुंबई, आइएएनएस: इस सप्ताह घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) ने घरेलू शेयर बाजारों को 18,520 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद के साथ सहारा दिया। इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआइआइ) उच्च बाजार अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शुद्ध विक्रेता बने रहे। एक्सचेंज के प्रारंभिक डाटा के अनुसार, एफआइआइ ने पिछले सप्ताह 13,580 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डीआइआइ शुद्ध खरीदार बने रहे।

डाटा के अनुसार, मई में अब तक एफपीआइ 24,660 करोड़ रुपये के शेयर बेच चुके हैं। वहीं, डीआइआइ ने घरेलू बाजारों में 39,920 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सप्ताह के दौरान तीन कारोबारी सत्रों में एफआइआइ शुद्ध विक्रेता बने रहे और करीब 15,100 करोड़ रुपये की निकासी की। अंतिम दो सत्रों में एफआइआइ ने शुद्ध खरीदार बनकर 1,520 करोड़ रुपये का निवेश किया। दूसरी ओर, डीआइआइ पिछले सप्ताह पांच कारोबारी सत्रों में से चार में शुद्ध खरीदार रहे। केवल एक सत्र में 1,960 करोड़ रुपये की निकासी की। विश्लेषकों ने कहा कि बाजारों ने सप्ताह के दौरान कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमजोर रुपये, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-चीन कूटनीतिक वार्ताओं के आसपास की अनिश्चितता के बीच बढ़ी हुई अस्थिरता का सामना किया।

इस सप्ताह दो हजार अंक से अधिक लुढ़का सेंसेक्स

इस सप्ताह दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स में 2,090.2 अंक या 2.7 प्रतिशत और एनएसई निफ्टी में 532.65 अंक या 2.2 प्रतिशत की गिरावट रही। सप्ताह के दौरान बीएसई के बाजार पूंजीकरण में 12.87 लाख करोड़ रुपये की कमी आई। आठ मई को समाप्त सप्ताह के अंत में बीएसई का कुल पूंजीकरण 4,73,46,840.21 करोड़ रुपये था, जो 15 मई को समाप्त सप्ताह के अंत में घटकर 4,60,59,270.46 करोड़ रुपये रह गया।

राष्ट्रीय फलक

केंद्र सरकार 10,211 करोड़ रुपये की लागत से कर रही 736 बांधों का आधुनिकीकरण

- इनमें भाखरा बांध, रंजीत सागर बांध, जिरगो बांध, सिलाबती बैराज शामिल
- 191 बांधों के लिए 5,053 करोड़ रुपये के पुनर्वास प्रस्तावों को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआइपी) के तहत 10,211 करोड़ रुपये की लागत से 736 बांधों का आधुनिकीकरण कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इसके तहत 191 बांधों के लिए 5,053 करोड़ रुपये के पुनर्वास प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और 31 मार्च, 2025 तक 43 बांधों पर पुनर्वास कार्य पूरा हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए डीआरआइपी के दूसरे और तीसरे चरण में 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों - केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और दामोदर घाटी निगमके 736 बांध शामिल हैं।

परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के तहत जिन प्रमुख बांधों की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा उनमें भाखरा बांध (हिमाचल प्रदेश), रंजीत सागर बांध (पंजाब), गांधी सागर बांध (मध्य प्रदेश), जिरगो बांध (उत्तर प्रदेश) और सिलाबती बैराज (बंगाल) शामिल हैं।

डीआरआइपी के दूसरे और तीसरे चरण के लिए कुल परियोजना लागत 10,211 करोड़ रुपये है - जिसमें से 5,107 करोड़ रुपये दूसरे चरण के लिए और 5,104 करोड़ रुपये तीसरे चरण के लिए हैं। इसमें से सात हजार करोड़ रुपये बाहरी ऋण सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं, जबकि 3,211 करोड़ रुपये सहभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा वहन किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआइआइबी) में भी फंडिंग मिल रही है। दूसरे और तीसरे चरण को मिलाकर योजना की अवधि 10 साल है। परियोजना का उद्देश्य पुराने होते बांधों की संरचनात्मक मजबूती, जल संग्रहण क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाना, रखरखाव के लिए राजस्व जुटाने के उपाय करना शामिल है।

मंत्रालय ने कहा कि डीआरआइपी दुनिया के सबसे बड़े बांध पुनर्वास कार्यक्रमों में से एक है। भारत 6,628 बांधों के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है, जिनमें से 6,545 चालू हैं और 83 निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब घन मीटर है और ये राष्ट्रीय खाद्य, ऊर्जा और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन बांधों में से 26 प्रतिशत से अधिक, यानी 1,681 तो 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं।

उप्र में रील बनाकर पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: अब रील (शार्ट वीडियो) बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में जारी आदेश में वर्ष 2023 में पुलिसकर्मियों के लिए बनाई गई इंटरनेट मीडिया नीति का उल्लेख किया गया है। एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा है कि कई पुलिस कर्मियों द्वारा इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर वीडियो, रील व अन्य आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पुलिस महकमे की छवि धूमिल हो रही है। लिहाजा, ऐसा करने वालों को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया पर कई पुलिसकर्मियों के आपत्तिजनक वीडियो व रील के मामले सामने आए हैं।

चैरिटी कमिश्नर के निर्देश के बाद टाटा ट्रस्ट्स की बोर्ड बैठक स्थगित

- चैरिटी कमिश्नर ने ट्रस्ट्स बोर्ड की संरचना में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद दिया निर्देश

मुंबई, एएनआइ : महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर के निर्देश के बाद टाटा ट्रस्ट्स ने शनिवार को होने वाली ट्रस्टियों की बोर्ड बैठक स्थगित कर दी है। चैरिटी कमिश्नर ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) के न्यासी बोर्ड की संरचना में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद टाटा ट्रस्ट्स को बोर्ड बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया था। टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रायटर के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स को निर्देश दिया गया है कि तब तक बैठक आयोजित न किया जाए जब तक कि निरीक्षक जांच पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दे।

शुक्रवार को जारी बयान में टाटा ट्रस्ट्स ने कहा, एक ईमेल मिला, जिसमें चैरिटी कमिश्नर ने टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी बोर्ड को 16 मई को निर्धारित बोर्ड की बैठक स्थगित करने का निर्देश दिया गया था। यह निर्देश कात्यायनी अग्रवाल द्वारा दायर शिकायत, ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन के अभ्यावेदन और सर रतन टाटा ट्रस्ट से संबंधित रिट याचिका में बांबे हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में जारी किया गया। ट्रस्ट्स ने दावा किया कि यह निर्देश केवल सर रतन टाटा ट्रस्ट से संबंधित था। कात्यायनी अग्रवाल ने शिकायत में आरोप लगाया है कि "सर रतन टाटा ट्रस्ट के छह ट्रस्टियों में से तीन स्थायी हैं, महाराष्ट्र सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 30ए (2) का उल्लंघन कर रहे हैं। सितंबर 2025 में लागू किए गए संशोधित प्रविधान के अनुसार, स्थायी या आजीवन न्यासियों की संख्या बोर्ड की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है।

आस्ट्रेलिया न भेजने से नाराज बेटी ने पिता को मारी गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर: खलचियां इलाके में एक बेटी ने आस्ट्रेलिया जाने की जिद में पिता को शुक्रवार रात गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज से परिवार और आसपास के लोग एकत्रित हुए और पिता को गुरु नानक देव अस्पताल (जीएनडीएच) में दाखिल करवाया। डीएसपी सुखपाल सिंह ने बताया कि युवती के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।

हरमिंदर सिंह की पत्नी मंजीत कौर ने बताया कि बेटी स्नेहदीप कौर ने पिछले साल प्लस टू की पढ़ाई पूरी की थी। अब वह विदेश जाना चाहती थी, लेकिन पिता इसके विरुद्ध थे। मंजीत के अनुसार, स्नेहदीप कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रही है। उसका पिता के साथ विदेश जाने को लेकर विवाद भी हो चुका है।

होटल के बाहर खड़ी बस में लगी आग, सीए के बच्चे की जलने से मौत

- सीट के नीचे मिला कंकाल
- शाजापुर में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल में हुआ हादसा

होटल के बाहर जलती बस। वीडियो ग्रैब

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात होटल के बाहर खड़ी बस में आग लगी गई। इससे भगदड़ में बाकी यात्री तो भाग खड़े हुए, लेकिन बस में अकेले रह गए सीए अभिषेक जैन के चार वर्षीय बच्चे की जलने से मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद सीट के नीचे उसका कंकाल मिला। एयर कंडीशन बस इंदौर से ग्वालियर जा रही थी। बस यात्रियों के चाय-नाश्ते के लिए शाजापुर के मक्सी क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित होटल पर रुकी थी। लगभग 50 में से अधिकांश यात्री उतरकर होटल जा चुके थे, कुछ ही बस में बाकी रह गए थे। इसी बीच बस के अगले हिस्से में आग लग गई। इसे देखकर यात्री भाग खड़े हुए, हालांकि इंदौर से शिवपुरी की यात्रा कर रहे अभिषेक जैन का चार वर्षीय बेटा अनय बस में ही रह गया। यात्रियों ने बताया कि बस में वायरिंग जलने जैसे बदबू आ रही थी। बस में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का लगेज था, इससे आग तेजी से फैली।

मृत बच्चे के पिता सीए अभिषेक जैन ने आग लगने के बाद बाकी यात्रियों की मदद की और लाखों रुपये के सोने के गहने पुलिस को सौंपे, लेकिन अपने ही बच्चे को वह नहीं बचा सके।

अमेरिकी नागरिक की पैंट से निकले 115 सोने के बिस्कुट, करोड़ों का सोना जब्त

जासं, नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की तस्करी के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कस्टम अधिकारियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर जाल बिछाकर सैन फ्रांसिस्को से आए एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपित अपनी विशेष बेल्ट और पैंट की जेबों में शातिर तरीके से छिपाकर 115 सोने के बिस्किट भारत ला रहा था। जब्त सोने का कुल वजन करीब 3.5 किलोग्राम है। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक, आरोपित 15 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को से एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-4174 के जरिए दिल्ली पहुंचा था।

जब यात्री और उसके सामान की व्यवस्थित तरीके से तलाशी ली गई, तो अधिकारी हैरान रह गए। आरोपित ने सोने को छिपाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन बेल्ट पहन रखी थी और अपनी पैंट के अंदरूनी हिस्सों में गुप्त जेबें बना रखी थीं। इन्हीं जेबों में शुद्ध 24-कैरेट (999.9 शुद्धता) के 115 सोने के बिस्किट छिपाए गए थे।

साप्ताहिक राशिफल

रविवार, 17 मई, 2026 से शनिवार 23 मई, 2026 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ)
कला संगीत के प्रति रुचि, धनागम में सुधार, साहस तथा युक्ति से सफलता, निजी संबंधों में सुधार, साधनों की पूर्ति, चयन में सफलता, रक्त, वायु विकार योग, परिवार में मंगल कार्य, स्थान पद परिवर्तन योग, व्यय अधिक, शुभ अंक 1

वृष (इ, ऊ, ए, ओ, पा, वी, वू, वे, वो)
आत्मविश्वास से कार्य करें, मन में विचारों की अधिकता, निजी संबंधों में सुधार, लक्ष्य के प्रति सजगता, स्व :सम्पत्ति की वृद्धि, शिक्षा में रुचि, मित्रों से सावधान, जीवनसाथी का मिलन, स्थान पद परिवर्तन योग, व्यय अधिक, शुभ अंक 2

मिथुन (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा)
कार्य क्षेत्र में युक्ति एवं प्रयास से सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, कार्य करने वालों से सावधान, स्वार्थीजनों से सावधान, भूमि भवन के कार्य में देरी, रक्त विकार, त्वचा विकार प्रभावी, शिक्षा में अवरोध, ससुराल से सहयोग, मनोरंजन एवं भ्रमण का योग, व्यय अधिक, शुभ अंक 4

कर्क (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो)
अर्थ साधन में देरी, कार्य क्षेत्र मे वृद्धि से बचें, साझेदारी में सावधानी, निजी संबंधों में सुधार, स्वार्थीजनों से बचें, महिला से सहयोग, भूमि कार्य में देरी, शिक्षा में रुचि, क्रोध, ईर्ष्या से बचें, जीवन साथी का मिलन, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

सिंह (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे)
निर्णय सलाह से करें, कार्य क्षेत्र में सावधानी, नकारात्मक विचारों से सावधान, लक्ष्य के प्रति सावधान, विदेश कार्य में देरी, भूमि निर्मा ण का योग, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष प्रभावी, जीवनसाथी का मिलन, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक, शुभ अंक 7

कन्या (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो)
कार्य में सफलता, धनागम में सुधार, नए कार्य में विस्तार से बचे, सामाजिक यश का योग, निजी मतभेद, साधनों की पूर्ति, शिक्षा में व्यवधान, चयन में देरी, खानपान का ध्यान रखे, जीवन साथी का मिलन, स्थान पद परिवर्तन, व्यय पर नियन्त्रण, शुभ अंक 6

तुला (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते)
वाणी पर संयम, कार्य क्षेत्र में विस्तार से बचें, अर्थ साधन में सुधार, विदेश कार्य में अवरोध, लक्ष्य के प्रति सजगता, चिन्ता का समाधान, भवन निर्माण सजावट, संतान से सहयोग, मित्रों से सहयोग, जीवनसाथी का मिलन, धर्म में रुचि, स्थान पद परिवर्तन, शुभ अंक 4

वृश्चिक (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)
कार्य में प्रयास से सफलता, धनागम में प्रयास, विदेश कार्य में अवरोध, महिला से सहयोग, सामाजिक कार्य में यश, सन्तान से सहयोग, मित्रों से सहयोग, शिक्षा में रुचि, वायु विकार, रक्त विकार योग, ससुराल से सहयोग, भ्रमण, मनोरंजन योग, व्यय में नियन्त्रण, शुभ अंक 5

धनु (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे)
अर्थ साधन में प्रयास करें, कार्य क्षेत्र में वृद्धि से बचें, साझेदारी में सावधानी, साझेदारी में अनबन, युक्ति तथा अनुभव से कार्य करे, स्व :सम्पत्ति की वृद्धि, शिक्षा में रुचि, त्वचा एवं रक्त विकार का योग, ससरुाल से सहारा, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक, शुभ अंक 6

मकर (भो, जा, ज, खी, खू, खे, खो, गा, गी)
नये कार्य क्षेत्र में विस्तार से बचें, अर्थ साधन में सुधार, कार्य करने वालों से सावधान, लक्ष्य के प्रति सजगता, स्वार्थीजनों से सावधान, माता-पिता का ध्यान रखें, शिक्षा में रुचि, क्रोध से बचें, जीवनसाथी का मिलन, स्थान पद परिवर्तन, आय में सुधार, शुभ अंक 7

कुम्भ (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सा, दा)
अर्थ साधन में प्रयास, कार्य क्षेत्र में वृद्धि से बचें, धन के आवागमन में सावधान, विशेष व्यक्ति से सहयोग, निजी संबंधों में सुधार, स्व : सम्पत्ति की वृद्धि, शिक्षा में अवरोध, चयन में देरी, वायु विकार, रक्त विकार योग, शत्रुपक्ष से सावधान, जीवनसाथी का मिलन, व्यय अधिक, शुभ अंक 9

मीन (दी, दू, थ, झ, दे, दो, चा, ची)
साझेदारी में सावधानी, धनागम में प्रयास, महिला स सहयोग, कार्य क्षेत्र में सावधानी, विदेश कार्य में देरी, भूमि भवन कार्य में देरी, शिक्षा में रुचि, मित्रों से लाभ, पैर दर्द, सिर दर्द का योग, पारिवारिक मंगल कार्य, अधिकारी से सहयोग, आय में प्रयास, शुभ अंक 8

16 मई को इटली के मोडेना शहर में एक युवक ने पैदल यात्रियों पर कार चढ़ा दी। मेयर मास्सिमो मेजेटी ने बताया कि इस घटना में आठ लोग घायल हुए हैं जिनमें से दो की हालत गंभीर है। घायल एक महिला के दोनों पैर काटने पड़ सकते हैं।

ताइवान पर पीछे हटने के संकेत, ट्रंप बोले– 15 हजार किमी दूर जाकर नहीं लड़ेंगे

चीन दौरे के बाद ट्रंप के बयान से अमेरिका की 'रणनीतिक अस्पष्टता' नीति पर उठे सवाल

ट्रंप बोले, चीन नहीं चाहता ताइवान खुद को स्वतंत्र घोषित करे, जिससे अमेरिका से लड़ना पड़े

बीजिंग, एएनआइः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दो दिवसीय चीन यात्रा वैश्विक कूटनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। यात्रा के दौरान ताइवान मुद्दे पर ट्रंप के बयान से अमेरिका की दशकों पुरानी 'रणनीतिक अस्पष्टता' नीति में नरमी के संकेत मिले हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता के लिए ''9,500 मील (करीब 15 हजार किलोमीटर) दूर जाकर युद्ध लड़ने'' के पक्ष में नहीं है।

फाक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ताइवान को औपचारिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने से आगाह करते हुए कहा कि वह मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्रता घोषित करे और फिर अमेरिका को हजारों मील दूर जाकर युद्ध लड़ना पड़े। मैं चाहता हूं कि हालात शांत रहें और चीन भी संयम बरते।''

ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए ताइवान हमेशा सबसे अहम मुद्दा रहा है। उनके अनुसार, चीन ताइवान पर कब्जा करने से ज्यादा इस बात को लेकर चिंतित है कि ताइवान खुद को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित न करे। ट्रंप ने दावा किया कि ताइवान का नेतृत्व यह मानकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है कि अमेरिका सैन्य समर्थन देगा। शी चिनफिंग ने ट्रंप से बातचीत में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों की स्थिरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ताइवान मुद्दे को कितनी समझदारी से संभाला जाता है।

चीन ने दोहराया कि 'ताइवान की स्वतंत्रता' और ताइवान जलडमरूमध्य में शांति साथ-साथ नहीं चल सकते। बीजिंग ने कहा कि जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखना चीन और अमेरिका के साझा हित में है।

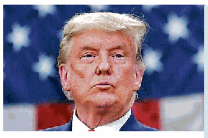
डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

ताइवान पर क्या है अमेरिकी नीति

अमेरिका 'वन चाइना' नीति को आधिकारिक मान्यता देता है, लेकिन ताइवान के साथ उसके अनौपचारिक संबंध बने हुए हैं। ताइवान संबंध अधिनियम के तहत अमेरिका ताइवान को रक्षा सहायता और हथियार उपलब्ध कराता है। अमेरिकी कांग्रेस के रिकार्ड के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन की 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में ताइवान को लेकर किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध दोहराया गया है। साथ ही कहा गया है कि ताइवान को लेकर संघर्ष रोकना अमेरिका की प्राथमिकताओं में शामिल है।

शी के साथ बैठक को ट्रंप ने बताया 'जी-2'

प्रेट्र के अनुसार, ट्रंप ने चीन यात्रा से लौटने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ हुई बैठक को ''जी-2'' करार दिया। कहा कि यह दुनिया के ''दो महान देशों'' की बैठक थी और इतिहास में इसे महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि चीन के साथ उनकी बातचीत सफल रही और कई बड़े व्यापारिक समझौते हुए। कहा कि चीन ने बोइंग से 200 विमान खरीद का समझौता किया है, जबकि 750 और विमान खरीद का आश्वासन दिया गया।

ईरान पर नए हमलों की तैयारी में अमेरिका, 'आपरेशन स्लेजहैमर' पर हो रहा मंथन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- युद्धविराम टूटने की आशंका के बीच अमेरिका-इजरायल ने तेज की सैन्य तैयारियां
- होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन-तेहरान में तनाव बरकरार

प्रतीकात्मक

पश्चिम एशिया में पिछले ढाई महीने से जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बने गतिरोध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारी तेज कर दी है। ट्रंप प्रशासन युद्धविराम टूटने की स्थिति में 'आपरेशन स्लेजहैमर' नाम से संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजरायल युद्धविराम के बाद से अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारियों में जुटे हैं। न्यूयार्क टाइम्स ने पश्चिम एशिया के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अगले सप्ताह से ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर नए हमले शुरू किए जा सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अभियान के तहत विशेष अभियान बलों को भी तैनात किया जा सकता है, ताकि जमीन के भीतर गहराई में छिपी परमाणु सामग्री और ठिकानों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, इसी उद्देश्य से मार्च में सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल आपरेशन फोर्स को पश्चिम एशिया भेजा गया था। बताया जा रहा है कि संभावित कार्रवाई वहीं से शुरू हो सकती है, जहां सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समय में हुए युद्धविराम से पहले सैन्य गतिविधियां रुकी थीं।

चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग से ईरान मुद्दे पर चर्चा के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और आक्रामक माना जा रहा है। अमेरिका और इजरायल इस समय संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। एक बार फिर युद्ध शुरू होने को लेकर दुनिया के देशों में आशंकाएं है।

युद्ध दोबारा शुरू होने को लेकर आशंकित ईरान

ईरान भी संभावित सैन्य संघर्ष को लेकर सतर्क हो गया है। तेहरान ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं और दावा किया है कि पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हुए एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा, ''हमारी सेना किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।'' वहीं, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात नियंत्रित करने के लिए नया तंत्र तैयार किया है। इसके तहत केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी तथा इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा। अमेरिकी सेंटकाम ने दावा किया है कि अब तक 78 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट में लौटाया जा चुका है, जबकि चार जहाजों को निष्क्रिय किया गया है।

नाइजीरिया में आइसिस का उप प्रमुख मिनुकी मारा गया

- अमेरिका और नाइजीरिया की संयुक्त कार्रवाई में हुआ ढेर
- हजारों ईसाइयों की मौत के लिए जिम्मेदार था वैश्विक आतंकी

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में शुक्रवार रात आतंकी संगठन आइएसआइएस (आइसिस) का उप प्रमुख अबू बिलाल अल-मिनुकी मारा गया। यह जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाइजीरिया के उनके समकक्ष बोला अहमद तिनुबू ने दी है।

ट्रंप ने शुक्रवार देर रात अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का अनुपम उदाहरण है। बताया- उनके निर्देश पर बहादुर अमेरिकी सैनिकों और नाइजीरिया के सुरक्षा बलों ने जटिल कार्रवाई में लड़ाई के मैदान में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे आतंकी अबू बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया। इसके कुछ घंटे बाद नाइजीरिया के राष्ट्रपति तिनुबू ने भी मिनुकी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। बताया- अमेरिकी सैनिकों के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में मिनुकी और आइसिस के कई उच्च पदस्थ आतंकी मारे गए हैं।

इससे पहले ट्रंप ईसाइयों की सुरक्षा में विफल रहने पर नाइजीरिया की कड़ी निंदा कर आतंकियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की चेतावनी दे चुके थे। नाइजीरिया में पिछले 10 वर्षों में इस्लामी आतंकियों के हमलों में हजारों ईसाई मारे गए हैं। लेकिन अब ट्रंप ने कार्रवाई में सहयोग के लिए नाइजीरिया सरकार को धन्यवाद दिया है। नाइजीरिया की सेना ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में बताया है कि आइसिस आतंकियों को बोर्नो प्रांत के मेटेले में घेरा गया। वहां चार घंटे चली कार्रवाई में अमेरिका और नाइजीरिया के सैनिकों ने सटीक हवाई और जमीनी कार्रवाई में मिनुकी और उसके कई सहयोगियों को मार गिराया। मिनुकी नाइजीरियाई नागरिक था। अमेरिका ने उसे 2023 में वैश्विक आतंकी घोषित किया था। इस क्षेत्र में आतंकी संगठन बोको हराम, आइसिस और आइसिस से अलग हुए गुट के आतंकियों ने पिछले 17 वर्षों में हजारों लोगों को मारा है। हमलों से बचने के लिए क्षेत्र की करीब 20 लाख की आबादी विस्थापित हुई है।

बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ट्रंप के बाद अब पुतिन जाएंगे चीन

- क्रेमलिन ने कहा, 19-20 मई को चीन दौरा करेंगे रूसी राष्ट्रपति
- द्विपक्षीय संबंध, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी वार्ता
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13-15 मई तक किया बीजिंग का दौरा

मास्को, रायटर : वैश्विक राजनीति के रंगमंच पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग की अपनी राजकीय यात्रा पूरी कर रवाना हुए हैं, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन का रुख कर लिया है। क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन 19 और 20 मई को चीन की दो दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से होगी। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया की निगाहें महाशक्तियों के बदलते समीकरणों पर टिकी हैं।

दोस्ती के 25 साल और गहरे होते रिश्ते: यह यात्रा महज एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती का जश्न है। दरअसल, पुतिन का यह दौरा वर्ष 2001 की 'चीन-रूस मैत्री संधि' की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। दोनों शीर्ष नेता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने पर बात करेंगे, बल्कि आर्थिक सहयोग और ''प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों'' पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद से, पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बीच रूस और चीन के रिश्ते बेहद गहरे हुए हैं। मुश्किल वक्त में चीन, रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक सहारा बनकर उभरा है।

व्लादिमीर पुतिन। फाइल

'प्रिय मित्रों' की मुलाकात पर दुनिया की नजर

पिछले साल सितंबर में जब पुतिन चीन गए थे, तब चिनफिंग ने उन्हें 'पुराना दोस्त' कहा था और पुतिन ने भी उन्हें 'प्रिय मित्र' कहकर पुकारा था। यह आत्मीयता आज के दौर में और अधिक प्रासंगिक हो गई है। ट्रंप ने अपनी यात्रा के दौरान चिनफिंग के साथ व्यापार और ईरान में जारी युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की थी। अब पुतिन की इस यात्रा से बीजिंग एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गया है। इस साल नवंबर में शेनझेन में होने वाले एपेक (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग) शिखर सम्मेलन में भी पुतिन शिरकत करेंगे, जो दर्शाता है कि बीजिंग और मास्को की यह जुगलबंदी आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली है।

आइएमएफ के भरोसे रक्षा बजट में 100 अरब की बढ़ोतरी की तैयारी में पाकिस्तान

2026-27 के लिए रक्षा खर्च 2.66 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये रहने का अनुमान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : कंगाली के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से मिले कर्ज के भरोसे अगले वित्त वर्ष में रक्षा बजट में 100 अरब पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार आइएमएफ समर्थित सुधार कार्यक्रम के तहत बजट तैयार कर रही है। 'डान' अखबार ने आइएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 2026-27 के लिए रक्षा खर्च 2.66 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष में 2.56 लाख करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट के अनुसार, आइएमएफ ने 2026-27 में पाकिस्तान की कुल संघीय आय 17.14 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये रहने का अनुमान लगाया है। यह मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने जून 2027 तक सभी संघीय और प्रांतीय सरकारी भुगतानों को डिजिटाइज करने का भी वादा किया है।

आइएमएफ के सुधारों के हिस्से के रूप में, सरकार इस साल के अंत तक भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा आशंका वाले 10 संस्थानों की पहचान करेगी। इन संस्थानों का विशेष आडिट और विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही, राज्यों की भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को भी और ताकत दी जाएगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के अलावा, पाकिस्तान की करीब 40 प्रतिशत आबादी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का एक दल पाकिस्तान के दौरे पर है।

प्रतीकात्मक

गंगा जल संधि का नवीनीकरण तय करेगा भारत व बांग्लादेश के संबंध : बीएनपी

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (बीएनपी) ने स्पष्ट किया है कि भारत के साथ देश के भविष्य के संबंध नई गंगा जल बंटवारा संधि पर निर्भर करेंगे। बीएनपी के महासचिव और मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने नई दिल्ली से बांग्लादेशी जनता की ''उम्मीदों और जरूरतों'' के अनुरूप तत्काल बातचीत शुरू करने की मांग की है।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 1996 में हस्ताक्षरित 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा संधि इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाली है। यह संधि तत्कालीन शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में हुई थी। आलमगीर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक नई संधि नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा समझौता प्रभावी रहना चाहिए। साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य के जल समझौते किसी निश्चित समय सीमा में बंधे नहीं होने चाहिए।

हमास ने सैन्य शाखा के चीफ हद्दाद के परिवार संग मारे जाने की पुष्टि की

यरुशलम, रायटर : गाजा में इजरायल ने शुक्रवार रात हवाई हमले में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख इज्ज अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया। मई 2025 में मुहम्मद सिनवार के मारे जाने के बाद से हद्दाद हमास की सैन्य शाखा की कमान संभाले हुए था। हद्दाद हमास के वरिष्ठतम लोगों में था और वह सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हुए हमले में प्रमुख भूमिका में था। 56 वर्षीय हद्दाद इजरायल और अमेरिका में द घोस्ट नाम से बदनाम था। हमास ने भी शनिवार को हद्दाद के मारे जाने की पुष्टि कर दी। हद्दाद के साथ पत्नी और 19 वर्ष की बेटी भी मारी गई है।

हमास ने अपने संक्षिप्त बयान में हद्दाद और उसके परिवार के मारे जाने का कारण नहीं बताया है। हद्दाद और उसके परिवारीजन का शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पता चला है कि शुक्रवार को हुए इजरायल के दो हमलों में कुल सात लोग मारे गए और 20 घायल हुए हैं। बताते हैं कि हद्दाद को निशाना बनाने के लिए इजरायल ने गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट और एक कार को निशाना बनाया। अपार्टमेंट एक हिस्से में हद्दाद परिवार के साथ मौजूद था और मारा गया।

कार्रवाई के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हद्दाद सात अक्टूबर, 2023 और उससे पहले भी इजरायली नागरिकों की हत्याओं में शामिल था, इसलिए उसका खात्मा कर दिया गया है।

इज्ज अल दीन अल हद्दाद। फाइल

गाजा सिटी के अपार्टमेंट में हमले में मारा गया, द घोस्ट के रूप में बदनाम आतंकी सरगना दफनाया गया

नेपाल के नए कस्टम नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

- बालेन शाह सरकार ने भारत से 100 रुपये के सामान लाने पर टैक्स लगाने का लिया था निर्णय
- नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, अगले आदेश तक विवादित प्रविधान को लागू न करें

काठमांडू, एएनआइः नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर भारत से सीमा पार आयातित 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के रोजमर्रा के सामान पर सीमा शुल्क वसूलने पर नेपाल सरकार को रोक दिया है। जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और जस्टिस टेक प्रसाद ढुंगाना की पीठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिपरिषद, नेपाल के वित्त मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक विवादित प्रविधान को लागू न करें। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से हाल ही में भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर कस्टम शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था।

न्यायालय का यह आदेश वित्त मंत्रालय के निर्णय को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका के जवाब में आया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाना सीमा शुल्क अधिनियम, 2024 के प्रविधानों के विपरीत है। दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को अंतिम फैसला सुनाए जाने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। नेपाल सरकार के इस विवादास्पद नियम के कारण भारत-नेपाल सीमा पर सीमा शुल्क चौकियों पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेपाल के बड़ी संख्या में नागरिक रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से भारतीय सीमावर्ती बाजारों में प्रवेश करते हैं। इस आदेश के बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है और चिप्स के पैकेट, बिस्कुट, मसाले और अन्य घरेलू सामान जैसी छोटी वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कदम का कड़ा विरोध हुआ, खासकर तराई-मधेस क्षेत्र में, जहां सीमा चौकियों पर नागरिकों और अधिकारियों के बीच अक्सर बहस और झड़पों की खबरें सामने आईं।

नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नेपाल की नई व्यवस्था से भारतीय बाजार प्रभावित

लखीमपुर खीरी संवाददाता के अनुसार, नेपाल सरकार की नई व्यवस्था से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नेपाली ग्राहकों की आवाजाही कम होने से पलिया, गौरीफंटा और बनगवां जैसे बाजारों में कारोबार लगभग ठप हो गया था, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। कोर्ट के इस फैसले से सीमा से लगे बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए नियम के कारण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के नेपाल से लगते दोनों देशों के बीच व्यापार ठहर गया था। व्यापारियों का कहना है कि नए नियमों के कारण सीमावर्ती बाजारों का कारोबार 50 प्रतिशत तक गिर गया था। छोटे दुकानदारों से लेकर होटल, किराना, कपड़ा और बर्तन कारोबारियों की बिक्री ठप हो गई थी।

भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को किया खारिज

- केंद्र बोला- 'अवैध' मध्यस्थता न्यायालय के सभी फैसले अमान्य, भारत ने दोहराया- सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी

नई दिल्ली, आइएएनएसः भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़े मामले में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (सीओए) के ताजा फैसले को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ''अवैध रूप से गठित'' है और उसके सभी फैसले अमान्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 15 मई को जारी फैसला अधिकतम जल संचयन से जुड़ा है और यह सिंधु जल संधि की व्याख्या से संबंधित पहले के फैसले का पूरक है। उन्होंने कहा कि भारत इस फैसले को उसी तरह खारिज करता है, जैसे पहले के सभी निर्णयों को खारिज किया गया था। जायसवाल ने कहा, ''भारत ने इस तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय को कभी मान्यता नहीं दी। इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय मान्य नहीं है।''

भारत ने यह भी दोहराया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला अब भी लागू है। सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता, तब तक संधि पर रोक जारी रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे से जुड़ी है। किशनगंगा और रैटल जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह मामला मध्यस्थता न्यायालय तक पहुंचा। भारत लगातार कहता रहा है कि इस न्यायाधिकरण का गठन ही संधि का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दबाव बनाने और आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए करता रहा है। पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना भी शामिल था।

प्रतीकात्मक

पीएम की अपील पर 10 में 6 भारतीय इस साल नहीं खरीदेंगे सोना

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध के चलते उत्पन्न संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस वर्ष सोना न खरीदने की अपील पर देशवासियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। आनलाइन सर्वे फर्म **लोकल सर्कल्स** द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, इस वर्ष आधे से अधिक भारतीयों ने सोना खरीदने से मना कर दिया है। इस सर्वेक्षण में 295 जिलों में 84,000 से अधिक सोने के मालिकों और खरीदारों से प्रतिक्रियाएं ली गईं।

सोने की खरीदारी पूरी तरह से बंद करने को तैयार मालिक व खरीदार

61% एक साल तक सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर देंगे

28% सोने की खरीद में काफी कमी करेंगे

7% केवल विवेकाधीन सोने की खरीद को स्थगित करेंगे

8% शादियों या पारिवारिक परंपराओं के लिए सोना खरीदना जारी रखेंगे

7% ने कहा कि वे आभूषण खरीदने के बजाय डिजिटल सोना, ईटीएफ या सावरेन गोल्ड बान्ड्स (एसजीबी) में निवेश करेंगे

1% ने कह नहीं सकते का विकल्प चुना

8% ने कहा कि वे निवेश के रूप में सोना खरीदना जारी रखेंगे

13% का कहना है कि पीएम की अपील का उनके सोने की खरीदारी के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

इसलिए जारी रखेंगे सोना खरीदना

सोने की खरीदारी जारी रखने वाले खरीदारों के छोटे वर्ग के लिए, शादी और पारंपरिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ अनिश्चित समय में निवेश की सुरक्षा प्रमुख प्रेरक बनी हुई है। सर्वेक्षण में शामिल 19 प्रतिशत ने अपील के बावजूद सोना खरीदने के पीछे की वजह शादी या पारिवारिक परंपरा को बताया। 19 प्रतिशत ने कहा कि अनिश्चित समय में सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। 17 प्रतिशत ने कहा कि वे तभी खरीदेंगे जब आवश्यक होगा, जबकि छह प्रतिशत ने कहा कि सोने की कीमतों में और वृद्धि होने का डर उनकी खरीदारी को प्रेरित करेगा। उल्लेखनीय रूप से 36 प्रतिशत ने कहा कि वे सोना बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तीन प्रतिशत ने ''कह नहीं सकते'' का विकल्प चुना।

सोने की खरीद में कमी के आर्थिक लाभों को लेकर जागरूकता

सर्वेक्षण में मिली प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि नागरिक सोने की खरीद में कमी के आर्थिक लाभों को काफी हद तक महत्वपूर्ण मानते हैं, साथ ही आभूषण क्षेत्र और उससे संबंधित रोजगार पर संभावित प्रभाव को भी समझते हैं।

66% ने माना की सोना न खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद मिलेगी

51% ने कहा कि इससे रुपये और आयात पर दबाव कम होगा

46% ने कहा कि इससे वैश्विक अनिश्चितता के दौरान अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी

35% का मानना था कि इससे आभूषण उद्योग और उससे संबंधित नौकरियों को नुकसान होगा

27% ने कहा कि सरकार को नीतिगत सुधारों पर ध्यान देना चाहिए

15% ने कहा कि नागरिकों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

10% का मानना था कि इससे परिवारों की वित्तीय सुरक्षा कम हो जाएगी

10% ने कहा कि इसका प्रभाव नगण्य होगा।

6% ने कह नहीं सकते

बल्लेबाज	रन
साई सुदर्शन	553
शुभमन गिल	552
हेनरिक क्लासेन	508

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	22
कैगिसो रबादा	21
अंशुल कंबोज	19

फिन एलन ने बिगाड़ा गुजरात का दिन

प्लेआफ की दहलीज पर खड़े गुजरात को 29 रनों से हराकर कोलकाता ने जीवित रखी अंतिम चार में पहुंचने की आस

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

शाट लगाते फिन एलन ● प्रेट्र

कोलकाता: लगातार पांच जीत दर्ज कर ईडन गार्डेंस स्टेडियम पहुंचा गुजरात टाइटंस यहीं से प्लेआफ में जगह पक्की करने को बेताब था, लेकिन कोलकाता के आरंभिक बल्लेबाज फिन एलन (93) ने आतिशी बल्लेबाजी कर उसके इंतजार को बढ़ा दिया है। वहीं अंतिम चार में पहुंचने की अपनी टीम की उम्मीदों को भी जीवित रखा है। फिन का अंगकृष रघुवंशी (अविजित 82) ने पूरा साथ दिया। कैमरन ग्रीन (52) ने भी शानदार पारी खेली। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में मात्र दो विकेट पर 247 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात इतने ओवर में चार विकेट खोकर 218 रनों तक पहुंच पाई। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल (85) व विकेटकीपर जोस बटलर (57) ने दूसरे विकेट के लिए 128 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम की जीत का छक्का लगाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कोलकाता की ओर से खड़ा किए गए रनों का पहाड़ नहीं चढ़ पाए। कोहनी की चोट के कारण पवेलियन लौट गए सुदर्शन ने (अविजित 53) भी गिल का विकेट गिरने के बाद क्रीज पर लौटकर मैच जिताने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। कोलकाता के बल्लेबाजों के साथ पदार्पण मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज सौरव दुबे ने 19वें ओवर में मात्र पांच रन दिए व बटलर का विकेट चटकाया। इस ओवर के समापन के बाद कोलकाता की जीत लगभग पक्की हो गई थी। कोलकाता का आइपीएल में यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सर्वोच्च स्कोर 272 रनों का है, जो उसने 2024 में दिल्ली के विरुद्ध विशाखापत्तम में बनाया था। कोलकाता के इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाने का एक प्रमुख कारण गुजरात का लचर क्षेत्ररक्षण भी रहा। गुजरात के खिलाड़ियों ने चार-चार कैच टपकाए, वो भी महत्वपूर्ण मौकों पर। वर्तमान सत्र में कोलकाता का यह सर्वोच्च स्कोर है।

फिन ने दिखाया फन: सत्र के आरंभिक मैचों में विफल रहे कीवी बल्लेबाज एलन फिन अब लय में आ गए हैं। उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर 93 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 21 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम में मौजूद कोलकाता के समर्थक उनकी बल्लेबाजी देख झूम उठे। चुनाव खत्म होने के बाद कोलकाता में हुए पहले मैच में फिन की बल्लेबाजी ने उन्हें तरोताजा कर दिया। फिन ने गुजरात के किसी गेंदबाज को नहीं बख्शा। उन्होंने राशिद खान का स्वागत दो छक्कों व एक चौके से किया। इसी तरह अरशद खान के पहले ही ओवर में तीन छक्के व एक चौका जड़ा। फिन ने शेष 43 रन मात्र 14 गेंदों पर बनाए। हालांकि फिन को दो बार जीवनदान भी मिला। पहले सिराज की गेंद पर होल्डर व उसके बाद होल्डर की गेंद पर सिराज ने उनका कैच छोड़ा।

अंगकृष का जलवा: अंगकृष ने मात्र 44 गेंदों पर अविजित 82 रनों की एक और लाजवाब पारी खेल सत्र का पांचवां अर्धशतक जड़ा। उनकी पारी में चार चौके व सात छक्के शामिल रहे। अंगकृष ने 2022 में हुए अंडर-19 विश्व कप में ही भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाकर अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। उनका खेल सुधारने में अभिषेक नायर की अहम भूमिका रही है, जो वर्तमान में कोलकाता टीम के कोच भी हैं। ग्रीन ने भी 28 गेंदों पर अविजित 52 रन बनाए।

सिराज के 200 विकेट: सिराज ने अपने तीसरे ओवर में रहाणे को बोल्ड आउट कर टी-20 क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए। सिराज इस सत्र में शानदार फार्म में हैं। वे अब तक 14 विकेट चटका चुके हैं। वहीं, केकेआर ने गुजरात के विरुद्ध मैच में एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। वह घरेलू मैदान में 100 मैच खेलने वाली आइपीएल की दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले आरसीबी ने घरेलू मैदान में 100 मैच खेले हैं। वहीं सुनील नारायण का यह 200वां मैच था।

स्कोर बोर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स: 247/2 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
रहाणे बो. सिराज	14	14	1/1
एलन का. राशिद बो. किशोर	93	35	4/10
अंगकृष अविजित	82	44	4/7
ग्रीन अविजित	52	28	3/4

अतिरिक्त: 6 (लेबा: 1, नोबा: 1, वा: 4)

विकेटपतन: 1-44 (रहाणे, 4.3), 2-139 (एलन, 11.2)
गेंदबाजी: सिराज 4-0-50-1, रबादा 4-0-40-0, होल्डर 4-0-39-0, राशिद 4-0-57-0, किशोर 3-0-38-1, अरशद 1-0-22-0

गुजरात टाइटंस: 218/4 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
सुदर्शन अविजित	53	28	6/3
शुभमन का. अनुकूल बो. सुनील	85	49	5/7
निशांत का. मनीष बो. सुनील	1	4	0/0
बटलर का. सब बो. सौरव	57	35	5/2
तेवतिया का. अंगकृष बो. ग्रीन	2	4	0/0

अतिरिक्त: 20 (बा: 1, लेबा: 8, वा: 11)

विकेटपतन: 1-49 (निशांत, 4.1), 2-177 (शुभमन, 16.2), 3-207 (बटलर, 18.5), 4-218 (तेवतिया, 19.6), गेंदबाजी: सौरव 2.4-0-23-1, ग्रीन 3-0-25-1, कार्तिक 4-0-59-0, पथिराना 1.2-0-9-0, सुनील 4-0-29-2, वरुण 4-0-47-0, अनुकूल 1-0-17-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद्द	नेट रन रेट	अंक
1	आरसीबी	12	8	4	0	+1.053	16
2	गुजरात	13	8	5	0	+0.400	16
3	हैदराबाद	12	7	5	0	+0.331	14
4	पंजाब	12	6	5	1	+0.355	13
5	राजस्थान	11	6	5	0	+0.082	12
6	चेन्नई	12	6	6	0	+0.027	12
7	कोलकाता	12	5	6	1	-0.038	11
8	दिल्ली	12	5	7	0	-0.993	10
9	मुंबई (E)	12	4	8	0	-0.504	8
10	लखनऊ (E)	12	4	8	0	-0.701	8

आज हारी तो दिल्ली हो जाएगी बाहर

लोकेश शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को होने वाला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रायल्स का मुकाबला घरेलू टीम के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आया है। इस मैच में हारने वाली टीम के लिए प्लेआफ की राह लगभग बंद हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम अपनी उम्मीदों को मजबूती दे सकेगी।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। 12 मैचों में पांच जीत के साथ उसके 10 अंक हैं और वह अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। यदि दिल्ली यह मैच हारती है तो उसका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। जीत दर्ज करने पर भी दिल्ली की किस्मत अन्य टीमों के परिणामों पर निर्भर रहेगी। उसे उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स अपने दोनों शेष मैच हार जाए, राजस्थान लगातार हार झेले और चेन्नई सुपर किंग्स को भी अगले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़े। दूसरी ओर राजस्थान रायल्स 11 मैचों में 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। यदि वह दिल्ली को हराने में सफल रहती है तो सीधे शीर्ष चार में पहुंच जाएगी। हालांकि टीम लगातार दो हार के बाद दबाव में है। एक मई को दिल्ली के हाथों हारने के बाद उसे 9 मई को गुजरात टाइटंस ने भी शिकस्त दी थी।

जल्द आउट करना सबसे बड़ी चुनौती: राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे हैं, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। दिल्ली के गेंदबाजों के सामने उन्हें जल्द आउट करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि राजस्थान का मध्यक्रम जुरैल, हेटमायर और रियान पराग के खराब प्रदर्शन से चिंता में है। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ही लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं। वहीं, दिल्ली की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है।

वैभव सूर्यवंशी | केएल राहुल

सवालों से बचने को पंजाब ने हेड फिजियो को किया आगे

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: महत्वपूर्ण मुकाबले से ठीक पहले पंजाब किंग्स और आरसबी के बीच धर्मशाला में होने वाले सीजन तय करने वाले मैच से पहले पंजाब ने अपने हेड फिजियो एंड्रयू लेपस को प्रेस कान्फ्रेंस के लिए भेजा। शनिवार को करीब एक दर्जन पत्रकार एचपीसीए स्टेडियम पहुंचे थे। उनके पास सवाल थे। ऐसे सवाल, जो लगातार पांच हार के बाद नाकआउट जैसी स्थिति वाले मुकाबले से पहले अपने आप बन जाते हैं। टीम कांबिनेशन, ड्रेसिंग रूम दबाव और ट्रेनिंग में क्या बदलाव किए गए हैं। जब लेपस से टास के महत्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह शायद मेरे कार्यक्षेत्र से थोड़ा बाहर है। टीम की लगातार हार पर भी उन्होंने कहा यह मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है।

आरसीबी के सामने पंजाब किंग्स की होगी अग्निपरीक्षा

नीरज व्यास ● जागरण

धर्मशाला: आइपीएल-2026 अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। जाहिर है प्लेआफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष भी बढ़ गया है। वहीं, अंक तालिका में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इस लिहाज से धर्मशाला के सर्द मौसम में आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जाने वाला मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। 17 मई को आरसीबी एक तरह से पंजाब की कठिन अग्निरीक्षा लेगा। इस मैच में जो जीता उसकी प्लेआफ में राह सुगम हो जाएगी। अगर बाजी आरसीबी के हाथ लगती है तो उसका दावा और मजबूत हो जाएगा। आरसीबी चाहेगी कि इस मैच को जीत कर प्लेआफ का दावा और पुख्ता कर लिया जाए। वहीं, अगर पंजाब हारा तो उसके लिए प्लेआफ के दरवाजे करीब-करीब बंद हो जाएंगे। धर्मशाला में अब तक पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच दो मुकाबले खेले गए हैं। दोनों ही टीमों ने एक-एक मैच जीता है। पहला मुकाबला 2013 में खेला गया था इसमें पंजाब ने आरसीबी पर 111 रनों से रिकार्ड जीत दर्ज की।

अफगानिस्तान सीरीज में बुमराह के चयन पर नजरें

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करने वाले जसप्रीत बुमराह अगले महीने अफगानिस्तान के विरुद्ध होने वाली सीरीज में या तो एकमात्र टेस्ट मैच खेलेंगे या फिर तीन मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय चयन समिति 19 मई को टीम घोषित करने को लेकर बुमराह के कार्यभार पर विशेष नजर रखे हुए है।

जसप्रीत बुमराह

छह से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेले जाने वाला एकमात्र टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। इसके बाद वनडे सीरीज के मुकाबले 14 जून (धर्मशाला), 17 जून (लखनऊ) और 20 जून (चेन्नई) में आयोजित होंगे। यह द्विपक्षीय वनडे सीरीज इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल इसी प्रारूप में खेलते नजर आते हैं। इस सीरीज के लिए दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का नाम भी चयन बैठक में चर्चा का विषय बन सकता है। विजय हजारे ट्राफी के पिछले सत्र में उन्होंने आठ मैचों में 17 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। वहीं इस आइपीएल में 16 विकेट लेकर प्रभावित किया है। हर्षित राणा के जल्द फिट होने की संभावना कम होने के कारण प्रिंस को आजमाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, बुमराह अगर टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा। वहीं, अगर वे वनडे मुकाबलों में उतरते हैं तो टेस्ट से विश्राम मिल सकता है। वहीं देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन की जगह मौका मिल सकता है। इस स्थान के लिए वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल भी विकल्प माने जा रहे हैं। टेस्ट में बुमराह की अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मौका मिल सकता है।

अब मैदान में पर्ची निकालकर क्रिकेटर कह रहे 'मन की बात'

शेखर झा ● जागरण

नई दिल्ली: अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे आइपीएल के इस सत्र में बल्लेबाजों ने विस्फोटक पारियां खेलते हुए कई पुराने रिकार्ड ध्वस्त किए, जबकि गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया लेकिन इन शानदार प्रदर्शनों के बीच खिलाड़ियों के जश्न मनाने का नया अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले खिलाड़ी अपने प्रदर्शन या भावनाओं को प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये साझा करते थे, लेकिन अब मैदान पर ही पर्ची सेलिब्रेशन नया ट्रेंड बन चुका है। खिलाड़ी विकेट लेने या शतक जमाने के बाद जेब से हाथ से लिखी पर्ची निकालते हैं और कैमरे के सामने उसे दिखाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इतना ही नहीं, मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर भी इस अंदाज को अपनाते नजर आए हैं। लखनऊ-चेन्नई मुकाबले के दौरान कमेंटेटर सुनील गावस्कर, पामी बांग्वा और इयान बिशप कमेंट्री कर रहे थे। इस दौरान पामी बांग्वा ने जेब से पर्ची निकालकर दिखाई।

पर्ची दिखाते उर्विल पटेल ● फाइल फोटो

रघु ने चलन को बढ़ाया आगे: आइपीएल 2026 में पर्ची सेलिब्रेशन ट्रेंड को आगे बढ़ाने का काम रघु शर्मा ने किया। मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध मुकाबले में अपने आइपीएल करियर का पहला विकेट हासिल किया। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस सफलता के बाद रघु ने जेब से हाथ से लिखी पर्ची निकाली। उस पर्ची पर लिखा था कि राधे-राधे, 15 साल का दर्दनाक इंतजार। गुरुदेव की कृपा से आज खत्म हुआ। मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस का शुक्रिया। इसके बाद उर्विल ने भी लखनऊ के विरुद्ध 13 गेंदों में अर्धशतक जड़कर पर्ची दिखाई और लिखा कि यह आपके लिए है पापा। वहीं, आकाश सिंह ने भी अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद पर्ची सेलिब्रेशन किया। लखनऊ के तेज गेंदबाज आकाश ने सीएसके के विरुद्ध मुकाबले में तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके। विकेट लेने के बाद आकाश ने जो पर्ची दिखाई, उस पर लिखा था कि अक्की को टी-20 क्रिकेट में विकेट लेना आता है, ऐसा है ना।

पर्ची सेलिब्रेशन का विरोध भी शुरू: एक शो पर चर्चा करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह पर्ची सेलिब्रेशन हास्यास्पद है। मेरी नजर में पर्ची सेलिब्रेशन पर बैन लगना चाहिए। वहीं, द. अफ्रीका के डेल स्टेन ने भी नाराजगी जाहिर की।

2025 में हुई थी पर्ची सेलिब्रेशन की शुरुआत

आइपीएल में पर्ची सेलिब्रेशन की शुरुआत पिछले सत्र में हुई थी। सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के विरुद्ध तूफानी बल्लेबाजी की थी। शतक पूरा करने के बाद अभिषेक ने जेब से एक पर्ची निकाली, जिस पर लिखा था कि यह आरेंज आर्मी के लिए है। वहीं, इस जश्न को लेकर अभिषेक ने कहा था कि शिखर धवन ने मुझसे कहा था कि कल्पना को सच मानना बहुत जरूरी है, बस यह कल्पना करो कि तुमने वह काम पहले ही कर लिया है। इस बारे में बात करने के लिए उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था।

पर्ची दिखाते आकाश सिंह ● फाइल फोटो

खेल डायरी

विश्व विजय अभियान के लिए निकलने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के भस्मआरती दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी टीम ने जीत के लिए प्रार्थना की ● नईदुनिया

नेशनल डबल्स स्क्वाश में जीते सेंथिलु-जोशना

चेन्नई, प्रेट्र: शीर्ष वरीय वेलवन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा ने शनिवार को तीसरी एचसीएल नेशनल डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए मिक्सड डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जोड़ी ने इंडियन स्क्वाश एकेडमी में हुए एक कड़े मुकाबले वाले फाइनल में दूसरी वरीय जोड़ी अभय सिंह और राधिका सीलन को 11-7, 11-9 से हराया। इससे पहले टूर्नामेंट में सेंथिलकुमार और जोशना दोनों ने ही अपने-अपने पार्टनर के साथ मिलकर क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के डबल्स का खिताब भी जीता था। सेंथिलकुमार ने अभय के साथ जोड़ी बनाकर पुरुषों के डबल्स का खिताब लगातार तीसरे साल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में दूसरी वरीय जोड़ी राहुल बैथा और सूरज कुमार चंद को 11-8, 11-5 से हराया। महिलाओं के डबल्स फाइनल में जोशना और राधिका ने जेनेट विधि और पूजा आरती को 11-8, 11-4 से हराकर खिताब जीता।

मेदवेदेव को हराकर फाइनल में सिनर

रोम, एपी: दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी जानिक सिनर ने बारिश से बाधित मुकाबले और शारीरिक परेशानियों के बावजूद शानदार वापसी करते हुए डेनियल मेदवेदेव को 6-2, 5-7, 6-4 से हराकर इटेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली। अब उनका मुकाबला फाइनल में कैस्पर रूड से होगा। सिनर ने शनिवार को बारिश के कारण रुके सेमीफाइनल मुकाबले के दोबारा शुरू होने पर मेडवेडेव को हराकर अपनी लगातार जीतों का सिलसिला 28 मैचों तक पहुंचा दिया। सिनर अब इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। अगर वह रोम मास्टर्स जीत लेते हैं तो वह नोवाक जोकोविक के बाद सभी नौ मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे। एकमात्र रोम मास्टर्स टूर्नामेंट को सिनर अब तक नहीं जीत सके हैं।

मोहसिन नकवी को आइपीएल फाइनल का न्योता नहीं मिला

मोहसिन नकवी

नई दिल्ली, प्रेट्र: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी को अहमदाबाद में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) फाइनल के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की सालाना बोर्ड बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। पता चला है कि नकवी आइसीसी निदेशक बोर्ड की बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। यह सुविधा उन सदस्य प्रतिनिधियों के लिए हमेशा से मौजूद रही है जो यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। आइसीसी की यह बैठक असल में पिछले महीने दोहा में होने वाली थी, लेकिन पश्चिम एशिया के संकट की वजह से इसे टालना पड़ा था। सूत्रों ने बताया कि नकवी के बैठक में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी और उनका वर्चुअल तरीके से शामिल होना आइसीसी के सामान्य चलन के मुताबिक ही है। नकवी उन तीन सदस्यों में से एक हैं जो इस बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। यह कांफ्रेंस इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अहमदाबाद में आइपीएल फाइनल के साथ ही होगी जिसमें अलग-अलग क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष प्रशासकों के मौजूद रहने की उम्मीद है।

मलेशियाई जोड़ी को हराकर सात्विक-चिराग फाइनल में

बैंकाक, प्रेट्र: सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने तीन गेम के रोमांचक मुकाबले में मलेशिया के गोह जे फेइ और नूर इजुद्दीन को हराकर थाइलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरूष डबल्स फाइनल में प्रवेश कर लिया। दुनिया की चौथे नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग ने नौवीं रैंकिंग वाली मलेशियाई जोड़ी को 82 मिनट में 19-21, 22-20, 21-16 से हराया। भारतीय जोड़ी ने 2019 और 2024 में खिताब जीता था और तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। अब सात्विक और चिराग का सामना इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नांडो और डेनियल मार्टिन या चीन के हि जि तिंग और रेन शियांग यू की जोड़ी से होगा।

पीएम ने भारतीय हाकी में डच कोचों को सराहा

नीदरलैंड्स में पीएम मोदी ● एएनआइ

नीदरलैंड्स के अपने दौरे पर पीएम ने भारतीय महिला हाकी टीम के कोच शोर्ड मारिन की खास तौर पर तारीफ की

हेग, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड्स दौरे पर अपने भाषण में भारतीय हाकी में डच कोचों के योगदान का जिक्र किया और महिला हाकी टीम के मौजूदा कोच शोर्ड मारिन की खास तौर पर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि नीदरलैंड्स और भारत के बीच दोस्ती की एक और कड़ी है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती और वह है खेल। हम दोनों देश खेलों के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हाकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा योगदान है। भारतीय हाकी को और निखारने में डच कोचों की भी मेहनत रही है। हमारी महिला हाकी टीम के शानदार प्रदर्शन में कोच शोर्ड मारिन की अहम भूमिका है। मारिन टोक्यो ओलिंपिक 2020 में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हाकी टीम के भी कोच थे। इस समय उनके मार्गदर्शन में टीम विश्व कप और एशियाई खेलों की तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री के बयान पर मारिन ने कहा कि इससे उन्हें और उनकी टीम को विश्व कप समेत आगामी टूर्नामेंटों में और बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। मारिन से पहले नीदरलैंड्स के रोलेंट ओल्टमेंस भी भारतीय पुरूष हाकी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से इस वर्ष नीदरलैंड्स की सह मेजबानी में 15 अगस्त से होने वाले हाकी विश्व कप में भारतीय टीम की हौसलाअफजाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप सभी को भारत के मैच देखने जरूर जाना है। ये बात पक्की है कि विश्व कप जो भी टीम जीते, लेकिन इसमें भारत और नीदरलैंड्स की दोस्ती जरूर जीतेगी। पीएम ने नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय मूल के खिलाड़ियों के योगदान की भी सराहना की।

मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को हराकर जीता एफए कप

फुटबाल डायरी

ट्राफी के साथ जश्न मनाती मैनचेस्टर सिटी की टीम ● एपी

लंदन, एपी: एंटोनी सेमेन्यो के करिश्माई गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप फाइनल में शनिवार को वेंबली स्टेडियम में चेल्सी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। फारवर्ड खिलाड़ी सेमेन्यो ने दूसरे हाफ में शानदार 'बैक-हील' गोल से इस मैच का रुख तय किया। मुकाबले में 72वें मिनट में एर्लिंग हालैंड के क्रास पर सेमेन्यो ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए एड़ी से गेंद को दिशा दी, जो चेल्सी के गोलकीपर राबर्ट सांचेज को छकाते हुए गोलपोस्ट के अंदर चली गई। जीत से सिटी घरेलू ट्राफी हैटट्रिक की दौड़ में बनी हुई है, क्योंकि वह पहले ही इंग्लिश लीग कप जीत चुकी है। सिटी में 10 साल के कार्यकाल में गार्डियोला की यह 17वीं बड़ी ट्राफी है। सिटी आठवीं बार एफए कप जीकर सर्वकालिक विजेताओं की सूची में चेल्सी, लिवरपूल और टाटेनहम के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

केन की हैटट्रिक से सीजन का आखिरी मैच जीता म्यूनिख: बुंडेसलीगा के शीर्ष स्कोरर हैरी केन ने हैटट्रिक जमाकर चैंपियन बायर्न म्यूनिख को शनिवार को लीग के आखिरी मैच में मेहमान टीम कोलोन पर 5-1 से शानदार जीत दिलाई। केन ने 10वें मिनट में बढ़त दिलाई और फिर तीन मिनट बाद फ्री किक से इसे दोगुना कर दिया। उन्होंने 69वें मिनट में गोल करके अपनी हैटट्रिक पूरी की।

सत्र के अंत में बार्सिलोना छोड़ देंगे लेवांदोव्स्की

बार्सिलोना, एपी: पौलेंड के स्ट्राइकर राबर्ड लेवांदोव्स्की इस सत्र के आखिरी में बार्सलोना छोड़ देंगे। स्पेनिश क्लब ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। लेवांदोव्स्की की उम्र इस अगस्त में 38 साल हो जाएगी। उनका करार खत्म होने वाला था। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वह क्लब छोड़ देंगे। 2022 में बायर्न म्यूनिख को छोड़कर बार्सिलोना से जुड़ने के बाद से उन्होंने इस क्लब को तीन स्पेनिश लीग खिताब और एक कोपा डेल रे खिताब जीतने में मदद की है। लेकिन क्लब के लिए 191 मैचों में 119 गोल करने के शानदार रिकार्ड के बावजूद वह इस सीजन में कोच हांसी फ्लिक की पहली पसंद वाले स्ट्राइकर का दर्जा खो बैठे हैं।

हाकी इंडिया ने यौन दुराचार के आरोपों पर स्टाफ सदस्य हटाया

पुरुष सब-जूनियर टीम से जुड़ा है मामला, हाकी इंडिया ने बयान जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की

नई दिल्ली, आइएएनएस: हाकी इंडिया में एक और विवाद सामने आया है। भारतीय पुरुष सब-जूनियर टीम के कोचिंग स्टाफ के एक सदस्य को यौन दुराचार के आरोपों के बाद भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय शिविर से हटा दिया गया है। यह घटना उसी दिन हुई जब भारत की अंडर-18 टीम भोपाल में अपने घरेलू मैदान पर आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलने वाली थी। हाकी इंडिया ने आधकारिक बयान जारी कर इस कार्रवाई की पुष्टि की है।

जानकारी के मुताबिक, सपोर्ट स्टाफ सदस्य सुधीर गोल्ला को रांची के मोराबादी स्थित एकलव्य बायज एंड गर्ल्स हाकी ट्रेनिंग सेंटर से उनके विरुद्ध शिकायतें सामने आने के बाद जाने के लिए कहा गया। झारखंड के खेल और युवा मामले निदेशालय में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें सेंटर आफ एक्सीलेंस में अपने कार्यकाल के दौरान गोल्ला पर कर्तव्य की उपेक्षा और यौन दुराचार के आरोप लगाए गए थे। 11 मई के एक आधिकारिक आदेश से पुष्टि हुई है कि गोल्ला को रांची में उनके पद से पहले ही हटा दिया गया था। केंद्र में उनकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए एक महिला कोच को नियुक्त किया गया है।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

हम जिन्हें क्षेत्रीय दल कहते थे, अब राजनीति शास्त्र की भाषा में इन्हें 'स्टेट पार्टीज' कहते हैं। इनका दायरा भले ही एक राज्य तक सीमित होता है, लेकिन वह राज्य की पहचान को लेकर राष्ट्रीय दलों से मुकाबला करते हैं। भारत जैसे देश में हर राज्य के विकास के लिए इनकी भूमिका अहम है।

दल क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, उन्हें हर 15 साल में नए नेतृत्व और सोच की जरूरत

सप्ताह का साक्षात्कार

हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी और भूमिका मुख्य रूप से सामने आई है। खासतौर पर तमिलनाडु में टीवीके के विजय और फिर बहुमत हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर कई पहलू सामने आए। एक ओर जहां कुछ समय पहले तक क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने की बात कही जा रही थी, वहीं एक नए क्षेत्रीय दल 60 साल की द्रविड़ राजनीतिक विरासत को संभालने वाले दो क्षेत्रीय दलों को हराकर खुद उस पर काबिज हो गया। इसके बाद क्षेत्रीय दलों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है। जाने-माने शिक्षाविद् और राजनीति शास्त्री **डा. सुहास पलशीकर** का कहना है कि क्षेत्रीय दल हमारी राजनीति का हिस्सा हैं। वह उभरते-सिमटते रहेंगे। अगले दस साल तक तो उनके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं दिखता है। हां, एक बात जरूर है कि क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, दोनों ही राजनीतिक दलों को हर 15 साल में नए नेतृत्व और सोच की जरूरत है। यदि उन्होंने खुद को नए सिरे से नहीं गढ़ा तो वह सिमटती चली जाएंगी। डा. पलशीकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। वह 'स्टडीज इन इंडियन पालिटिक्स' समूह से जुड़े हुए हैं, जो भारत में चुनावी राजनीति, मतदान व्यवहार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सतत अध्ययन करता है। डा. पलशीकर शिकागो यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया सेंटर और प्रोविडेंस में ब्राउन यूनिवर्सिटी के ब्राउन इंडिया इनिशिएटिव में विजिटिंग स्कालर भी रहे हैं। दैनिक जागरण की समाचार संपादक **रुमनी घोष** ने उनसे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का इतिहास, आचार-व्यवहार, जवाबदेही और बढ़ते-घटते दायरे पर आनलाइन चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

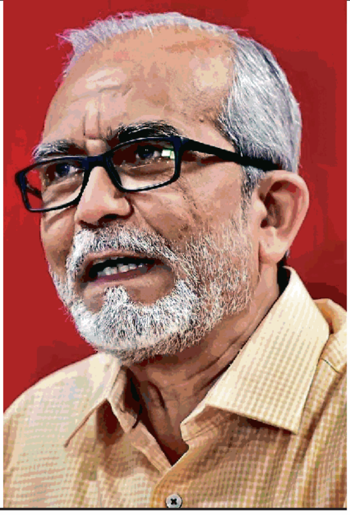

● जब लग रहा था कि देशभर में क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व खो रहे हैं तो तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपर स्टार थलपति विजय की पार्टी टीवीके का उदय क्या संकेत दे रहे हैं?

– क्षेत्रीय दलों पर अध्ययन के लिए यह उदाहरण सबसे सटीक है। भारत में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व आजादी के पहले से है, लेकिन आजादी के बाद उन्हें सत्ता तक पहुंचने का रास्ता इसी राज्य से ही तैयार हुआ। तमिलनाडु में ही सी.एन. अन्नादुरई के नेतृत्व में द्रमुक (डीएमके) ने 1967 में पहली बार कांग्रेस को हराकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। देश में पहली बार किसी क्षेत्रीय दल ने सरकार बनाई थी। उसके बाद लगभग 60 साल तक दो क्षेत्रीय दलों द्रमुक (डीएमके) और अन्नाद्रमुक (एआइडीएमके) का ही कब्जा रहा है। टीवीके अभी खुद क्षेत्रीय दल है और दो क्षेत्रीय दलों को हराकर सत्ता तक पहुंची है। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बना हुआ है और आगे भी रहेगा।

● टीवीके को छोड़ दें, तो बंगाल से टीएमसी, बिहार से आरजेडी, ओडिशा से बीजेडी, पंजाब से अकाली दल सहित कई उदाहरण हैं, जिसमें क्षेत्रीय दल सत्ता से बाहर हो गए और अपना आधार खो रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर संकट नहीं?

– क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति का हिस्सा हैं। आजादी के पहले क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व था। आजादी से पहले गठित प्रमुख क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल (1920 में स्थापित) और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस (1939 में 'आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कान्फ्रेंस' के रूप में स्थापित, बाद में नाम परिवर्तन) प्रमुख थे। अधिकांश क्षेत्रीय दल आजादी के बाद 1952 से 1970 के बीच कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरे। आजादी के बाद जब भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ने लगीं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) जैसी पार्टियों के साथ क्षेत्रीय दलों का वास्तविक उदय और विस्तार शुरू हुआ।

● क्या आपको नहीं लगता कि आज क्षेत्रीय दलों की भूमिका सत्ताधारी दलों से सौदेबाजी तक सीमित होती जा रही है। चर्चा है कि तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने की आड़ में कई क्षेत्रीय दलों ने मंत्री पद का सौदा किया। इससे पहले उप्र, महाराष्ट्र व बिहार चुनाव में यह परिदृश्य देख चुके हैं?

– मैं यह नहीं कहूंगा कि सौदेबाजी कर क्षेत्रीय दल सही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आदर्श का चश्मा पहनकर देखना गलत होगा। राजनीति में सौदेबाजी सामान्य प्रक्रिया है। क्या राष्ट्रीय दलों में सौदेबाजी नहीं होती है? जिस विधायक का जितने बड़े क्षेत्र में 'दबाव-प्रभाव' रहता है, वह अपनी ही सरकार से सौदेबाजी कर मंत्री पद ले लेता है। मैंने बहुत पहले अपने एक लेख में लिखा था कि क्षेत्रीय दलों को न खलनायक बनाने की जरूरत है और न ही उन्हें बहुत आदर्श या बेहतर विकल्प मान लेना उचित है। हर राजनीतिक दल की तरह इनमें भी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों है।

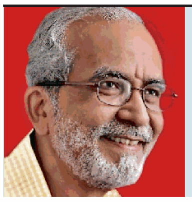

● आप लोग मतदान व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। क्या ऐसा कोई फार्मूला है, जिस पैटर्न से चुनाव कर मतदाता अपने लिए बेहतर सरकार चुन सकती है? यानी स्थायी सरकार के लिए एकतरफा मतदान ज्यादा बेहतर है या सभी दलों की भागीदारी को चुनें?

– नहीं, इसका कोई स्थायी फार्मूला न तो है और न ही हो सकता है। यह देश-काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारे सामने 1990 का दौर है, जब अस्थायी सरकारों द्वारा उदारीकरण सहित कई ऐसे कदम उठाए गए, जिन्हें आगे आने वाली स्थायी सरकारों ने भी अपनाया और आज भी जारी है। वहीं ऐसे भी उदाहरण हैं कि स्थायी सरकारें अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद बहुत बेहतर प्रयास नहीं कर पाईं। मतदान का व्यवहार उस समय की परिस्थितियों और मतदाता के मनोभावों पर ही निर्भर करता है।

● क्षेत्रीय दलों में वंशवाद या एक ही परिवार का प्रभाव रहता है। ऐसे में यह निजी महात्वकांक्षाएं पूरी करने का जरिया बन गया है? इस पर आपकी क्या राय है?

– निश्चित रूप से क्षेत्रीय दलों में से एक, अकाली दल को छोड़ दें, तो अधिकांश दलों में एक ही व्यक्ति या परिवार हावी है। यहां तक कि उनके राजनीतिक दलों को भी उनके नाम से ही जाना जाता है...जैसे मुलायम सिंह की, लालू यादव, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी आदि इसके उदाहरण हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू भी कहीं न कहीं इसी दायरे में है। सरकार में होने के बावजूद पार्टी के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई सुदृढ़ नेतृत्व नहीं है। इन सभी क्षेत्रीय दलों की दलगत राजनीति इनके इर्द-गिर्द घूमती रही है। हो सकता है कि सभी में 'कुर्सी' पाने की महत्वाकांक्षाएं रही हो, लेकिन इनमे नेतृत्व क्षमता थी और सभी ने तात्कालिक मुद्दे उठाए थे, इसलिए जनता ने इन्हें चुना। अब जनता इन्हें इसलिए नकार रही है, क्योंकि न तो ये नेता नया नेतृत्व दे पा रहे हैं और न ही नए सोच के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दरअसल, हर क्षेत्रीय दल की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्हें बार-बार खुद को नए सिरे से गढ़ना चाहिए, वरना वह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे।

● आपने क्षेत्रीय दलों को खुद को नए सिरे गढ़ने की सलाह दी है। यह काम उन्हें कितने-कितने साल बाद करना चाहिए ?

– सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दलों के लिए भी यह सलाह है कि हर 15 साल के अंतराल में नई लीडरशिप (नेतृत्व) खड़ी करनी चाहिए और नए सोच के साथ जनता के बीच जाना चाहिए। ताजा उदाहरण बंगाल चुनाव है, जिसमें जनता ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सत्ता से बाहर कर दिया।

● राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लेने के बाद भी टीएमसी ने इस चुनाव में 'जय बांग्ला' का नारा दिया। डीएमके ने हिंदी बनाम तमिल भाषा को मुद्दा बनाया। क्षेत्रीयता का मुद्दा उठाकर भी दोनों दल क्यों हार गए?

– टीएमसी हो या डीएमके दोनों ही राजनीतिक दलो के नेतृत्व ने पिछले चुनाव तक अपनी-अपनी भूमिकाएं ठीक से निभाई थी, इसलिए दोनों अभी तक सत्ता में बने हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेकेंड या थर्ड लीडरशिप विकसित नहीं की। टीएमसी वाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी। सत्ता में आने के बाद धीरे-धीरे वाम के खिलाफ उनका आक्रोश कम होने लगा। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि 15 साल से राज्य में उनका ही शासन था और अब उनकी जवाबदेही तय हो रही थी। उन्होंने चुनाव के दौरान जनता के सामने कोई नया मुद्दा भी नहीं रखा। इससे उलट भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर लोगों को 'परिवर्तन' के लिए प्रेरित कर दिया। यही तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ हुआ। इससे स्पष्ट है कि मतदाता को एक समय के बाद नए मुद्दे की जरूरत है। ताकि लगे कि राजनीतिक दल उनके हित में बदलाव करना चाहते हैं।

● नेतृत्व या बदलाव के लिए 15 साल का आंकड़ा क्यों ? इसके पीछे क्या तर्क है।

– भारत में आजादी के पहले भी क्षेत्रीय दल मौजूद थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित थी। स्वतंत्रता आंदोलन की अगुआई कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के बाद राष्ट्रीय दल बन गई। 1960 के दौर में कांग्रेस के विकल्प के रूप में डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल उभरकर सामने आए। 1989-91 के दौर में भारतीय राजनीति में 'गठबंधन युग' की शुरुआत हुई। इस दौर में क्षेत्रीय दल इतने सशक्त बनकर उभरे कि वह केंद्र में सरकार निर्माण से लेकर नीतियां बनाने तक में भूमिका निभाने लगे थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल उसी दौर में प्रधानमंत्री बने। भाजपा में गठबंधन का आइडिया पहली बार प्रमोद महाजन लेकर आए थे और कांग्रेस को हटाया था। 2004 में इसी क्षेत्रीय दल की मदद से कांग्रेस ने भाजपा को हराया था और अब भाजपा ने इन्हीं क्षेत्रीय दलों के गठबंधन के सहारे कांग्रेस को कई राज्यों में सत्ता से बाहर किया। यह शक्ति संतुलन है। उधर, नेतृत्व व नए मुद्दों के अभाव में जब क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उस समय टीवीके का सत्ता तक पहुंचना एक ओर टर्निंग प्वाइंट है। यदि इस अंतराल का आकलन किया जाए तो आप पाएंगे कि हर 15-20 साल में दलों का स्वरूप बदल रहा है।

● भाजपा पर आरोप है कि वह पहले क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करती है और फिर उसे कमजोर कर सत्ता हासिल कर लेती है? क्या यह क्षेत्रीय दलों के लिए झटका नहीं?

– सीधे तौर पर तो यह साबित नहीं किया जा सकता है कि भाजपा क्षेत्रीय दल को खत्म कर रही है। यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है। जब क्षेत्रीय दलों को खतरा महसूस होगा तो वह खुद ही सचेत होंगे। तमाम आरोपों के बावजूद एक बात जरूर है कि भाजपा ने कभी भी अपने संकल्पों को छिपाया नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन के दौरान वह घोषणा करती रही है कि भाजपा राज्य में स्वतंत्र सरकार बनाना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस मुक्त भारत भाजपा का सार्वजनिक एजेंडा है। इसकी घोषणा भी वह लगातार करते रहते हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं।

● और कांग्रेस को क्या करना चाहिए?

–क्षेत्रीय दलों का सराहा लेना होगा।

● क्या टीवीके क्षेत्रीय दलों के लिए कोई नया उदाहरण पेश कर पाएगा? खास तौर पर जब आप से उम्मीदें टूट चुकी हैं?

– मेरे हिसाब से टीवीके की तुलना आप से करना ठीक नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार की सीमा काफी सीमित होती है। टीवीके की तुलना चंद्रबाबू नायडू के पहले कार्यकाल से करना चाहिए। जैसे तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) 'पापुलिज्म' (जनता जो सुनना चाहती है, वही बोलना, उसे वही सपने दिखना) की थ्योरी के जरिये सत्ता में आई थी, वैसे ही टीवीके आई है। पांच साल के काम के आधार पर ही उसका आकलन संभव है।

● चंद्रबाबू नायडू हाईटेक सीएम माने जाते थे। कंप्यूटर, स्टार्टअप आदि पर काफी निवेश किया था। फिर क्यों हार गए थे?

– जनता को सपने देखना अच्छा लगता है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उसकी पहली जरूरत हैं। चंद्रबाबू नायडू यहीं चूके थे। उन्होंने राज्य को हाईटेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों की मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया था। इस बार भी उनके एजेंडे में हाईटेक डेवलपमेंट है, लेकिन इस पर वह ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं।

● किसी देश में क्षेत्रीय दलों की अवधारणा हो, जिस पर हमें गौर करना चाहिए?

– अमेरिका में दो राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके अधीन रहने वाली स्टेट पार्टियां क्षेत्रीय दलों की तरह ही काम करती हैं।

मजदूर के घर चमका 'पूनम' का चांद

श्रम को सम्मान

पिता को दिन-रात मजदूरी करते देख धनबाद की पूनम कुमारी ने बचपन से ही मन में गांठ बांध ली थी कि मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। पिता यदि खेत-खलिहान या सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं तो उसे भी किताबों से दो-दो हाथ करना है। मेहनत रंग लाई और सीबीएसई की परीक्षा में 97.4 प्रतिशत अंक लाकर धनबाद जिले में टाप किया। जानिए, गुदड़ी के इस लाल के बारे में:

आशीष सिंह ● जागरण

पिता धर्मु गोराई और मां टीपू देवी के साथ पूनम कुमारी ● जागरण

धनबाद : संभवतः यह धनबाद समेत राज्य का पहला ऐसा मामला है, जिसमें सीबीएसई से गुदड़ी का लाल निकला है। सीबीएसई बोर्ड से संचालित सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस एसएसएलएनटी प्लस टू स्कूल की छात्रा पूनम कुमारी ने विज्ञान संकाय में 97.4 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। वह विज्ञान संकाय में जिला टापर बनी हैं।

यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भूदा बस्ती की रहने वाली पूनम कुमारी के पिता धर्मु गोराई मजदूरी करते हैं। मां टीपू देवी गृहिणी हैं। निम्न मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली पूनम को कई बार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि निजी स्कूल (अपर्णा पब्लिक स्कूल गोसाईंडीह) से दसवीं पास करने के बाद उन्होने सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में दाखिला लिया। सीबीएसई बोर्ड में यह अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है, जहां गुदड़ी का लाल निकला है।

पूनम ने अंग्रेजी में 95, भौतिकी में 96, रसायन 98, बायोलाजी 98 और आइसी में 100 नंबर प्राप्त किया है। पूनम ने बताया नौ लोगों का संयुक्त परिवार है। दो बड़े भाई प्राइवेट जाब करते हैं। पढ़ाई के प्रति ललक देखते हुए परिवार ने पूनम का बहुत सहयोग दिया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने भी पूनम को बहुत सहयोग दिया। पूनम कहती हैं बेहतर अंक हासिल करने का कोई फार्मूला उन्हें नहीं पता है। उन्हें बस एक ही चीज आती है कि पाठ्य-पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं, उसे पहले शब्द से लेकर आखिरी तक स्मृतियों में बिठा लेना। इसके साथ ही अनवरत अभ्यास जरूरी है। हर पाठ को कई-कई बार रिवाइज किया। जवाब लिखने के तरीकों पर शिक्षकों से मार्गदर्शन लिया। प्वाइंट टू प्वाइंट और तथ्यात्मक जवाब लिखने पर खास जोर रहा। वह कहती हैं संभवतः इन सभी चीजों की वजह से ही मुझे बेहतर अंक मिले होंगे।

पहले ही प्रयास में नीट पास करने की थी उम्मीद...

पढ़ाई के अलावा ड्राइंग करना पसंद है। हाल ही में नीट की परीक्षा दी थी, जो निरस्त हो गई है, तो दोबारा देंगी। जनरल श्रेणी में 620 में से 610 अंक आने की संभावना थी। पहले ही अटेम्प्ट में एमबीबीएस मिल सकता था। अपने जूनियर को मैसेज देती हैं कि प्रैक्टिस और रिवाइज, यह दोनों चीज हर छात्र को करना चाहिए। सफलता का श्रेय अपने स्वजन, स्कूल के शिक्षकों और प्राचार्या अंजना महतो को देती हैं।

सेल्फ स्टडी, यू-ट्यूब और चैट जीपीटी से ली सहायता

इस सफलता के पीछे उनका बनाया हुआ गोल चार्ट कारगर साबित रहा। हर दिन किस विषय को कितना समय देना है यह पहले से ही निर्धारित कर रखा था। पढ़ाई को घंटे में नहीं बांधा और हर विषय को समान रूप से समय दिया। सोने और जागने का समय निर्धारित था। सुबह साढ़े तीन बजे उठ जाया करती थी। हर हाल में रात 10 बजे सो जाती थी। सुबह की पढ़ाई सबसे बेहतर होती है, इसलिए पढ़ने का यही समय हुआ करता था। कभी कोई कोचिंग नहीं की। सेल्फ स्टडी, यू-ट्यूब और चैट जीपीटी से मदद लेकर सभी शंकाओं का समाधान किया। किसी भी इंटरनेट मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। वाट्स-एप और यू-ट्यूब का प्रयोग भी सिर्फ पढ़ाई के लिए किया। पूनम का मानना है कि यह छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान डालता है। इसका सही इस्तेमाल आपको सफलता दिला सकता है, बस यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से प्रयोग करते हैं।

समुद्र में मौजूद सेंसर मशीनें अब नहीं 'मरेंगी'

ताकि सुनामी जैसी आपदाओं की सूचनाएं मिलती रहे

उपलब्धि

केरल के कन्नूर के रहने वाले विज्ञानी डा. विपिन बलराम को तीन करोड़ रुपये की यूरोपीय संघ की मैरी क्यूरी रिसर्च फैलोशिप जीती है। यह फैलोशिप उन्हें समुद्र में सुनामी की सूचना देने वाली मशीनों में कभी न खत्म होने वाली बैटरी पर शोध के लिए दिया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित सम्मान असाधारण प्रतिभा के लिए दिया जाता है। जानिए इनके बारे में:

नेशनल डेस्क ● जागरण

नई दिल्ली: समुद्रों की सतह के नीचे ऐसा अंधकार है, जहां कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची। यहां लाखों छोटी मशीनें चौकसी कर रही हैं और सुनामी से पहले आने वाले झटकों को ट्रैक कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के संकेत देने वाले तापमान में बदलाव को माप रही हैं और उन चेतावनी प्रणालियों को निरंतर डाटा प्रदान कर रही हैं। एक तरह से यह करोड़ों तटीय जीवन की रक्षा करती हैं। यह मशीनें जब बंद हो जाती हैं, तो क्या असर डालती हैं? उसे ठीक करने का क्या कोई विकल्प है? इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कन्नूर के मेकेनिकल इंजीनियर डा. विपिन बलराम। वह इन मशीनों में उपयोग होने वाली बैटरियों को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि ताकि वह कभी बंद ही न हो।

कोयंबटूर के अमृता इंजीनियरिंग कालेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डा. बलराम बताते हैं समुद्र में मौजूद मशीनें धीरे-धीरे खत्म हो रही हैं। न तो दबाव से और न ही जंग लगने से बल्कि बैटरी खत्म होने से ये मशीनें दम तोड़ रही हैं। इन सेंसर को बदलने के लिए एक शोध पोत, एक विशेष दल, हफ्तों की लाजिस्टिकल योजना और विशाल खर्च की आवश्यकता होती है। इससे बचने के लिए ही शोध की जरूरत है। यही नहीं, एक मशीन बंद होने से महासागरों के नीचे फैले अदृश्य सुरक्षा जाल में एक अंतर पैदा करता है। यह हमारे समय की सबसे अहम इंजीनियरिंग संकटों में से एक है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है।

महासागर स्वयं ही ऊर्जा देगा : डा. विपिन के अनुसार समुद्र की गहराई में एक सेंसर को अनिश्चितकाल के लिए कैसे चालू रख सकते हैं...वह भी बिना किसी ऊर्जा स्रोत, बिना किसी रखरखाव दल और बिना किसी चार्जिंग प्वाइंट के। यही वजह है कि यह शोध जितनी उम्मीद जगाता है, धरातल पर उसको उतारना उतनी ही चुनौती भरा है। व्यवहारिक प्रयोग कठिन है।

लहरों से बनती है बिजली

जब एक सेंसर बुई महासागर की लहरों की प्राकृतिक लय के साथ उछलती और लुढ़कती है, तो इसके अंदर लटका पेंडुलम झूलता है। इस पेंडुलम के जरिये एक जनरेटर को चलाता है। वह जनरेटर लगातार, स्वच्छ, और बिना किसी मानव हस्तक्षेप के बिजली उत्पन्न करता है। डा. विपिन ने इसे ही अपने शोध का आधार बनाया है। समुद्र के भीतर खुद ब खुद चार्ज होने वाली बैटरी का संकल्प लिया है।

कन्नूर से ग्लासगो की यात्रा

डा. बिपिन ने कन्नूर में बड़े होकर त्रिशूर के सरकारी इंजीनियरिंग कालेज में अध्ययन किया, जहां उन्होंने कालेज यूनियन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कालीकट से पीएचडी की और इसके बाद अमृता विश्वविद्यालय में फैकल्टी सदस्य के रूप में शामिल हुए। अब ग्लासगो में शोध करेंगे।

अंधेरे से लड़ते थके नहीं कदम...छू लिया 'गगन'

उड़ान

मथुरा के दृष्टिबाधित गगन सिंह राघव ने तमाम बाधाओं को पार कर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 95.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं में भी उन्हें 91.2 प्रतिशत अंक मिले थे। ब्रेललिपि में पढ़ने-लिखने की सुविधा नहीं मिली तो शिक्षकों ने जो पढ़ाया उसकी रिकार्डिंग कर वाइस नोट बना लिया:

वेद प्रकाश गौतम ● जागरण

मथुरा: मां-बाप ने उनका नाम गगन रखा था। मगर, उन्हें गगन का मतलब नहीं पता था। उसकी ऊंचाई, रंग की कोई समझ नहीं। उनके हिस्से में आया था अंधेरा। किसान मां-बाप की संतान गगन जन्म से ही आंखों से दिव्यांग हैं। मगर, उन्होंने अपने हौसले से ऊंची उड़ान भरी है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 95.4 प्रतिशत अंक लाकर सबको चौंका दिया। गगन होने के मायने साबित किए। अभी उन्हें और ऊंची उड़ान की चाहत है।

संघर्ष की ये कहानी है, मथुरा के भद्रवन निवासी गगन सिंह राघव की। तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े गगन को जन्म से ही दिखाई नहीं देता। पिता हाकिम सिंह किसान और मां रानी देवी गृहिणी हैं। पांचवीं तक गगन भाई और बहन के साथ स्कूल जाते और सुनकर पढ़ाई करते। उसमें सुनकर याद रखने की अद्भुत क्षमता है। गगन को उसके भाई और बहन के साथ वृंदावन स्थित परमेश्वरी देवी धानुका स्कूल में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन यहां ब्रेललिपि से पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीनों भाई-बहन वृंदावन में किराए का कमरा लेकर रहते। कक्षा में शिक्षक जो भी पढ़ाते, गगन उसे याद रखते और घर आकर अपने मोबाइल पर उसके वाइस नोट्स बना लेते। मोबाइल पर टाक बैक एप्लीकेशन की मदद से वह इससे रिवीजन करते। भाई और बहन उसी की कक्षा में होने से उनसे किताबें पढ़कर सुनते। इस तरह, गगन ने अपनी मेहनत से हाईस्कूल में 91.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 12वीं में उन्होंने एक और प्रतिष्ठित स्कूल श्रीजी बाबा सरस्वती स्कूल में प्रवेश लिया। मगर, ब्रेललिपि से पढ़ने या पढ़ाने की व्यवस्था यहां भी नहीं थी। गगन ने यहां भी मोबाइल पर वाइस नोट्स से पढ़ाई की। सीबीएससी की 12वीं के परीक्षा परिणाम में उसे 95.4 प्रतिशत अंक मिले हैं। गगन का हौसला इतना है कि उसे यह नंबर भी कम लग रहे हैं। प्री-बोर्ड में 98 प्रतिशत तक अंक आए थे।

पढ़ाई के लिए विदेश से आया बुलावा, लेकिन आर्थिक तंगी ने रोका रास्ता

गगन ने बताया कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने विश्व में नौवीं रैंक प्राप्त यूके की यूनिवर्सिटी कालेज आफ लंदन में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। वहां से बीएससी बिजनेस एंड हेल्थ में प्रवेश के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ है, लेकिन वहां की पढ़ाई का खर्चा 55 हजार पाउंड प्रतिवर्ष है। इसके लिए उन्हें बड़ी आर्थिक मदद की आवश्यकता है।

वाइस रिकार्डिंग के जरिये की पढ़ाई

गगन ने बताया कि उन्हें परीक्षा में अलग रूम में बैठाया गया। लिखने के लिए 11वीं कक्षा का एक राइटर दिया गया। उन्होंने बोल-बोलकर लिखवाया और सफलता पाई। ब्रेललिपि में अधिकांश किताबें उपलब्ध न होने पर उन्हें पढ़ाई में काफी परेशानी हुई। टीचर जो बोलकर पढ़ाते थे, उसे वह वाइस रिकार्डिंग कर पढ़ते थे। इसके साथ ही यू-ट्यूब से नोट्स से भी मदद मिली। प्रतिदिन स्कूल के अलावा छह घंटे और छुट्टी वाले दिनों में 12 घंटे पढ़ाई करते थे।

दुनिया का पहला सिंक्रोनस मौसम उपग्रह किया गया लांच

1974 में आज ही नासा ने दुनिया का पहला सिंक्रोनस (स्थिर) मौसम उपग्रह एसएमएस-1 लांच किया था। इससे विज्ञानियों को दिन-रात लगातार बादलों की तस्वीरें और मौसम का रियल-टाइम डाटा उपलब्ध कराया, जिससे गंभीर मौसमी घटनाओं की सटीक ट्रैकिंग संभव हो सकी।

लंदन में पेश की गई दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर

1861 में आज ही के दिन लंदन में स्काटिश गणितज्ञ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल व फोटोग्राफर थामस सटन ने मिलकर दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर टार्टन रिबन पेश की थी। इस तस्वीर को लाल, हरे और नीले फिल्टर की मदद से तीन अलग-अलग फोटो जोड़कर तैयार किया गया था।

दिल को छू लेने वाली गजलों के लिए जाने जाते हैं पंकज उधास

पंकज उधास का जन्म 1951 में आज ही वर्तमान गुजरात के राजकोट में हुआ था। 1972 में फिल्म 'कामना' से बतौर गायक सिनेमा जगत में पदार्पण हुआ। फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन पंकज उधास की सुरीली आवाज को काफी सराहा गया। 1980 में अपना पहला गजल एल्बम आहट रिलीज किया। 1986 में फिल्म नाम के गाने 'चिट्ठी आई है' ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। करियर में मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल और नायाब सहित कई सुपरहिट गजल एल्बम निकाले। आहिस्ता कीजिए बातें, जिए तो जिएं कैसे बिन आपके, ना कजरे की धार सहित कई कालजयी गाने व गजल गाए।

साइलेंट किलर बन रही पल्मोनरी एम्बोलिज्म

रहें सतर्क ▶ प्रतीक यादव की मौत के बाद चर्चा में बीमारी, हार्ट अटैक के बराबर है इसकी घातकता

सप्लीमेंट के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण युवाओं में बढ़ रहा है खून के थक्के का खतरा

जागरण संवाददाता, लखनऊ

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव की असामयिक मृत्यु के बाद 'मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म' नामक बीमारी चर्चा में आ गई है। चिकित्सा विशेषज्ञ इसे 'साइलेंट किलर' मानते हैं। अगर आपका दिल तेजी से धड़कने लगे या घबराहट महसूस हो, तो यह शरीर में आक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है। जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का एक बड़ा संकेत है। यह बीमारी तब होती है, जब शरीर के किसी हिस्से (अक्सर पैरों) में बना खून का थक्का फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में जाकर फंस जाता है। इससे हृदय और फेफड़ों का संपर्क कट जाता है और आक्सीजन न मिलने के कारण व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है।

प्रतीक यादव अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहते थे। उनको बीते अप्रैल माह में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पहला गंभीर अटैक आया था। उस समय एक अस्पताल में उपचार के 24 घंटे बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बीमारी में दवाओं का नियमित सेवन और डाक्टर की निगरानी अनिवार्य है। डाक्टर की सलाह पर उन्होंने जिम और एक्सरसाइज भी बंद कर दी थी, जिससे जोखिम कई गुना बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने एंटीकोआगुलेंट (खून पतला करने वाली) दवाएं लेना भी बंद कर दिया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ।

प्रतीकात्मक

इसका रखें ध्यान

- यदि पैर के किसी एक हिस्से में सूजन, दर्द या लाली दिखे, तो नजरअंदाज न करें।
- लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने वाले लोग हर एक घंटे में जरूर टहलें।
- पर्याप्त पानी पीना और वजन नियंत्रित रखना इस जानलेवा थक्के को रोकने के सबसे सरल उपाय है।

ये है मुख्य लक्षण

पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षणों में अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द और बेहोशी शामिल है, ऐसी स्थिति में बिना देर किए विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, ताकि मरीज की जान बचाई जा सके।

क्या है यह बीमारी

लखनऊ स्थित डा. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रो. अजय वर्मा के अनुसार, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई बहुत प्रचलित बीमारी नहीं है। इसकी घातकता हार्ट अटैक के बराबर है। इसमें मृत्युदर 50 प्रतिशत से अधिक है। जब पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का बनता है, तो इसे 'डीप वेन थ्रोम्बोसिस' (डीवीटी) कहते हैं। यदि यह थक्का टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाए तो रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है और शरीर को आक्सीजन नहीं मिल पाती। इससे अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेल्योर हो सकता है। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, धूमपान, सर्जरी और लंबे समय तक शारीरिक निष्क्रियता इसके मुख्य कारण हैं।

प्रो. अजय वर्मा, विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, लोहिया संस्थान। सौ. स्वयं

चेतावनी : बिना डाक्टरी सलाह के प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट लेना खतरनाक हो सकता है। इससे न केवल किडनी पर दबाव बढ़ता है, बल्कि खून के थक्के जमने और हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ता है। बाजार में मौजूद कई सप्लीमेंट में भारी धातुएं और स्टेरायड पाए जाते हैं, जो शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बिगाड़ देते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि सप्लीमेंट की बजाय दाल, दूध, चने, राजमा, सोयाबीन और अंडे जैसे प्राकृतिक प्रोटीन स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फिल्म रिव्यू

कर्तव्य ✪✪◖

प्रमुख कलाकार: सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, मनीष चौधरी, जाकिर हुसैन

लेखक और निर्देशक: पुलकित **अवधि**: एक घंटा 48 मिनट

रिलीज प्लेटफार्म: नेटफ्लिक्स

कलाकारों ने निभाया कर्तव्य

कोई फिल्म प्रभावशाली तभी बन पाती है, जब उसके पात्रों को समुचित तरीके से विकसित किया गया हो। खासतौर पर नायक और खलनायक के टकराव को। लेखक और निर्देशक पुलकित इसी सबसे अहम पहलू पर अपना कर्तव्य निभाने में चूक जाते हैं।

पुलकित ने झामली नामक छोटे से कस्बे को कहानी का आधार बनाया है, जिसकी भाषा और माहौल से समझ आता है कि यह हरियाणा का होगा। कहानी का केंद्र आनर किलिंग (प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या) और अन्य सामाजिक विसंगतियां हैं। झामली के ईमानदार एसएचओ पवन (सैफ अली खान) और उसके भरोसेमंद मातहत अशोक (संजय मिश्रा) की सुरक्षा में एक चर्चित महिला पत्रकार की हत्या हो जाती है, जो आध्यात्मिक गुरु आनंद श्री (सौरभ द्विवेदी) से जुड़े नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले की छानबीन के लिए आई होती है। उधर, पवन का छोटा भाई दूसरे संप्रदाय की लड़की के साथ फरार हो जाता है। कट्टर जातिवादी उसका पिता हरिहर (जाकिर हुसैन) इस घटना को अपमान की तरह देखता है। फिर पता चलता है कि पत्रकार का हत्यारा नाबालिग हरपाल (युधवीर अहलावत) है, जिसने आनंद श्री के आदेश पर यह कत्ल किया है। आनंद श्री के करीबियों में पवन का अफसर केशव (मनीष चौधरी) भी शामिल होता है। एक तरफ पवन का कर्तव्य व इंसानियत है, दूसरी तरफ परिवार, समाज और व्यवस्था का जहरीला सोच।

आनर किलिंग, धर्म और सत्ता के गठजोड़ जैसे गंभीर विषयों को आधार बनाकर बनाई गई यह फिल्म आरंभ में प्रभावशाली क्राइम-ड्रामा बनने का भरोसा जगाती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पटकथा की कमजोरियां सामने आने लगती हैं। ढोंगी बाबा आनंद श्री का चित्रण सतही है। उसकी ताकत और कमजोरी को चंद संवादों में निपटा दिया गया है। हरपाल को भगाने का प्रसंग भी कमजोर है। हालांकि, आनर किलिंग को लेकर खाप पंचायत वाले दृश्य कुछ पकड़ बनाते हैं, लेकिन उसके असर को गहराई नहीं दे पाते। सैफ अली खान पूरी फिल्म में छाए रहते हैं। नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच झूलते पवन की हताशा, बेबसी और आक्रोश को संतुलित ढंग से दर्शाया हैं। संजय मिश्रा और रसिका दुग्गल रंग जमाते हैं। मनीष चौधरी अपने पात्र को विश्वसनीय बनाते हैं। सैफ के साथ उनके टकराव वाले दृश्य अच्छे हैं। सौरभ द्विवेदी पात्र के अनुरूप नहीं लगते। युधवीर अहलावत का अभिनय उल्लेखनीय है। फिल्म अपने संदेश को प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतार नहीं पाती।

स्मिता श्रीवास्तव

पूरी फिल्म में छाए रहते हैं सैफ अली खान चित्र सौ. : फिल्म टीम

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं: feature@jagran.com

युवाओं में बढ़ते स्क्रीन टाइम व आनलाइन ज्यादा समय बिताने से हाई बीपी के मामलों में वृद्धि

अनूप कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली : मोबाइल फोन, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म और डिजिटल स्क्रीन पर लगातार बढ़ता समय युवाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार देर रात तक आनलाइन सक्रिय रहना, कम नींद, तनाव और निष्क्रिय जीवनशैली युवाओं में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मामलों को तेजी से बढ़ा रही है।

विश्व हाइपरटेंशन डे पर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं ने समय रहते अपनी जीवनशैली नहीं बदली तो आने वाले वर्षों में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार इस समय भारत में 18 करोड़ से अधिक लोग हाइपरटेंशन से प्रभावित हैं। इसमें शहरी युवाओं में स्थिति अधिक गंभीर है। पाया गया है कि 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 15 से 20 प्रतिशत युवा प्री-हाइपरटेंशन या हाई बीपी से ग्रसित हैं। दिल्ली में लगभग हर तीन में से एक वयस्क यानी करीब एक करोड़ लोगों का बीपी अधिक पाया गया।

विश्व हाइपरटेंशन डे

प्रतीकात्मक

इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलाजिस्ट डा. पुष्पेंद्र नाथ रंजन के अनुसार देर रात तक फोन इस्तेमाल करने से स्लीप साइकल बिगड़ती है, बढ़ता स्क्रीन टाइम अब केवल आंखों की थकान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित कर रहा है। शारदा केयर के डा. अखिल कुमार रुस्तगी का कहना है कि डिजिटल लाइफस्टाइल में बढ़ता स्क्रीन टाइम और कम नींद युवाओं के ब्लड प्रेशर पर सीधा असर डाल रहे हैं। लगातार तनाव और नींद की कमी हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ाती है। पीसीआरआइ अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डा. रवि प्रकाश ने बताया कि देर रात तक स्क्रीन के संपर्क में रहने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होता है, जो अच्छी नींद के लिए जरूरी है। इसके प्रभावित होने से नींद की कमी हो जाती है। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हृदय और रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। शारीरिक गतिविधि की कमी व डिजिटल डिवाइस की लत हाई बीपी के मामलों को गंभीर बना रही है।

प्लेटलेट्स सामान्य होने के बाद भी खतरनाक हो सकता है डेंगू का बुखार

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : डेंगू को लेकर लोगों के मन में बड़ी गलतफहमी यह है कि यह बीमारी केवल तभी खतरनाक होती है जब मरीज के प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं।

मेदांता नोएडा के इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट कंसल्टेंट डा. सौरदीप चौधरी के अनुसार, लोग अक्सर सिर्फ प्लेटलेट्स की संख्या पर ध्यान देते हैं और उन अन्य लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बीमारी के गंभीर होने का संकेत देते हैं। सच्चाई यह है कि प्लेटलेट्स सामान्य होने पर भी डेंगू खतरनाक रूप ले सकता है। डेंगू वायरस हर मरीज पर अलग-अलग तरह से असर डालता है। कई मरीजों में प्लेटलेट्स का स्तर ठीक होने के बावजूद प्लाज्मा लीकेज, शरीर से खून बहने, लिवर से जुड़ी समस्याओं, सांस लेने में तकलीफ जैसी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, केवल रिपोर्ट में प्लेटलेट्स के नंबर देखने के बजाय मरीज की पूरी शारीरिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है।

इधर उधर की

...जब नशे में धुत हिरण लगा गोल गोल घूमने

पुलिस ने की लोगों से की सावधानी बरतने की अपील • इंटरनेट मीडिया

पेरिस, एजेंसी: फ्रांस के ग्रामीण इलाके साओन-एट-लोइरे में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब वहां के हिरण बेतरतीब तरीके ये उछल-कूद करने लगे। ऐसे ही गोल-गोल घूमते और लड़खड़ाते एक हिरण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। शुरू में लोगों को लगा कि ये हिरण किसी बीमारी के शिकार हो गया है, लेकिन जब असली कारण सामने आया, तो सभी हंस पड़े। पुलिस के अनुसार, हिरण ने किण्वित फल खा लिए थे। मौसम में धूप और गर्मी के कारण गिरे हुए फल व पौधे प्राकृतिक रूप से सड़कर अल्कोहल बना लेते हैं। क्षेत्र के हिरण इसी के आदी हो गए हैं।

बाडी फैट में बदलाव से गंभीर हो सकता है अल्जाइमर रोग

अनुसंधान

अल्जाइमर रोग को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है, जिसमें पाया गया है कि मोटापा के कारण बाडी फैट में बदलाव के चलते भूलने की यह बीमारी गंभीर हो सकती है। अध्ययन के अनुसार, मोटापा से संबंधित बाडी फैट में बदलाव मस्तिष्क को हानिकारक संकेत भेज सकते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम का कार्य बाधित होता है और अल्जाइमर रोग की स्थिति बिगड़ सकती है।

अध्ययन के नतीजों को मोलेक्यूलर न्यूरोडीजेनेरेशन जर्नल में प्रकाशित गया है। इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधी इस बीमारी के बारे में नई जानकारी मिलती है। अध्ययन के नतीजों से अल्जाइमर रोग के लिए नया उपचार विकसित करने का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। उम्र संबंधी इस बीमारी के कारण स्मृति और बोलने की क्षमता प्रभावित होने के साथ ही दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अमेरिका के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट अस्पताल के शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन में मोटापे को सामान्य स्वास्थ्य जोखिम के रूप में देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर देखा गया है। मेटाबोलिक स्थिति के कारण सूजन और रक्त वाहिकाओं को क्षति हो सकती है, जिससे अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि मोटापा बाडी टिश्यू में फास्फेटिडाइलएथेनोलामाइन (पीई) के स्तर को बढ़ा देता है, जो एक प्रकार का फैट मोलेक्यूल होता है और मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मस्तिष्क में पीई न्यूरान के बीच संचार को बाधित करता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और एमलाइड प्रोटीन के जमा होने में मदद करता है। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता स्टीफन वोंग ने कहा, "मोटापा मस्तिष्क तक पहुंचने वाले संकेतों में बदलाव कर सकता है। अच्छी बात यह है कि हम इसका उपचार कर सकते हैं।" प्रेट्र

सियोल में लोटस लैंटर्न फेस्टिवल

दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में शनिवार को भगवान बुद्ध के आगामी जन्मदिन से पहले आयोजित लोटस लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान विशाल लालटेन के साथ लालटेन परेड में हिस्सा लेते बौद्ध लोग। यह 1200 साल पुराना यूनेस्को मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें हजारों की संख्या में लोग हाथों में पारंपरिक कमल के आकार की लालटेन लिए शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकालते हैं। इस दौरान जोग्ये मंदिर और सियोल की प्रमुख जगहों पर पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला प्रदर्शन होते हैं। एपी

स्क्रीन शाट

'रीमेक नहीं, ओरिजिनल है, है जवानी तो इश्क होना है की कहानी'

पहली बार साथ होगी वरुण व मृणाल की जोड़ी। @varundvn

फिल्मकार डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है एक तरफ चुनरी चुनरी गाने के रीक्रिएशन को लेकर विवादों में है। बता दें कि चुनरी चुनरी.. गाना फिल्म बीवी नंबर 1 का है, जिस पर फिल्म के निर्माता वासु भगनानी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट के अधिकार का दावा किया है।

वासु भगनानी और फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी के बीच अधिकारों को लेकर विवाद चल ही रहा था कि वहीं अब इस फिल्म को गोविंदा अभिनीत फिल्म सैंडविच की रीमेक भी बताया जाने लगा। दरअसल, हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी होते ही कुछ लोगों ने इसे सैंडविच की रीमेक बता दिया। जिसके बाद फिल्म के निर्माताओं को शनिवार को इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। निर्माताओं ने जारी बयान में कहा, 'हमें पता चला है कि हमारी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को लेकर इंडस्ट्री और जनता के बीच काफी चर्चा हो रही है। टिप्स (फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी), रमेश तौरानी जी, डेविड धवन जी, कास्ट और क्रू के साथ, यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले ओरिजिनल है तथा इसका किसी दूसरी फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है। हमने इस फिल्म को अपने पूरे दिल से बनाया है और पांच जून को सिनेमाघरों में दर्शकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिससे उन्हें परिवार के साथ एक मनोरंजक अनुभव दे सकें।'

हंसी न उड़े, इसलिए सलमान खान ने पूरा किया था फिल्म का स्टंट

शूटिंग देखने के लिए कई बार आम लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। ऐसे में कलाकार भी इस बात को लेकर सतर्क हो जाते हैं कि उनकी छवि न खराब हो। ऐसा ही कुछ अभिनेता सलमान खान को भी लगा था, जब उन्हें ऊंचाई से छलांग मारनी थी। एक किस्सा सुनाते हुए सलमान कहते हैं कि हम जागृति (1992) फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 80 फुट का पहाड़ था, जब मैंने नीचे से देखा, तो मुझे लगा की मैं तो आसानी से कूद जाऊंगा। पहले एक या दो बाक्स लगाए जाते थे, जिस पर कूदना होता था, लेकिन यहां पर ऊंचाई ज्यादा थी, तो तीन परतों का बाक्स और उस पर एक गद्दा लगाया गया था। मैं ऊपर चढ़ा और जब वहां से देखा, तो बाक्स नहीं दिख रहा था, मुझे केवल अंदाजा लगाकर कूदना था। मैं शायद नहीं कूदता, लेकिन तब तक भीड़ जमा हो गई थी। ऊपर जाकर फिर नीचे आकर कहना कि मैं नही करूंगा, ऐसा करने में स्वाभिमान आड़े आ रहा था, जो नुकसानदेह होता है। मुझे लगा कि अब तो करना होगा। मुझे पता था कि बाक्सेस नीचे ही कहीं हैं। मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट राजू का हाथ पकड़ा और थोड़ा झुककर देखा, तो वह बाक्सेस माचिस के डिब्बे की तरह दिख रहे थे। मैं दूर से भागकर आकर कूदा, लेकिन फिसल गया, मेरे बाल उस दौरान पहाड़ पर काफी घिसे थे। आगे सलमान स्क्रिप्ट के चुनाव को लेकर अपने तरीकों की बात पर कहते हैं कि मैंने आज तक एक भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। मैं स्क्रिप्ट्स सुनता हूं।

मातृभूमि फिल्म में फिर एक्शन करते दिखेंगे सलमान। फाइल

जान अब्राहम को अगले जेम्स बांड के तौर पर देखते हैं शेखर

साल 1962 में फिल्म डाक्टर नो से शुरु हुई जासूसी दुनिया पर आधारित जेम्स बांड हालीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी की अब तक 25 फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं। जिनमें छह अलग-अलग अभिनेता जासूस नायक जेम्स बांड की भूमिका निभा चुके हैं। इस बीच फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्देशक शेखर कपूर अगले जेम्स बांड के तौर पर अभिनेता जान अब्राहम को देखते हैं। शेखर ने इस बारे में शनिवार को एक्स पर लिखा, 'जैसे कि अगले जेम्स बांड की खोज जोरों से चल रही है। डेनियल क्रेग (हालीवुड अभिनेता) के बाद अगले जेम्स बांड के लिए मेरा वोट जान अब्राहम को जाएगा। उनके पास कूल, शेकेन नाट स्टर्ड व्यक्तित्व और बांड आकर्षण के साथ अच्छी एक्टिंग है। वैसे भी निर्माताओं ने डेनियल क्रेग को जेम्स बांड के तौर पर मेरी फिल्म एलिजाबेथ में देखने के बाद कास्ट किया था।' बता दें कि शेकेन नाट स्टर्ड जेम्स बांड की फिल्मों से प्रसिद्ध हुआ वाक्यांश है, जो उसके शांत, मजबूत और तनाव मुक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है। शेखर से प्रशंसा सुनकर जान भी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहें। उन्होंने जवाब में लिखा, 'धन्यवाद सर। यह बात ऐसे इंसान ने कही है, जिन्होंने न सिर्फ कहानी कहने का तरीका बदल दिया, बल्कि बांड के रूप में दुनिया को दिखने से पहले ही डेनियल क्रेग को पहचानना... यह बातें मेरे लिए मायने रखती है। जहां तक बांड की बात है... मैं खुशी-खुशी मार्टिनी आर्डर (जेम्स बांड का पसंदीदा ड्रिंक) की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। शेकेन नाट स्टर्ड।'

इन दिनों अभिनय के साथ लगातार फिल्म निर्माण भी कर रहे हैं जान। फाइल

शैतान 2 के लेखन पर चल रहा काम, रेड 3 भी कतार में

गोलमाल से लेकर सिंघम और फिर दृश्यम तक, फ्रेंचाइजी फिल्मों के मामले में अभिनेता अजय देवगन की फिल्में काफी सफल रही हैं। ऐसे में वह आगे भी कई फिल्मों की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कड़ी में अब शैतान और रेड भी शामिल हो चुकी है। साल 2024 में प्रदर्शित शैतान की सीक्वल शैतान 2 के लेखन का काम चल रहा है, तो निर्माता रेड फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रेड 3 भी लाने पर विचार कर रहे हैं। इन फिल्मों की पुष्टि स्वयं निर्माता अभिषेक पाठक ने की। शैतान 2 को लेकर अभिषेक ने बताया, 'अभी इसके लेखन पर काम चल रहा है। मैं सिर्फ नाम के लिए कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनाना चाहता। मैं कोई भी हारर फिल्म बनाकर उसे शैतान 2 का नाम नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि कहानी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े, जैसे दृश्यम 10 सालों में आगे बढ़ी। एक बार स्क्रीनप्ले पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद, फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।'

आगे रेड 3 के लेकर अभिषेक ने कहा कि हम कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं। जब तक हमारे पास अमय पटनायक (फिल्म में अजय देवगन के पात्र का नाम) के अगले सफर के लिए कागजों पर कुछ बहुत बढ़िया नहीं आ जाता, तब तक हम इंतजार करना चाहते हैं। अभी इसके कंटेंट और कहानी पर चर्चा हो रही है।

कई फिल्मों की फ्रेंचाइजी आगे बढ़ा रहे हैं अजय। फाइल